


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2016/माघ 30, 1937

No. 56]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2016/MAGHA 30, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2016

अंतिम जांच परिणाम

विषय : यूरोपीय संघ (ईयू), मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नार्मल ब्यूटानोल या 'एन-ब्यूटाइल अल्कोहल' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच

फा. सं. 14/4/2013-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. उक्त नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) को दि आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि. (एपीएल) (जिसे एतदपश्चात 'याचिकाकर्ता' कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यूरोपीय संघ (ईयू), मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) (जिन्हें आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नार्मल

ब्यूटानोल या 'एन-ब्यूटाइल अल्कोहल' (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' या 'एनबीए' कहा गया है) के पाटन का और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।

ख. आवेदन की प्रारंभिक जांच से कतिपय कमियों का पता चला है, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा बाद में सुधार दिया गया है। याचिकाकर्ता ने अद्यतन याचिका दायर की जिस पर प्राधिकारी द्वारा जाँच की शुरुआत के लिए विचार किया गया। अतः आवेदन को विधिवत रूप से दस्तावेज सहित माना गया था।

ग. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध जाँच शुरू करने का निर्णय लिया।

घ. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को जांच की शुरुआत करने के पहले आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ङ. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने के संबंध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

च. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके व्योरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें उनके विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर दिया।

छ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर उनके विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने की सलाह दी।

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली 6(3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराई थी। जहां कहीं भी अनुरोध किया गया आवेदन की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षों को भी उपलब्ध कराई गई।

झ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं:

ससोल मिडिल ईस्ट एफजेडसीओ 1 स्टर्डि एवेन्यु रोसबैंक पोस्ट बाक्स नं. 5486 जोहानेसबर्ग दक्षिण अफ्रीका	आक्सेनो-डेगुसा हल्स ग्रुप डेगुसा हल्स ग्रुप आक्सेनो ओलिफिनकेमी जीएमबीएच डी 45764 मारिपाल बाउमान स्ट्रेवे 1, जर्मनी
डो यूरोप जीएमबीएच दि डो कैमिकल कं. टैक्सास सिटी, टेक्सास, यूएसए	औक्सी जीएमबीएच 1505, वेस्ट एलबीजे फ्रीवे सूइट 400आर डल्लास टीएक्स यूएस 75234
ईआइएफ एटोकैम एस.ए. 4, कुर्समिकेलैट 92091 पैरिस ला डिफेंस सेडेक्स, फ्रांस	सोलवेंट्स डाक्यूमेंटेशन सिनथेसिस एस.ए. बी.पी. 4, 13124 पेपिन

जेडएके जाकलेली एजोटावे कियोजिरान एस.एसकेआर. पोइजोटा 163 47220 केडजिजिन कोजले पोलेंड	ईस्टमैन कैमिकल टेक्सास सिटी आपरेशन्स पो. बा. नं. 471 टेक्सास सिटी, टीएक्स 77592 यूएसए
आईसीसी कैमिकल कार्पोरेशन 460, पार्क एवेन्यु न्यूयार्क – 10022, यूएसए	पर्सट्राप ओक्सो एबी स्टेननग्संड सेनडेन 44495, कोडस्माल, स्वीडन
ईस्टमैन कैमिकल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय 9 नार्थ बुओना विस्टा ड्राइव #05-01 दि मेट्रोपोलिस टावर 1 सिंगापुर 138588	ईस्टमैन कैमिकल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, विनिर्माण साइट 50 साकरा एवेन्यु जुरोंग आइलैंड सिंगापुर
अरकेमा मुख्यालय 420 रू एस्टीने डी'ओरव्स 92705 कोलंबस, सेडेक्स, फ्रांस	

ज. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया:

- पेट्रोनास कैमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया या 'पीसीडी'
- पेट्रोनास कैमिकल्स मार्केटिंग एसडीएन बीएचडी, मलेशिया या 'पीसीएम'
- पीसीएम कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि.
- बीएएसएफ पेट्रोनास कैमिकल्स एसडीएन बीएचडी मलेशिया या 'बीएएसएफ'
- आक्सिया जीएमबीएच, ईयू
- पेट्रोकैम मिडिल ईस्ट एफजेडई, दुबई
- आईसीसी कैमिकल कार्पोरेशन, यूएसए
- आक्सिया कार्पोरेशन, यूएसए

ट. मै. आक्सिया कार्पोरेशन, यूएसए जिसके अनुरोध बाद में बताए गए हैं, को छोड़कर उक्त सभी उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

ठ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को प्रश्नावली भेजी गई थी:

केएलजे ग्रुप आफ कं. मुख्यालय: केएलजे हाउस, 63, रामा मार्ग, नजफगढ़ रोड नई दिल्ली - 110 015	पीसीएल ग्रुप 703, सातवां तल, डीएलएफ टावर-बी डिस्ट्रिक्ट सेंटर जसोला, नई दिल्ली- 110044
एपीआई इंडस्ट. कार्पोरेशन	रचना प्लास्टिसाइजर्स

एनके पालीमर्स एंड एडिटिव्स मैनु.कं. 36/2 रिंगनवाडा, सोमनाथ इंड. इस्टेट के पास दमन- 396201 (केन्द्र शासित प्रदेश)	प्लाट नं. : 116-117, पिपरिया इंड.इस्टेट दादर और नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश सिलवासा वापी- गुजरात
विसेन इंडस्ट्रीज लि. 102/ए, विरवानी इंडस्ट्रीयल इस्टेट गोरेगांव (ई) मुम्बई - 4000 063	माइक्रो इंकस लि. प्लाट नं. : 2801/3ए और 3, 2082/बी, 2083/2, 2084 &2085-25, सर्वे नं.: 285/1, जीआईडीसी थर्ड फेस, वापी, वलसाड, गुजरात
अल्काइल एमाइन्स कैमिकल्स लि. प्लाट नं. 67, एमआईडीसी पाताल गंगा इंड. एरिया गांव: कायरे, ताल: खलापुर जिला – रायगढ़	ललिता कैमि. इंड. प्रा. लि. यूनिट नं. 2, प्लाट नं. 32बी नांजी इंड. एरिया, सर्वे नं.: 200/1/2 गांव:खराडी, पुणे
दीपक नाइट्राइट लि. एंटरप्राइज सेंटर, 301, III तल होटल आर्चिड के पास, विलेपार्ले (इ) मुम्बई- 4000099	पायल पालीप्लास्ट प्रा. लि. ई-24, नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज नई दिल्ली- 110002
डार्फ केटल स्पेशिएल्टी प्रा. लि. इंटेक. पालिमर – डिवीजन 1 डार्फ केटल टावर, डी मोंटे लेन, ओरलम मलाड (वे), मुम्बई—400 064	अणुशक्ति कैमिकल्स एंड ड्रग्स लि. 71, उद्योग क्षेत्र, दूसरा तल मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड, मुलुंड (वे), मुम्बई- 400080
सी जे शाह एंड कंपनी 105, बजाज भवन, 10वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021	रमणीकलाल एस. गोसालिया एंड कं. नेशनल हाउस, 608, बी. जे. मार्ग, जैकब सर्किल, मुम्बई - 400011
हरेश पेट्रोकेम प्रा. लि. 404/405, एकमे प्लाजा, अंधेरी कुर्ला रोड, संगम थियेटर के सामने, अंधेरी (ई), मुम्बई-400059	हैजल मर्केन्टाइल लि. 3/10, कपाडिया चैम्बर्स 599, जे.एस.एस., मरीन लाइन्स मुम्बई - 4000 02
कुन्दन राइस मिल्स लि. डी-16, सिटी चैम्बर्स, प्रशांत विहार, दिल्ली - 110085	हैजल मर्केन्टाइल लि. 3/10, कपाडिया चैम्बर्स 599, जे.एस.एस., मरीन लाइन्स मुम्बई - 4000 02
एशियन सोल्वेकैम प्रा. लि. विंडसर, दूसरा तल, सीएसटी रोड,	केएलजे रिसोर्सेज लि. 76, जूहू शॉपिंग सेंटर, दूसरा तल

कलीना, सांताक्रुज (ई) मुम्बई - 400098	गुलमोहर क्रास, नौवां रोड, जूहू स्कीम मुम्बई - 400049
पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट (इंडिया) प्रा. लि. 201, बिजनेस स्क्वायर, बी-विंग, अंधेरी कुर्ला रोड, एप्पल-हेरिटेज के सामने, अंधेरी (ई), मुंबई-400093	पोन प्योर कैम (पी) लि. सं. 32, एच-ब्लाक, 15वां मेन रोड अन्ना नगर, चेन्नई- 600 040
योग इंटरनेशनल प्रा. लि. खसरा नं. 36/8 मुंडका गांव दिल्ली- 110041	डागा ग्लोबल कैमिकल्स लि. 302, साकार-III, पुरानेउच्च न्यायालय के सामने नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
अपरा एंटरप्राइजेज प्लॉट सं. 176, दूसरा तल डा. केनी हाउस साइन (वेस्ट), मुम्बई- 400022	ओवरसीज पालीमर प्रा. लि. विनमार हाउस, ए-41 एमआईडीसी रोड नं.2 अंधेरी (ई), मुम्बई-400093
केतुल कैम प्रा. लि. वेस्टर्न एज-1, कनाकिआ स्पेसेस यूनिट नं. 403, मेट्रो शापिंग माल, बोरिवली (ई), मुम्बई- 400 066	बालमुकन्द कैमिकल्स प्रा. लि. प्लॉट नं. 4765, जीआईडीसी इस्टेट फिकाम चार रास्ता के पास, अंकलेश्वर - 393002
पारस डार्ज एंड कैमिकल्स बी-82, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024	जागृति प्लास्टिक्स लि. 107, एम.जी. हाउस, समुदाय केन्द्र वजीरपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110052
सुरभि एंटरप्राइजेज प्रा. लि. मुख्यालय 4/1 कैमेक स्ट्रीट, भूमि तल कोलकाता - 700 016	संजल कैमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि. पांचवा तल, केनमूर हाउस 281/287 नर्शि नाथ स्ट्रीट मस्जिद, मुम्बई—400 009 (महाराष्ट्र)
सुप्रीम इंडिया इंटरनेशनल सी-11, जीवन ज्योत 18/20, कवसजी पटेल स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई- 400 000	बूनीशा कैम प्रा. लि. 203/204, शिव चैम्बर्स, प्लॉट सं. 21, ए-विंग सैक्टर-11, एमटीएनएल बिल्डिंग से आगे, सीबीडी बेलापुर(ई), नवी मुम्बई
अंकिता कैमिकल कार्पोरेशन नं. 7, सरवण भवन, नई गाम क्रास रोड दादर ईस्ट	केतुल कैम प्रा. लि. 403, वेस्टर्न एज, मेट्रो स्टोर,

मुम्बई - 400 014	बोरिवली (ई), मुम्बई - 400092
नूतन कैमिकल्स जे-37, एम.आई.डी.सी., भोसारी पुणे- 411026, महाराष्ट्र, भारत	त्रिवेणी एरोमैटिक्स एंड परफ्यूमरी प्रा. लि. 136, पंचरत्न चार रास्ता, जी.आई.डी.सी., वापी - 386195, गुजरात
ए.बी. एंटरप्राइजेज 202, श्रद्धानंद बिल्डिंग 272/ 274, सैमुअल स्ट्रीट, मुम्बई - 400 003	प्लास्टिकैम इंड. कार्पोरेशन ए-2001, रनवाल प्राइड 20वाँ तल, एल.बी.एस. रोड, मुलुंड वेस्ट मुम्बई- 400 080
तुलसी कैमिकल्स 3, ओल्ड नं. 2, राजा अन्नामलाई रोड पहला तल, पुरसवाकम चेन्नई- 600 084	देव कैमिकल्स 1-89, अध्यापक नगर नांगलोई दिल्ली- 110 041
इंडियन प्लास्टिसाइजर्स मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन केएलजे हाउस, 63 रामा मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली- 110015	

ड. निम्नलिखित आयातकों/उपभोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- पीसीएम कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि.
- पायल पेट्रोकेम प्रा. लि.
- रचना प्लास्टिसाइजर्स,
- केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लि.
- केएलजे रिसोर्सेज लि.
- पायल पालीप्लास्ट प्रा. लि.

इसके अलावा अनेक अन्य हितबद्ध पक्षों ने वर्तमान जांच के संबंध में टिप्पणियां और अनुरोध प्रस्तुत किए हैं जिन पर उचित ढंग से विचार किया गया है। उक्त हितबद्ध पक्ष निम्नानुसार हैं:

- इवोनिक इंडस्ट्रीज
- लुब्रिजोल इंडिया प्रा. लि.
- बारकुर सर्फेक्टेंट्स प्रा. लि., मुम्बई
- युनिटोप कैमिकल्स प्रा. लि., मुम्बई
- एडवांस्ड माइक्रोडिवासेज प्रा. लि.
- श्री कृष्णा फार्मास्युटिकल लि.

ढ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को सभी हितबद्ध पक्षों के निरीक्षण के लिए एक सार्वजनिक फाइल के रूप में खुला रखा। सार्वजनिक फाइल का अनेक हितबद्ध पक्षों ने अनेक बार निरीक्षण किया। ऐसे हितबद्ध पक्ष जिन्होंने सार्वजनिक फाइल के निरीक्षण और दस्तावेजों की प्रतियों के लिए अनुरोध किया उन्हें वह उपलब्ध कराए गए।

ण. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने

के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।

त. आवश्यक समझी गई सीमा तक याचिकाकर्ता और अन्य हितबद्ध पक्षों से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया था।

द. प्राधिकारी के अनुरोध पर, केन्द्र सरकार ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अनुसार जाँच को पूरा करने के समय को 19 फरवरी, 2016 तक बढ़ा दिया।

ध. निम्नलिखित निर्यातकों के परिसर में मौके पर सत्यापन भी किया गया था:

- पेट्रोनास कैमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया या 'पीसीडी' (8 दिसम्बर, 2015)
- पेट्रोनास कैमिकल्स मार्केटिंग एसडीएन बीएचडी, मलेशिया या 'पीसीएम' (9 दिसम्बर, 2015)
- बीएसएसएफ पेट्रोनास कैमिकल्स एसडीएन बीएचडी मलेशिया (7 दिसम्बर, 2015)
- आक्सिया जीएमबीएच, ईयू (2-3 नवम्बर, 2015)

न. उक्त निर्यातकों को की गई जाँच की रिपोर्ट जारी की गई। निर्यातकों द्वारा की गई टिप्पणी पर इन जाँच परिणामों में आगे विचार किया गया।

प. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत पर विचार करते हुए क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' कहा गया है) को ज्ञात किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

फ. यह जाँच 1 अप्रैल, 2013 से 30 जून, 2014 तक (15 महीनों) में की गई (जिसे आगे जाँच अवधि या 'पीओआई' कहा गया है)। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जाँच में 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012- 2013 की अवधि तथा जाँच की अवधि शामिल है।

ब. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 6 नवम्बर, 2015 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने अनुरोध और उनके बाद खंडनों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।

भ. अमरीकी डालर को रुपये में बदलने के लिए विनिमय दर जाँच अवधि के लिए सीमाशुल्क आकड़ों के अनुसार 60.77 रुपये मानी गई है।

म. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी ने 8 फरवरी, 2016 को मामले के अनिवार्य तथ्यों का ज्ञात हितबद्ध पक्षों को प्रकटन किया था और उसके संबंध में हितबद्ध पक्षों से टिप्पणियाँ भी प्राप्त हुईं और प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक इस जाँच परिणाम में उन पर विचार किया गया है।

य. इस अंतिम जाँच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

2. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद 'नार्मल ब्यूटानोल' या 'एन-ब्यूटाइल अल्कोहल' है।

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के इन कथनों की जाँच करनी चाहिए कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुएं और विचाराधीन उत्पाद समान हैं और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

घरेलू उद्योग के विचार

4. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(क) वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद एन-ब्युटानोल है जिसे एन-ब्युटाइल अल्कोहल या नार्मल ब्युटानोल के रूप में भी जाना जाता है। नार्मल ब्युटानोल 4-कार्बन संरचना और अणु सूत्र सी4एच9ओएच वाला एक प्राथमिक अल्कोहल है। यह स्पष्ट, चल, निष्क्रिय द्रव है जिसमें विशेष गंध होती है। यह सभी सामान्य विलायकों में विलेय है परंतु जल में कम घुलनशील है। एनबीए चीनी और कार्बोहाइड्रेट के खमीरीकरण के लघु उत्पाद के रूप में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है और अनेक खाद्य और पेयों में मौजूद होता है।

(ख) नार्मल ब्युटानोल यूरिया, मेलामाइन या फेनोलिक रेजिंस से उत्पन्न एसिड-क्यूरेबल लेकर्स और बेकिंग फिनिशेस के लिए एक उत्कृष्ट विलायक है। एन-ब्युटानोल के एक बड़े हिस्से को कोटिंग उद्योगों में विलायक के रूप में प्रयोग हेतु व्युत्पत्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

5. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद 'नार्मल ब्युटानोल' है। नार्मल ब्युटानोल एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसे आम तौर पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नार्मल ब्युटानोल 4-कार्बन संरचना और अणु सूत्र सी4एच9ओएच वाला एक प्राथमिक अल्कोहल है।

6. नार्मल ब्युटानोल यूरिया, मेलामाइन या फेनोलिक रेजिंस से उत्पन्न एसिड-क्यूरेबल लेकर्स और बेकिंग फिनिशेस के लिए एक उत्कृष्ट विलायक है। एन-ब्युटानोल के एक बड़े हिस्से को कोटिंग उद्योगों और छपाई की स्याही में विलायक के रूप में प्रयोग हेतु व्युत्पत्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। नार्मल ब्युटानोल को औषधों और प्राकृतिक पदार्थों के उत्पादन में एक्स्ट्रेक्ट्स, पालिशों और क्लीनर्स में एडिटिव की तरह, वस्त्र उद्योग में सोल्युबिलाजर, डाइसिंग तरलों में एडिटिव, गैसोलाइन में एंटी-आइसिंग, सेल्युलोज नाइट्रेट के लिए ह्यूमेक्टेंट, ग्लाइकोल इथर्स और फ्लोटेशन ऐड्स (ब्युटाइल सेंथेट) के उत्पादन में फीडस्टाक और ब्युटाइल मानो कार्बोजिलेट्स, ब्युटाइल एसिटेट, ब्युटाइल ब्यूटीरेट के उत्पादन के लिए आरंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है।

7. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 29051300 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

8. 'समान वस्तु' की परिभाषा से संबंधित नियम 2(घ) में विनिर्दिष्ट है कि "समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तु के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती है।

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारत में संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तु समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और संबद्ध देशों से आयातित नार्मल ब्युटानोल भौतिक और रासायनिक लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का उपयोग, एक दूसरे के स्थान पर कर सकते और कर रहे हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। घरेलू और आयातित संबद्ध वस्तु की प्रतिस्थापनीयता बताने वाली तकनीकी विशेषताओं में अंतर की कोई विशेष बात सिद्ध नहीं की गई है जिसमें विस्तृत जांच की जरूरत हो। पैकेजिंग के रूप में मामले पर उचित स्थानों पर विचार किया गया है। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के रूप में ही माना जाता है।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता एनबीए, ईएचए और आईबीए का उत्पादन कर रहा है। 2011 से ईएचए और एनबीए को दो अलग-अलग संयंत्रों में उत्पादित किया जाता है।

11. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से भारत में आयातित किए जा रहे संबद्ध उत्पाद की समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

12. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

13. मै पीसीडी, पीसीएम और पीसीएम कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि. ने दलील दी है कि समान वस्तु के अनेक अन्य उत्पादक जैसे मै. गैलेक्सी कैमिकल्स, मै. हिमांशु कैमिकल्स और मेरू कैम प्रा. लि. हैं। आवेदन ने इन उत्पादकों का नाम भी नहीं बताया है।

14. याचिकाकर्ता को पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए ‘घरेलू उद्योग’ नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि याचिकाकर्ता कभी भी संबद्ध वस्तु का नियमित उत्पादक नहीं रहा है।

घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

(क) यह याचिका घरेलू उद्योग के रूप में दि आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है।

(ख) याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।

(ग) अन्य पक्षों की इस दलील के संबंध में, याचिकाकर्ता ने सूचना एकत्र की है और उसे प्राधिकारी को प्रस्तुत किया है जो यह दर्शाती है कि ये कंपनियां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रही हैं।

(घ) याचिकाकर्ता ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या किसी आयातक से (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) संबंधित है।

(ङ) याचिकाकर्ता नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग बनने का पात्र है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदन घरेलू उद्योग के रूप में दि आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। याचिकाकर्ता ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या किसी आयातक से (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) संबंधित नहीं है।

17. इस दलील के संबंध में कि मै. गैलेक्सी कैमिकल्स, मै. हिमांशु कैमिकल्स और मेरू कैम प्रा. लि. भी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा कोई साक्ष्य जो सिद्ध करता हो कि ये पक्ष विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल हैं, उपलब्ध नहीं कराया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण सूचना याचिकाकर्ता को इन पक्षों से एक लिखित पत्र को दर्शाती है जिसमें निम्नानुसार बताया गया है:

- i. मेरू कैम प्रा.लि. ने बताया कि वे रसायन और विलायक के केवल व्यापारी और आपूर्तिकर्ता हैं, वे एनबीए या किसी अन्य रसायन या विलायक का उत्पादन नहीं करते हैं।
- ii. हिमांशु कैमिकल ने बताया कि वे उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रहे हैं बल्कि उत्पाद का व्यापार कर रहे हैं।
- iii. गैलेक्सी कैमिकल ने बताया कि वे उत्पाद के प्रयोक्ता नहीं हैं और वे एनबीए और अन्य विलायकों का व्यापार कर रहे हैं।

18. यह भी नोट किया जाता है विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में भारी पूंजी निवेश की जरूरत होती है और इसलिए याचिकाकर्ता को देश में किसी अन्य उत्पादक की मौजूदगी के बारे में निश्चित रूप से जानकारी नहीं होगी। पक्षों के तर्क से पता चलता है कि वे विचाराधीन उत्पाद के व्यापारी हैं और घरेलू उत्पादक नहीं हैं।

19. रिकार्ड में दी गई सूचना के मद्देनज़र, विधिक प्रावधानों की आवश्यक जाँच और उन पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं अर्थात् नियमों के अंतर्गत योग्यता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। अतः याचिकाकर्ता को नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है।

घ. पाटन मार्जिन

20. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

घरेलू उद्योग के विचार

21. सामान्य मूल्य के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

(क) निर्यातक देशों में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निम्नलिखित आधार हो सकते हैं:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमत,
- (ii) निर्यातक देश या क्षेत्र या उचित तीसरे देश से निर्यात के समय समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत
- (iii) मूलता के देश में प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों और लाभों के लिए तर्कसंगत राशि जोड़कर उक्त वस्तु की उत्पाद लागत।

(ख) प्रत्येक संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की कीमत सूची या उद्धरण लेने के प्रयास भी किए गये। तथापि, याचिकाकर्ता किसी भी संबद्ध देश के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमत की विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

(ग) याचिकाकर्ता ने परिकलित मूल्य की नीति का प्रयोग करके सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा किया है। याचिकाकर्ता ने मध्वर्ती वस्तुओं – सिनगैस और बुट्रालडेहाइड और अंतिम उत्पाद – नार्मल बुटानोल की लागत का परिकलन करने के लिए संबद्ध देशों में प्रचलित विद्युत की कीमतों को अपनाया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कच्ची सामग्री और सुविधा के लिए उनके खपत कारकों का दावा किया है।

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

22. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- सामान्य मूल्य की गणना की याचिकाकर्ता की नीति त्रुटिपूर्ण है और संदेहास्पद संसाधनों पर आधारित है और इसलिए उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- याचिकाकर्ता ने बड़ी हुई लागत पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है और उसने परिकलित सामान्य मूल्य पर गोपनीयता का गलत दावा किया है। इस संबंध में, **बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2004 (167) ई.एल.टी. 163 (त्रि.-दि.)** का उल्लेख किया गया है।
- प्राधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा यथानिर्धारित मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए और प्रतिवादी-निर्यातक के आकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए।
- मलेशिया से संबद्ध वस्तु का कोई पाटन नहीं हुआ है क्योंकि प्रतिवादी की कीमतें आईसीआईएस कीमतों पर आधारित बेंचमार्क कीमतें हैं। वास्तव में आयात कीमतों में क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

प्राधिकारी द्वारा जॉच

23. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी और उन्हें विहित ढंग और तरीके से सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया। निम्नलिखित पक्षों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- पेट्रोनास कैमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया या 'पीसीडी'
- पेट्रोनास कैमिकल्स मार्केटिंग एसडीएन बीएचडी, मलेशिया या 'पीसीएम'
- पीसीएम कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि.
- बीएसएसएफ पेट्रोनास कैमिकल्स एसडीएन बीएचडी मलेशिया या 'बीएसएसएफ'
- आक्सिया जीएमबीएच, ईयू
- पेट्राकैम मिडिल ईस्ट एफजेडई, दुबई
- आईसीसी कैमिकल कार्पोरेशन, यूएसए
- आक्सिया कार्पोरेशन, यूएसए (पीओआई के दौरान केवल कोई निर्यात नहीं करने की सूचना दी)

I. मलेशिया

मै. पेट्रोनास कैमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया या 'पीसीडी'

24. संबद्ध वस्तु के उत्पादक मै. पीसीडी ने उत्पादक के रूप में प्रश्नावली का उत्तर दिया है। उसके संबंधित निर्यातक अर्थात् मै. पीसीएम और संबंधित आयात अर्थात् मै. पीसीएम कैमिकल्स इंडिया प्रा.लि. ने भी प्रश्नावली का उत्तर दिया है। उनके अनुरोध निम्नानुसार हैं:

(क) पीसीडी पेट्रोनास कैमिकल्स ग्रुप बरहार्ड (पीसीजीबी) की पूर्ण-स्वामित्व सहायक कंपनी है। पीसीजीबी पेट्रोलियम नेसिनलबरहार्ड (पेट्रोनास) द्वारा 64.4 प्रतिशत स्वामित्व है और 35.6 प्रतिशत जनता और अन्य निवेशकों के स्वामित्व में है।

(ख) उत्पाद के विनिर्माण के लिए मुख्य कच्ची सामग्री प्रापीलीन और सिनर्गस/ओक्सोगैस है।

ग) पीसीडी दोनों कच्ची सामग्रियों को अपनी संबंधित कंपनी से बाजार कीमतों पर खरीदता है।

(घ) प्रक्रिया के दौरान उत्पादित उप-उत्पाद बुटानोल ऑफ गैस है। बुटानोल ऑफ गैस की बिक्री से प्राप्त राशि को संबंधित उत्पाद की उत्पादन लागत निर्धारित करते समय ऋण के रूप में लिया जाता है।

(ङ) सामान्य मूल्य का दावा घरेलू बाजार में बिक्रियों के आधार पर किया गया है।

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. पीसीडी द्वारा संबद्ध वस्तु की पीओआई में की गई घरेलू बिक्री ***एमटी है। प्राधिकारी उत्पादक और उसके संबद्ध निर्यातक अर्थात् मै. पीसीएम द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर का सत्यापन किया है। मै. पीसीडी की घरेलू बिक्रियों के व्यापार की सामान्य प्रक्रिया (80:20) संबंधी परीक्षण से यह पता चला है कि *** प्रतिशत अर्थात् *** एमटी लगभग घरेलू बिक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में हैं। पीओआई में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य इसलिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सौदो के संबंध में और मध्यवर्ती प्रभागों (*** डा./मी.टन), अंतरदेशीय परिवहन (*** डा./मी.टन), ऋण लागत (*** डा./मी.टन), पैकिंग (*** डा./मी.टन), संबंधी समायोजन करते हुए निर्धारित किया गया है। भारित औसत सामान्य मूल्य ***

डा./मी.टन के रूप में माना गया है। मै. पीसीडी की घरेलू बिक्रियों को मै. पीसीएम जो मै. पीसीडी की संबंधित कंपनी है, के जरिए किया गया है। इसके अलावा प्राधिकारी ने सत्यापन किया है कि मै. पीसीएम ने मै. पीसीडी से खरीदी गई वस्तु को आगे चिन्ह के साथ घरेलू बाजार में असंबद्ध प्रयोक्ताओं को बेचा गया है इस प्रकार, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में निकट बिक्रियां सिद्ध हुई हैं।

मै. पेट्रोनास कैमिकल्स मार्केटिंग एसडीएन बीएचडी, मलेशिया या 'पीसीएम'

26. निर्यातक ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अनुरोध किया है:

(क) पीसीडी पेट्रोनास कैमिकल्स ग्रुप बरहार्ड (पीसीजीबी) की पूर्ण-स्वामित्व सहायक कंपनी है।

(ख) भारत को बिक्रियां पेट्रोनास कैमिकल डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी (पीसीजीबी की पूर्णतः स्वामित्व में) से खरीद द्वारा की गई हैं।

(ग) आपवादिक मामलों में, भारत को बिक्री बीएसएफ पेट्रोनास कैमिकल्स एसडीएन बीएचडी (बीएसएफ और पीसीजीबी के बीच संयुक्त उद्यम) से की गई खरीद से भी की गई हैं।

(घ) पीसीएम कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि. भारत में संबंधित आयात और व्यापारी है।

(ङ) पीसीएम कैमिकल्स इंडिया और अन्य असंबंधित उपभोक्ताओं को भारत को बिक्रियां की गई हैं।

(च) सामान्य मूल्य का दावा घरेलू बाजार में बिक्री के आधार पर किया गया है।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. पीसीएम ने उपभोक्ता पहचान को सुकर बनाने के लिए पीसीएम कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि. के साथ भारत को पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु को बेचा है। प्राधिकारी ने मै. पीसीडी से मै. पीसीएम की बिक्री कीमत के साथ मै. पीसीडी द्वारा उत्पादित वस्तु की मै. पीसीएम की निर्यात कीमत को भी सहसंबंधित किया है। भारित औसत सीआईएफ कीमत को *** डा./एमटी के रूप में निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने समुद्री भाड़ा, ऋण लागत और प्रहस्तन के लिए क्रमशः *** डा./एमटी, *** डा./एमटी और *** डा./एमटी जिसका कुल योग *** डा./एमटी बनता है, की सीमा तक समायोजन की अनुमति दी है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** डा./एमटी के रूप में निर्धारित की गई है। इस प्रकार पाटन मार्जिन *** डा./एमटी (10-15 प्रतिशत) के रूप में निर्धारित किया गया है।

28. आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य को आगे मै. पीसीडी द्वारा उत्पादित और मै. पीसीएम द्वारा भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु की सत्यापित भारित औसत सीआईएफ कीमतों में 1 प्रतिशत पहुंच प्रभार और लागू सीमाशुल्क अर्थात् मूल सीमाशुल्क और उपकर को जोड़कर किया गया है।

मै. पीसीएम कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि.

29. संबद्ध वस्तु के उक्त असंबंधित आयातक ने मूल्य श्रृंखला को पूरा करते हुए प्रश्नावली का उत्तर दिया है और निम्नानुसार बताया है:

(क) पीसीएम कैमिकल इंडिया पीओआई में संबद्ध वस्तु के एक आयातक और व्यापारी के रूप में कार्य कर रहा था। तथापि, पीसीएम कैमिकल्स इंडिया अब एक निष्क्रिय कंपनी है।

(ख) पीसीएम कैमिकल्स को पहले मिटकोलाबुआन (इंडिया) प्रा. लि. के रूप में जाना जाता था।

(ग) मिटको लाबुआन कं. लि. और पेट्रोनास कैमिकल्स मार्केटिंग एसडीएन बीएचडी पीसीएम कैमिकल्स इंडिया इंडिया के दो शेयरधारक हैं। मिटको लाबुआन कं. लि. इसके बाद पेट्रोलिअम नेसिनल बर्नाड ('पेट्रोनास') के पूर्ण स्वामित्व वाली है।

(घ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. पीसीएम द्वारा मै. पीसीएम कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि. को हाई सी बिक्री के रूप में किए गए दो सौदे आगे *** प्रतिशत के चिह्नांकन के साथ अंतिम प्रयोक्ता को बेचे गये थे।

बीएसएफ पेट्रोनास

30. सामान्य मूल्य: मै. बीएसएफ ने *** डा./मीटन की दर पर *** मीटन की मै. पीसीएम को घरेलू बिक्रियां की हैं। उन्हें मौके पर सत्यापन के रूप में भारित औसत कारखाना-द्वार उत्पादन लागत के साथ तुलना करते समय व्यापार की सामान्य प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रहस्तन, अन्य और ऋण लागत पर बिक्री कीमत संबंधी क्रमशः *** डा./एमटी, *** डा./एमटी और *** डा./एमटी जिसका कुल योग *** डा./एमटी बनता है, की सीमा तक

समायोजन की अनुमति दी है। मै. बीएसएफ के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य *** डा./एमटी के रूप में माना गया है।

31. निर्यात कीमत : मै. पीओआई में प्रत्यक्ष रूप से भारत को *** डा./मी.टन की भारित औसत सीआईएफ कीमत पर संबद्ध वस्तु के कुल *** मी. टन का कुल निर्यात किया। स्थल पर निर्यातक के सत्यापन के आधार पर प्राधिकारी ने कमीशन (*** डा./मी.टन), प्रहस्तन (*** डा./मी.टन), विदेशी भाड़ा (*** डा./मी.टन), विदेशी बीमा(*** डा./मी.टन), अन्य (*** डा./मी.टन) और ऋण लागत (*** डा./मी.टन) जिनका कुल योग *** डा./मी.टन है, के समायोजनों पर विचार किया है। इस प्रकार, कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** डा./एमटी के रूप में निर्धारित की गई है। इस प्रकार पाटन मार्जिन *** डा./एमटी (0-5 प्रतिशत) के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, पंधुच मूल्य को सीआईएफ के 1 प्रतिशत पंधुच प्रभारों और लागू सीमाशुल्क को जोड़कर निर्धारित किया गया है।

ख. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक:

32. मलेशिया में सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सहयोगी निर्यातकों के सर्वाधिक सामान्य मूल्य को उनके सामान्य मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत के लिए सहयोगी निर्यातकों की न्यूनतम निर्यात कीमत को सहयोगी निर्यातकों के मामले में अपनाये गए अनुसार समायोजनों के साथ स्वीकार किया गया है। इस प्रकार कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** डा./मी.टन की सीमा तक समायोजनों के साथ *** डा./मी.टन की सीआईएफ कीमत पर विचार किया गया है। तदनुसार, मलेशिया से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार निर्यात कीमत की क्रमशः *** डा./मी.टन और *** डा./मी.टन के रूप में गणना की गई है। इस प्रकार, पाटन मार्जिन को *** डा./मी.टन (15-20 प्रतिशत) के रूप में निर्धारित किया गया है।

33. मलेशिया से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पंधुच मूल्य न्यूनतम निर्यात कीमत (सीआईएफ), 1 प्रतिशत पंधुच प्रभारों और लागू सीमाशुल्क अर्थात् मूल सीमाशुल्क और उपकर सहित अपनाया गया है।

क्रम संख्या	उत्पादक	निर्यातक	एनवी (अम.डा./मी.टन)	कारखाना द्वार ईपी (अम.डा./मी.टन)	पाटन मार्जिन (अम.डा./मी.टन)	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा (%)
(1)	पीसीडी	पीसीएम	***	***	***	***	10-15
(2)	बीएसएफ पेट्रोनास	बीएसएफ पेट्रोनास	***	***	***	***	0-5
(3)	असहयोगी उत्पादक/निर्यातक और उपरोक्त 1) और 2) से भिन्न अन्य मिश्रण		***	***	***	***	15-20

II यूरोपीय संघ

क. सहयोगी उत्पादक/निर्यातक

ओक्सिया जीएमबीएच जर्मजी, ईयू

34. उक्त उत्पादक ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अनुरोध किया है:

(क) एन-बुटानोल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री एन-बुटीराल्डेहाइड और हाइड्रोजन है।

(ख) सामान्य मूल्य का दावा ईयू में उसकी बिक्री के आधार पर किया गया है।

(ग) अंतरदेशीय भाड़े, अंतरदेशीय बीमा प्रहस्तन, ऋण और ब्याज पर समायोजनों का दावा किया गया है।

(घ) जॉच अवधि में भारत को निर्यात मै. पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट, दुबई और मै. आईसीसी कैमिकल्स, यूएसए के जरिए किया गया है।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. ओक्सिया जीएमबीएच, जो ईयू में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, द्वारा पीओआई में संबद्ध वस्तु की की गई कुल घरेलू बिक्री ***एमटी है। पीओआई में सत्यापित कारखाना द्वार उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्रियों के व्यापार की सामान्य प्रक्रिया (80:20) संबंधी परीक्षण से यह पता चला है कि ओक्सिया जीएमबीएच की 99 प्रतिशत से अधिक घरेलू बिक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में हैं। इसलिए उत्पादक का संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सौदो के संबंध में और अंतरदेशीय भाड़े (*** डा./मी.टन), अंतरदेशीय बीमा (*** डा./मी.टन), प्रहस्तन (*** डा./मी.टन), ऋण और व्याज (*** डा./मी.टन), संबंधी समायोजन करते हुए भारित औसत घरेलू बिक्री कीमत के अनुसार परिकलित किया गया है [कुल *** डा./मी.टन]। इस प्रकार, भारित औसत सामान्य मूल्य *** डा./मी.टन के रूप में निर्धारित किया गया है।

36. इसके अलावा, उत्पादक ने मै. पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट, दुबई (***मी.टन) और मै. आईसीसी कैमिकल्स, यूएसए (***मी.टन) के जरिए पीओआई में भारत को कुल *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। भारत को निर्यातित मात्रा की भारित औसत निर्यात कीमत (सीआईएफ) ***डा./मी.टन के रूप में परिकलित की गई है। उक्त निर्यात पर प्राधिकारी ने अंतरदेशीय भाड़े (*** डा./मी.टन), बीमा (*** डा./मी.टन), प्रहस्तन (*** डा./मी.टन), अंतरदेशीय भाड़े (*** डा./मी.टन), अंतरदेशीय बीमा (*** डा./मी.टन), पोत परिवहन प्रभार (*** डा./मी.टन), और अन्य (*** डा./मी.टन) जिनका कुल योग *** डा./मी.टन है, संबंधी समायोजनों की अनुमति दी है। इस प्रकार, मै. ओक्सिया जीएमबीएच, उत्पादक के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत की गणना *** डा./मी.टन के रूप में की गई है। पाटन मार्जिन को *** डा./मी.टन (15-20 प्रतिशत) के रूप में निर्धारित किया गया है।

37. मै. पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट एफजेडई, दुबई, निर्यातक ने बताया है कि उनकी कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी है जो ईयू में आधारित उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध वस्तु को खरीदती है और भारत को उनकी पुनः बिक्री करती है। पीओआई में *** मी. टन संबद्ध वस्तु का उनके द्वारा भारत को निर्यात किया गया है। भारित औसत सीआईएफ को ***डा./मी.टन के रूप में निर्धारित किया गया है।

38. आईसीसी कैमिकल कार्पोरेशन, यूएसए निर्यातक ने बताया है कि उनकी कंपनी केवल संबद्ध वस्तु की निर्यातक है और उसने ***डा./मी.टन की भारित औसत सीआईएफ पर भारत को पीओआई में *** मी.टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

39. इसके अलावा मै. ओक्सिया जीएमबीएच के लिए पंधुच मूल्य को 1 प्रतिशत पंधुच प्रभारों और लागू सीमाशुल्क अर्थात् मूल सीमाशुल्क और उपकर सहित निर्धारित किया गया है।

ख. ईयू से असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

40. ईयू से सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए किसी समायोजन के बिना सहयोगी निर्यातकों की सर्वाधिक बिक्री कीमत पर विचार किया गया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत के लिए सहयोगी निर्यातकों की न्यूनतम निर्यात कीमत को सहयोगी निर्यातकों के मामले में अपनाये गए अनुसार समायोजनों के साथ स्वीकार किया गया है। इस प्रकार ईयू से शेष निर्यातकों/उत्पादकों के लिए *** डा./मी.टन की सीआईएफ कीमत पर विचार किया गया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार निर्यात कीमत की क्रमशः *** डा./मी.टन और *** डा./मी.टन के रूप में गणना की गई है। इस प्रकार, पाटन मार्जिन को *** डा./मी.टन (30-35 प्रतिशत) के रूप में निर्धारित किया गया है।

41. ईयू से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पंधुच मूल्य न्यूनतम निर्यात कीमत/सीआईएफ, 1 प्रतिशत पंधुच प्रभारों और लागू सीमाशुल्क अर्थात् मूल सीमाशुल्क और उपकर सहित अपनाया गया है।

पाटन मार्जिन

क्रम संख्या	उत्पादक	निर्यातक	एनवी (अम.डा./मी.टन)	कारखाना द्वार ईपी (अम.डा./मी.टन)	पाटन मार्जिन (अम.डा./मी.टन)	पाटन मार्जिन का %	पाटन मार्जिन की सीमा (%)
(1)	ओक्सिया जीएमबीएच	पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट	***	***	***	***	15-20
(2)	ओक्सिया जीएमबीएच	आईसीसी कैमिकल, यूएसए	***	***	***	***	15-20
(3)	असहयोगी उत्पादक/निर्यातक और उपरोक्त (1) और (2) से भिन्न अन्य मिश्रण		***	***	***	***	30-35

III. यूएसए, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से उत्पादक निर्यातक

ओक्सिया कार्पोरेशन, यूएसए

42. निर्यातक ने बताया है कि उनकी कंपनी ने पीओआई में भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है और इसलिए वर्तमान जाँच में भाग लेने या निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर देने का उनके पास कोई आधार नहीं है। यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो कंपनी न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

43. प्राधिकारी मै. ओक्सिया कार्पोरेशन, यूएसए के अनुरोधों को नोट करते हैं और मानते हैं कि न्यू शिपर समीक्षा के अनुरोध पर संगत एडीडी नियमावली के अनुसार उचित ढंग से कार्य किया जाएगा।

44. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यूएसए, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से उत्पादकों/निर्यातकों में से किसी ने भी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार, किसी उत्तर के अभाव में, प्राधिकारी ने इन तीन देशों से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना संबंधित नियम 6(8) के साथ पठित धारा 9क(1)ग के अनुसार उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर की गई है।

45. सामान्य मूल्य का परिकलन नाफ्था सहित प्रमुख कच्ची सामग्रियों और उनकी कीमतों, प्रचलित विद्युत कीमत और सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संगत अवधि के दौरान परिवर्तन लागत के लिए ज्ञात अनुमानों के लिए खपत मानकों को अपनाकर किया गया है। उत्पादन लागत में इस प्रकार निर्धारित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत और तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़ा गया है ताकि परिकलित सामान्य मूल्य ज्ञात किया जा सके। अनेक हितबद्ध पक्षों ने दलील दी है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत काफी अधिक है जिसका कारण वर्तमान पीओआई में कम उत्पादन होना है और उनके द्वारा कच्ची सामग्री का अधिक मूल्य देना है। यह स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकारी ने सर्वोत्तम खपत मानकों पर कच्ची सामग्री और सुविधा लागत को अपनाया है और जीओआई की परिवर्तन लागत को क्षतिअवधि के दौरान प्राप्त सर्वोच्च क्षमता उपयोग पर मानकीकृत किया गया है। सभी उक्त प्रत्येक संबद्ध देश के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य *** डा./मी.टन माना गया है।

46. इसके अलावा, प्राधिकारी अपनी संगत प्रक्रिया के अनुसार पीओआई के लिए सौदावार डीजीसीआईएंडएस आकड़ों के आधार पर उक्त तीन देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए यूएसए ***अम.डा. और सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका प्रत्येक के लिए ***अम.डा. के लिए में साक्ष्य के अनुसार तर्कसंगत समुद्री भाड़ा के लिए, समुद्री बीमा (सीआईएफ का *** प्रतिशत), कमीशन (एफओबी का *** प्रतिशत), बैंक प्रभार (एफओबी का *** प्रतिशत),

पत्तन व्यय (एफओबी का *** प्रतिशत), और संभलाई (एफओबी का *** प्रतिशत) तीनों में से प्रत्येक देश के लिए समायोजनों पर विचार करते हुए भारित औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। इस प्रकार यूएसए, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के लिए कारखाना-द्वार निर्यात कीमत क्रमशः *** डा./मी.टन, *** डा./मी.टन और *** डा./मी.टन संदर्भित की गई है।

47. इसके अलावा, डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आकड़ों को पीओआई सहित क्षति अवधि वर्ष के लिए विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के लिए छांटा गया है। ऊपर उल्लिखित तीन संबद्ध देशों अर्थात् यूएसए, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भारित औसत सीआईएफ के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पीओआई में लगभग 6 प्रतिशत की गैर पीयूसी प्रविष्टियों को अलग किया गया है।

48. पीओआई में संबद्ध वस्तु के पंधुच मूल्य को सीआईएफ पर 1 प्रतिशत पंधुच प्रभारों, मूल सीमाशुल्क और उपकर को जोड़कर डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

पाटन मार्जिन

देश	उत्पादक	निर्यातक	एनवी (अम.डा./ मी.टन)	ईपी (अम.डा./ मी.टन)	डीएम(अम.डा./ मी.टन)	डीएम%	डीएम रेंज
यूएसए	कोई	कोई	***	***	***	***	20-25
सिंगापुर	कोई	कोई	***	***	***	***	10-15
दक्षिण अफ्रीका	कोई	कोई	***	***	***	***	10-15

ड. क्षति

घरेलू उद्योग के अनुरोध

49. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है कि:

क. पूरी क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग सकारात्मक रही है।

ख. संबद्ध देशों से आयातों में इस अवधि के दौरान समग्र रूप से और भारत में विचाराधीन उत्पाद की खपत और उत्पादन के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से आयात भारत में आयातों का लगभग पूरा भाग बनाते हैं।

ग. भारित औसत आयात कीमत (मूल सीमाशुल्क को जोड़कर) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम रहा है, इस प्रकार भारी कीमत कटौती हुई है।

घ. क्षति मार्जिन काफी अधिक है।

ङ. आयातों की पंधुच कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम रहा है। आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी न्यूनकारी प्रभाव पड़ा रहा है। यद्यपि बिक्री लागत में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है, परंतु पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बिक्री कीमत को उस सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सका है जिससे भारी घाटा हुआ है।

च. घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि के उत्तर में वर्ष 2011-12 में क्षमताओं में वृद्धि की। घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2011-12 में सुधार हुआ और उसके बाद गिरावट आई। उत्पादन में गिरावट पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान काफी अधिक है।

छ. घरेलू उद्योग 2011-12 में अच्छा क्षमता उपयोग करने में सक्षम रहा था, परंतु 2012-13 के बाद और पीओआई में उसमें गिरावट आई है।

ज. पीओआई में उत्पादन में घाटा अन्य कारकों से भी हुआ है। पीओआई में उत्पादन कुछ समय के लिए अलाभकारी कीमतों के कारण और कच्ची सामग्री की आपूर्ति में कमी के कारण 5388 मी.टन तक घट गया। उस पर विचार करते हुए कि इस अवधि में उत्पादन में घाटा अन्य कारकों की वजह से हुआ, याचिकाकर्ता ने अपने निष्पादन को इस प्रकार से बताया है कि कच्ची सामग्री की कमी के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों द्वारा हुई क्षति को ज्ञात करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए आई कुल लागत से बर्बाद हुए समय की लागत को हटा दिया है। यह देखा जाएगा कि पीओआई में याचिकाकर्ता के सामान्य उत्पादन प्राप्त करने के बाद भी, बिक्री कीमत उत्पादन लागत से कम बनी हुई है। याचिकाकर्ता ने बेकार समय को समायोजित करने के बाद लाभप्रदता का भी दावा किया है।

झ. घरेलू बिक्रियों में भी यही प्रवृत्ति रही है। यद्यपि उत्पाद की मांग में 2010-11 और पीओआई के बीच 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तथापि बिक्री में 68 प्रतिशत की गिरावट आई और संबद्ध देशों से आयातों में उसी अवधि में 125 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि आयातों ने लगातार घरेलू उद्योग के बाजार पर कब्जा कर लिया है।

ञ. घरेलू उद्योग के लाभ में 2010-11 से क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। घरेलू उद्योग 2012-13 से नुकसान उठा रहा है, जो पीओआई में काफी बढ़ गया है। लाभप्रदता, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और कर और निवेश पर आय में भी यही प्रवृत्ति रही है।

ट. याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों से हुई क्षति का आकलन करने के लिए कुल लागत से व्यर्थ समय को निकाल दिया है। यह देखा जाएगा कि यद्यपि पीओआई में याचिकाकर्ता सामान्य उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम रहा था, तथापि लाभप्रदता में भारी गिरावट आ गई होती जो संबद्ध देशों से भारी पाटन के कारण हुआ है।

ठ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है जबकि पाटित आयातों के बाजार हिस्से में पूरी क्षति के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

ड. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान काफी आर्डरों को गंवाया है।

ढ. रोजगार के स्तर में 2012-13 में वृद्धि हुई है और उसके बाद गिरावट आई है। प्रदत्त मजदूरी ने 2011-12 तक वृद्धि हुई और और उसके बाद क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ण. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन की दिशा में ही विकृति आई है।

त. आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि, भारी कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण, घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि और पाटित आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि के कारण वास्तविक क्षति का खतरा और बढ़ गया है।

आयातकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशनों द्वारा किए गए अनुरोध

50. आयातकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशनों और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के बीच कारणात्मक संबंध का पूर्णतः अभाव है, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है:

- मात्रात्मक प्रभाव: कच्ची सामग्री भण्डारण, आग लगने की दुर्घटना, हुदहुद चक्रवात – संयंत्र बंद होना – कम हुआ उत्पादन – कम बिक्रियां- कम बाजार हिस्सा
- कीमत प्रभाव: ऋणात्मक कीमत कटौती – घरेलू उद्योग पीओआई तक बढ़ती हुई लागत के उत्तर में अपनी कीमतों में पर्याप्त वृद्धि नहीं कर सका – संयंत्र के बंद होने के कारण लाभप्रदता में गिरावट

ख. कारणात्मक संबंध के विश्लेषण में संयंत्र का बंद होना एक महत्वपूर्ण कारक है। इस मुद्दे पर, हेमाटाइट पिग आयरन मामले [1990 ओ.जे. (एल135) 7] और एजीएफए गेवार्ट एजी बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले का उल्लेख किया गया।

ग. याचिकाकर्ता ने मानक ऋण लागत को 90 दिनों के लिए घटाकर और 270 दिनों के लिए मानक ऋण लागत पर विचार करते हुए क्षतिरहित कीमत को बढ़ाकर पंधुच मूल्य को कम करने का प्रयास किया है।

घ. याचिकाकर्ता को हुई क्षति का एकमात्र कारण उत्पादन को रोकना था जिससे कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण पीओआई के दौरान 212 दिनों (लगभग 7 महीनों) बंद हो गया। ऐसे कारकों के कारण हुई क्षति के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट में भी यही पहलू बताया गया है। आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (201) ईएलटी481 (त्रि-दि.) मामले में माननीय सेस्टेट ने भी उस मामले में प्राधिकारी के अंतिम जाँच परिणामों को अस्वीकार करने के लिए घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट पर भरोसा किया था।

ङ. याचिकाकर्ता ने अपना कार्यनिष्पादन ऐसा बताया है जैसे यदि वह नहीं होता जो कोई घाटा नहीं होता। कानून में इसकी अनुमति नहीं है। प्राधिकारी उस अवधि जब याचिकाकर्ता प्रचालनरत था, के दौरान आयातों के स्तर और याचिकाकर्ता के अप्रचालनरत रहने के समय के आयातों के स्तर की तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा यह स्पष्ट नहीं है कि कार्यनिष्पादन के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री की किस कीमत पर विचार किया गया है। घरेलू उद्योग को क्षति निर्धारण के लिए 'जैसा है' आधार पर लेना चाहिए। इस मुद्दे पर, चीनी ताइपेई, इंडोनेशिया और ईयू (फ्रांस को छोड़कर) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा- अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 1 अक्टूबर और थाइलैंड – एच बीम्स की अपीलीय निकाय की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।

च. याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य की गणना मुद्रास्फीति लागत के आधार पर की है और संरचित सामान्य मूल्य पर गोपनीयता का दावा गलत किया है। इस संबंध में बिरला इरिक्शन अस्टिकल्सवस निर्दिष्ट प्राधिकारी 2004 (167) ई.एल.टी. 163 (ट्री.डेल.) उद्धरित किया गया था।

छ. यहां तक कि जिस समय याचिकाकर्ता उत्पादन कर रहा था, उस अवधि के दौरान भी इसका उत्पादन इष्टतम नहीं था। इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किए जाने के कारण पीओआई के दौरान करना आयात आवश्यक हुआ था।

ज. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री वास्तव में ऋणात्मक है जो आकस्मिक कारक नहीं होने के कारण अन्तर्निहित है।

झ. ऋणलागत और मालभाड़ा लागत के लिए समायोजन भारतीय कानूनों के अंतर्गत अनुमेय नहीं है। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क निर्धारणीय मूल्य हेतु जोड़ा जाना चाहिए और न कि पहुंच मूल्य की गणना करने के लिए सीआईएफ कीमत हेतु।

ञ. याचिकाकर्ता की लाभप्रदाता में गिरावट और लागत में वृद्धि के कारण मूलभूत घटक हैं। इस प्रकार याचिकाकर्ता के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता है।

ट. 2011-12 और 2012-13 की तुलना में पीओआई के दौरान मालसूची में कमी को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के लिए कोई क्षति नहीं हुई है।

ठ. जन सुनवाई के दौरान क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन के संबंध में मलेशिया की सरकार द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया जाना चाहिए। जन-सुनवाई के दौरान संबंधित देशों की सरकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को एडी जांच के दौरान उठे मुद्दों के बारे में अपने हितों को उठाने का अधिकार है।

ड. याचिकाकर्ता का यह दावा कि क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए एनआईपी में उत्पाद शुल्क और बिक्री को जोड़ा जाना चाहिए और सीवीडी भी आयात कीमत में जोड़ा जाना चाहिए, प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

ढ. संचयी जांच का टेस्ट वर्तमान मामले में भी संगत नहीं हो सकता है क्योंकि वर्तमान मामलों में किसी अंतिम मात्रा के आकस्मिक कारक के भंग होने के आधार पर समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

ण. याचिकाकर्ता की कम मात्रा आयात के कारण नहीं है परंतु कच्ची सामग्री की अल्प-आपूर्ति के कारण निष्क्रिय समय के कारण है।

- त. यदि पाटनरोधी शुल्क अपने इरेटिक और कच्ची सामग्री आपूर्ति मुद्दे के कारण विक्षिप्त निष्पादन के आधार पर लगाया जाता है तो प्रयोक्ता उद्योग की स्थिति असुरक्षित और अप्रतिस्पर्द्धी हो जाएगी।
- थ. याचिकाकर्ता का यह अनुरोध है कि एनआईपी जैसी अवधारणा कहीं भी वैश्विक रूप से सही नहीं है।
- द. प्राधिकारी को करों आदि को शामिल करने के लिए एनआईपी के संबंध में याचिकाकर्ता के विभिन्न दावों को अस्वीकृत कर देना चाहिए और एनआईपी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।
- ध. याचिकाकर्ता एक अकेले संयंत्र में तीन उत्पादों अर्थात् ईएच, एन-बुटानोल (एन-बीओएल) और आई-बुटानोल (आई-बीओएल) का उत्पादन करता है। इसलिए आयातों के लिए क्षति का कोई आंकन किए जाने से पूर्व इसकी जांच की जानी चाहिए कि याचिकाकर्ता ने एन-बीओएल का उत्पादन घटाकर और ईएच तथा आई-बीओएल का उत्पादन बढ़ाकर स्वयं अपनी क्षति की है।
- न. एचपीसीएल द्वारा मई-जून, 2013 में प्रोपलीन की आपूर्ति में व्यवधान और अगस्त, 2013 में प्रोपलीन एचपीसीएल के उत्पादन के लिए आवश्यक पीआरयू यूनिट को बंद करने का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस संबंध में याचिकाकर्ता की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2013, निदेशक रिपोर्ट और रेटिंग रिपोर्ट को नोट और आंकन किया जाना चाहिए।
- प. "उत्पादन", "बिक्री मात्रा" आदि जैसे याचिकाकर्ता के (कम) निष्पादन को दर्शाने वाली सभी संख्या और रूख को संबद्ध करना होगा और वित्तीय वर्ष 2013-14 के 212 दिनों के लिए संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री नहीं होने के कारण संबंधित संख्याओं और रूख को समायोजित किया जाना चाहिए।
- फ. आर्थिक क्षति विश्लेषण प्रत्याशित हैं और भूतलक्षी विश्लेषण नहीं है।
- ब. पारस्परिक रूप से संबद्ध देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति के कारण वर्तमान जांच में सभी संबद्ध देशों को संचयी करना अनुपयुक्त होगा। इस संबंध में डीजीएडी की निम्नलिखित जांच उद्धरित की गई थी:
- * यूरोपियन यूनियन, ईरान, इंडोनेशिया और जापान के मूल की अथवा से निर्यातित मेलामाइन के आयातों से संबंधित दिनांक 01 जून, 2012 की पाटनरोधी जांच।
- * अंतिम जांच परिणाम यूरोपियन यूनियन, चाइनीज तैपई, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए के मूल की अथवा से निर्यातित एसिटोन के आयातों से संबंधित दिनांक 04 जनवरी, 2008 की पाटनरोधी जांच।
- * अंतिम जांच परिणाम: चीन पीआर, कोरिया गणराज्य, ताइवान और ब्राजील से 3000 से 4000 मॉलक्यूलर भार के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलियोल के आयात से संबंधित दिनांक 11 नवंबर, 2004 की पाटनरोधी जांच।
- * अंतिम जांच परिणाम: चीन पीआर, पोलैंड, रूस और रोमानिया से बाल बियरिंग (50 मिमी. बोर डायामेटर तक) के आयातों से संबंधित दिनांक 19 मार्च, 2004 की पाटनरोधी जांच।
- भ. एक तरफ एआईएफटीए और इंडिया-मलेशिया सीईसीए के कारण उन्हीं संबद्ध वस्तुओं के लिए लागू मूल सीमा शुल्क मलेशिया और सिंगापुर से आयातों के लिए भिन्न है और दूसरी तरफ अन्य लक्ष्य देश (ईयू, यूएस और दक्षिण अफ्रीका) हैं।
- म. प्राधिकारी को ईयू आयातों को असंचयी करना चाहिए और इन आयातों के लिए जांच को समाप्त करना चाहिए। इस बिन्दु पर चीन, कंबोडिया और थाइलैंड से लोहे और इस्पात की कतिपय ट्यूब और पाइप फिटिंग तथा रूस से अमोनियम नाइट्रेट के ईयू मामले हैं।

य. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से उतराई आयात कीमत बढ़ी है जोकि क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कीमत में वृद्धि से अधिक थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तेजी आयात के कारण नहीं थी।

र.क्षति का पाटन एकमात्र और पर्याप्त कारण नहीं होना चाहिए। इस बिन्दु पर प्राधिकारी का अंतिम निष्कर्ष – मलेशिया, थाइलैंड, चीन पीआर और कोरिया आरपी के मूल की अथवा से निर्यातित कथोड रे कलर टेलीविजन पिकचर ट्यूब के आयातों से संबंधित दिनांक 17 फरवरी, 2009 की पाटनरोधी जांच और अंतिम जांच – यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और यूएसए के मूल की अथवा से निर्यातित एसिटोन के आयातों के संबंध में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की दिनांक 13 दिसंबर, 2013 की निर्णायक समीक्षा उद्धरित की गई थी।

कक. जांच के इस चरण पर पीओआई 15 माह के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती। प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम चीन पाआर, पोलैंड, रूस और रोमानिया से बाल बियरिंग (50 मिमी. बोर डायामेटर तक) के आयातों से संबंधित दिनांक 19 मार्च, 2004 पाटन-रोधी जांच उद्धृत की गई थी।

खख. याचिकाकर्ता अप्रैल-जून, 2014 की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस लेन-देन वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराने में विफल रहा है और केवल-उक्त आंकड़ों का सार उपलब्ध कराया है। इस प्रकार के सार की यथार्थता संदिग्ध है।

गग. इंडिया-मलेशिया सीईसीए अधिसूचना संख्या 56/2013 दिनांक 31 दिसंबर, 2013 के प्रकाश में क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान मलेशिया से आयात होने के कारणों की जांच करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है।

घघ. याचिकाकर्ता ने सम्पूर्ण जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नहीं की। इसके प्रकाश में तुलना के लिए अपनाई गई पद्धति प्रकट की जानी चाहिए और जन-सुनवाई के लिए भी मंजूरी दी जानी चाहिए।

ड.ड. याचिकाकर्ता के लाभ में भी गिरावट हुई है जबकि वह कच्चा माल खरीदने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि याचिकाकर्ता कच्ची सामग्री के अपने प्रापण का विविधीकरण कर सकता तो वह जांच अवधि (पीओआई) के दौरान उत्पादन को बंद करने से आसानी से बच सकता था।

चच. याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित यूरोपियन आयोग मामला पाटनरोधी के प्रश्न से ही संबंधित है न कि क्षति मार्जिन से। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त मामले का नाम उपलब्ध नहीं कराया है।

छछ. कच्चे माल की कमी के कारण घरेलू उद्योग कच्चे माल के लिए उच्च कीमत का भुगतान करता है।

जज. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वह संबद्ध वस्तुएं और ईएचए विभिन्न संयंत्रों में उत्पादित कर रहा है और किसी एक उत्पाद का उत्पादन किसी दूसरे पर निर्भर होने को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

झझ. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि इसने प्रौद्योगिकी में निवेश किया है, परंतु इसका निष्पादन अवधि खराब है, को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

ञञ. एचपीसीएल संयंत्र में आग प्रत्याशित घटना नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता वैकल्पिक स्रोतों से कच्चा माल प्राप्त कर सकता था और याचिकाकर्ता को कच्चे माल का आयात करने पर विचार करना चाहिए।

टट. पाटन के कारण गैर-लाभ पूर्ण कीमतों संबंधी याचिकाकर्ता का दावा असमर्थनीय है। पाटनरोधी योजना के तहत दुरुपयोग उपायों के प्रयास उपलब्ध हैं।

ठठ. प्रमुख रिफाइनरियां प्रोपलीन का उपयोग करती हैं जो पोली प्रोपलीन के विनिर्माण को बंद करने हेतु एनबीए के लिए प्रमुख कच्चा माल है। इस प्रकार, भारत में एनबीए के लिए कच्चे माल का स्रोत अनुपलब्ध होगा अथवा कम उपलब्ध होगा जो इसे संबद्ध वस्तुओं के आयात के लिए अनिवार्य बनाती है।

डड. उतराई कीमत के लिए मालभाड़ा लागतों के कारण डाउनवर्ड समायोजन के बारे में प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के दावों की समीक्षा और अस्वीकृति हेतु अनुरोध है।

ढढ. प्राधिकारी को निर्यात करने वाले उत्पादकों और इसके निर्यातकर्ताओं और घरेलू उद्योग के बीच ऋण लागतों में अंतर के लिए उतराई लागत को समायोजित नहीं करना चाहिए।

णण. याचिकाकर्ता ने कच्चे माल की कमी शुरू होने से पूर्व 2010/11 और 2011/12 के बीच क्षमताएं उत्पादन और बिक्री में काफी वृद्धि की।

तत. याचिकाकर्ता द्वारा क्षमता उपयोग भ्रामक रूप से कम बताया गया है क्योंकि क्षमता इस तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित की जानी चाहिए कि संयंत्र 12 माह की अवधि के दौरान केवल 153 दिन अथवा कम चला था।

थथ. याचिकाकर्ता का यह दावा कि इसने उत्पादन प्रक्रिया को इष्टतम करने के लिए निवेश किया है और इसका निष्पादन तथाकथित पाटित आयात से प्रतिस्पर्धा के कारण खराब हुआ है, गलत है।

दद. मैसर्स लुबोरिजोल ने कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पाद की बिक्री की स्थितियां निःसन्देह प्रमाणित हैं कि याचिकाकर्ता एकाधिकार स्थिति में प्रचालनरत है और बिक्री शर्तों पर दबाव बना रहा है।

धध. याचिकाकर्ता उक्त वस्तुओं के साथ ब्लैंडिड उत्पाद की आपूर्ति करने में इच्छुक नहीं है जो उच्च अंतिम ब्लैंडिड उत्पादों की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत का पता लगाने के लिए प्रयोक्ता को मजबूर कर सकता है।

नन. याचिकाकर्ता के उक्त उत्पाद का एकमात्र विनिर्माता होने के कारण अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों में कोई विश्वास कायम नहीं करता। तकनीकी अथवा वित्तीय कारणों से अपने संयंत्र को बंद करने के कारण उत्पाद की अनुपलब्धता घरेलू प्रयोक्ताओं को काफी कठिनाई में डाल सकती हैं और अपने लाभ के लिए उत्पाद की कीमत पर दबाव बनाने के लिए व्यापारियों को अनुमति देगा। इस प्रकार की स्थिति से न तो याचिकाकर्ता लाभान्वित होता है और न ही प्रयोक्ता।

पप. उत्पाद की सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति के लिए कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्रयोक्ता को नुकसान होगा और उनके द्वारा किए गए संभावित निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा।

फफ. उन वस्तुओं, जो उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं, पर पाटनरोधी शुल्क लगाना भारत नीति में सरकार द्वारा उठाए गए कदम का विरोधाभासी है।

बब. जून, 2014 के बाद जिस समय मैसर्स आंध्र पेट्रोकेमिकल्स ने आपूर्ति बंद कर दी थी, पक्षकार किसी रिसेलर से 1.5 गुना से अधिक लागत पर माल खरीदने को मजबूर हुआ था।

भभ. शुल्क एवं करों को शामिल करने के पश्चात आयातित माल की लागत आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स से खरीद की गई लागत से अधिक बनती है।

मम. मैसर्स एडवांस्ड माइक्रोडिवाइसेस (प्रा.) लिमिटेड ने कहा है कि भारतीय उद्योग को सुरक्षित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लागू किया जाना चाहिए। तथापि, संरक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारतीय उद्योग शिथिल पड़ जाए और अपनी दक्षता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर काम करना बंद कर दे।

यय. मैसर्स यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि उनके घरेलू उद्योग ने उत्पादन और बिक्री लगभग 15 प्रतिशत बढ़ाई है। इस अनुकूल बाजार स्थिति, जिसमें क्षमता उपयोग भी बढ़ा है, में लाभ किस प्रकार घट गया, पर प्रश्न-चिह्न लगाता है।

रर. भारतीय बैंक ऋणों के लिए व्याज दर हेतु समायोजन किए बिना कोई कम दाम कीमत नहीं होगी।

लल. मैसर्स बारकूर सरकैक्टेंट्स प्रा. लि. तथा मैसर्स यूनियोप कैमिकल्स प्रा. लि. ने कहा है कि वे भारत में वैकल्पिक विनिर्माता होने तक अथवा कम से कम 60000 एमटी/वर्ष का विनिर्माण किए जाने की स्थिति में हैं,

"नॉर्मल बुटानोल/ए-बुटाइल एल्कोहल" पर पाटनरोधी शुल्क के लिए कड़ा विरोध करेंगे क्योंकि एनबीए की मांग भारत में बढ़ रही है क्योंकि भारत में कृषि उद्योग का विकास हो रहा है। आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड हमारी बढ़ रही मांग की तुलना में बहुत छोटा विनिर्माता हैं।

बब. मैसर्स यूनियोप कैमिकल्स प्रा. लि. ने भी कहा है कि आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लि. एकमात्र विनिर्माता है और उनकी कुल उत्पादन क्षमता 30000 एमटी/वर्ष है, इसमें से आंध्र पेट्रोकेमिकल्स केवल 20000 एमटी से 22000 एमटी/वर्ष बनाता है क्योंकि इसका संयंत्र बहुत पुराना है और सदैव अनुरक्षण और बंदी के अधीन रहता है। इस प्रकार, कभी भी पूर्णतः उपयोग नहीं करते और भारत में इस उत्पाद की कुल मांग 70000 एमटी/वर्ष से अधिक है। इस प्रकार, लगभग 50000 एमटी/वर्ष का अंतर है जिसका आयात किया जाता है।

ककक. मैसर्स श्री कृष्णा पेट्रोकेमिकल्स ने कहा है कि उन्होंने अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 और अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि के दौरान यूरोपियन यूनियन (ईयू), मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के मूल के अथवा से निर्यातित नॉर्मल बुटानोल अथवा एन-बुटाइल एल्कोहल का आयात किया।

संचयी आंकन

51. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (iii) में प्रावधान है कि किसी उत्पाद के एक से अधिक देशों से पाटनरोधी जांच के अध्यक्षीन साथ-साथ किया जा रहा है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित निर्धारित होने की स्थिति में इस प्रकार के आयातों के प्रभाव का संचयी आंकन करेगा:

क) प्रत्येक देश/क्षेत्र से आयात की तुलना में पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत है अथवा पृथक्-पृथक् देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है तो आयात समान वस्तु के आयात के संचयी रूप से 7 प्रतिशत से अधिक है।

ख) आयातों के प्रभाव का संचयी आंकन आयातित वस्तु और इसी प्रकार की घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के प्रकाश में उपयुक्त है।

52. वर्तमान मामले में, प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन निर्धारित डी-मिनिमस सीमा से अधिक होना पाया गया है, प्रत्येक संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है और संबद्ध देशों से निर्यात सीधे पारस्परिक रूप से और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा ऑफर की गई इसी प्रकार की वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करता है। आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति तथा आयातित उत्पादों एवं समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के प्रकाश में आयातों के प्रभाव का संचयी आंकन उचित है। इसलिए, प्राधिकारी पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी आंकन करने के लिए इसे उपयुक्त मान सकते हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

53. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार और हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करके घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की है।

54. एडी नियमावली में प्राधिकारी द्वारा मात्रा और कीमत प्रभाव दोनों की जांच करके क्षति की जांच की जानी अपेक्षित है। क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयात की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव तथा (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव दोनों की जांच करने का उद्देश्य शामिल है। पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि भारत में उत्पादन अथवा खपत की सापेक्ष दृष्टि अथवा तुलनात्मक रूप से पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा पर्याप्त कम दाम कीमत है अथवा इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा पर्याप्त मात्रा के लिए कीमतों पर दबाव बनाता है अथवा प्रचलित कीमत बढ़ती है जिससे अन्यथा पर्याप्त मात्रा होगी।

55. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नलिखित उल्लेख है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ उत्पादन, भारी, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

56. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी प्राचलों की खराब स्थिति दर्शाना जरूरी है। कुछ प्राचल खराब स्थिति दर्शा सकते हैं जबकि कुछ सुधार दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी सभी क्षति प्राचलों पर विचार करते हैं और उसके पश्चात यह निर्णय करते हैं कि घरेलू उद्योग पाटन के कारण क्षति वहन कर रहा है अथवा नहीं।

57. प्राधिकारी ने अनुरोधों में तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति प्राचलों की निष्पक्ष रूप से जांच की है।

मांग का आंकन

58. संबद्ध वस्तुओं की मांग इसी प्रकार के समान घरेलू उत्पादों की घरेलू बिक्री को सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात में जोड़कर निर्धारित की गई है। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से लिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नीचे तालिका में दिए अनुसार क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में काफी वृद्धि हुई है:

मांग	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई	पीओआई*
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	19,321	21,612	14,472	7,651	6,121
संबद्ध देश	एमटी	19,297	23,949	31,929	53,195	42,556
अन्य देश	एमटी	3,918	5,192	205	750	600
मांग	एमटी	42,536	50,753	46,606	61,596	49,277
प्रवृत्ति		100	119	110	116	116

* पीओआई वार्षिकीकृत है (अप्रैल, 2013 से जून, 2014)

59. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2011-12 में देश में उत्पाद की मांग बढ़ी है, 2012-13 में घटी है और उसके बाद पीओआई में पुनः बढ़ी है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में उत्पाद के लिए मांग ने पर्याप्त वृद्धि दर्शाई है।

पाटित आयात का मात्रा प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव
आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

60. पाटित आयात की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में सापेक्ष रूप से अथवा उत्पादों अथवा खपत के लिए तुलनात्मक रूप से पाटित आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात मात्रा नीचे दी गई है:

आयात की मात्रा	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई	पीओआई*
ईयू	एमटी	3,546	8,758	6,738	7,021	5,617
मलेशिया	एमटी	4,423	5,804	16,454	22,459	17,967
दक्षिण अफ्रीका	एमटी	6,247	4,936	6,698	7,129	5,703
यूएसए	एमटी	5,081	3,977	1,835	3,014	2,411
सिंगापुर	एमटी	-	475	204	13,573	10,858
संबद्ध देश	एमटी	19,297	23,949	31,929	53,195	42,556
अन्य देश	एमटी	3,918	5,192	205	750	600
कुल आयात	एमटी	23,215	29,142	32,134	53,945	43,156
कुल आयात की दृष्टि से संबद्ध आयात		83%	82%	99%	99%	99%
भारतीय उत्पादन	एमटी	19,407	22,184	14,409	6,735	5,388
भारतीय उत्पादन की दृष्टि से संबद्ध आयात	%	99%	108%	222%	790%	790%
मांग	एमटी	42,536	50,753	46,606	61,596	49,277
मांग की दृष्टि से संबद्ध आयात	%	45%	47%	69%	86%	86%

61. उपरोक्त का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

- क. निरपेक्ष रूप से संबद्ध देशों से आयात में काफी वृद्धि हुई है। पीओआई के दौरान आयात में वृद्धि काफी अधिक है।
- ख. संबद्ध देशों से आयात संचयी रूप से पीओआई के दौरान कुल आयात का 99 प्रतिशत है।
- ग. संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई है। अन्य देशों से आयात शून्य रहा है। इस प्रकार भारत में उत्पाद के कुल आयात की तुलना में आयात में वृद्धि हुई है।
- घ. उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से आयात 2010-11 के दौरान 99 प्रतिशत से बढ़कर पीओआई में संचयी आधार पर 790 प्रतिशत हो गया है।
- ङ. कुल मांग की तुलना में संबद्ध देशों से आयात 2010-11 के दौरान 45 प्रतिशत से बढ़कर पीओआई में संचयी आधार पर 87 प्रतिशत हो गया है।
- च. भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध देशों से आयात में संपूर्ण क्षति अवधि में निरंतर वृद्धि हुई है।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध उत्पाद का आयात ऐसे समय हुआ है जबकि घरेलू उद्योग ने उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है। नीचे तालिका पीओआई के 15 माह में घरेलू उद्योग द्वारा आयात और उत्पाद की तुलना दर्शाती है:

पीओआई	वास्तविक		सूचीबद्ध	
	उत्पादन	आयात	उत्पादन	आयात
	एमटी	एमटी		
अप्रैल, 2013	***	***	100	100
मई, 2013	***	***	30	88
जून, 2013	-	***	-	147
जुलाई, 2013	***	***	196	96
अगस्त, 2013	***	***	334	226
सितंबर, 2013	-	***	-	67
अक्तूबर, 2013	***	***	193	133
नवंबर, 2013	***	***	193	267
दिसंबर, 2013	-	***	-	106
जनवरी, 2014	-	***	-	184
फरवरी, 2014	-	***	-	86
मार्च, 2014	-	***	-	71
अप्रैल, 2014	***	***	132	169
मई, 2014	***	***	107	111
जून, 2014	-	***	-	187

62. यह देखा गया है कि जब मई, 2013 में उत्पादन कम हुआ था, आयात में कमी हुई थी और जिस समय जून, 2013 में उत्पादन कम हुआ था, आयात में वृद्धि हुई थी, जुलाई, 2013 में जब उत्पादन में वृद्धि हुई थी, आयात में कमी हुई थी, अगस्त, 2013 (अप्रैल, 2013 के दो गुना से भी अधिक) में जब जुलाई में उत्पादन पर्याप्त था (अप्रैल, 2013 का दोगुना) में आयात काफी बढ़ा था और अगस्त (अप्रैल, 2013 के तीन गुना से अधिक) में आगे और बढ़ गया। अक्तूबर और नवंबर, 2014 के बाद इसी प्रकार की स्थिति पाई गई। यह भी पाया गया है कि दिसंबर, 2013 और मार्च, 2014 के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कोई उत्पादन नहीं किए जाने के बावजूद आयात की मात्रा न केवल कम थी बल्कि उसमें कमी हुई थी।

63. उतार-चढ़ाव के रुख को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से उत्पादन और आयात के बीच सह-संबंध तथा सह-दक्ष सांख्यिकी निर्धारित की है जो 0.5 बनती है तथा जहां एक घनात्मक संतुलित सह-दक्ष दर्शाता है कि दोनों प्राचल कमोबेश रूप में एक ही दिशा में बढ़े हैं और हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के विपरीत है कि आयात और उत्पादन विरोधी दिशा में बढ़े हैं।

64. इस प्रकार यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से भारत में आयात उत्पादन और खपत के सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों दृष्टियों से बढ़ा है। यह भी नोट किया गया है कि तथापि, घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान उत्पादन बंद कर दिया था और जबकि इस कारण से आयात शुरू हुआ है। यह भी सच है कि जिस समय घरेलू उद्योग का उत्पादन उच्च था, आयात की मात्रा उच्च थी। इस प्रकार, यह दर्शाता है कि जब भी घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करने की स्थिति में था, इसने अधिक आयात से प्रतिस्पर्धा का सामना किया।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयात का कीमत प्रभाव

65. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-11 (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

"जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।"

66. यह जांच की गई है कि भारत में समान उत्पाद की कीमत पाटित आयातों पर कम दाम कीमत से काफी रही है अथवा इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा पर्याप्त मात्रा के लिए कीमतों पर दबाव बनाता है अथवा कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करता है जो कि अन्यथा पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री में वृद्धि और कीमतों में कमी, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की है।

कीमत कटौती

67. यह निर्धारित करने के लिए कि आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ आयात की पहुंच कीमत की तुलना की है। इस संबंध में प्रत्येक संबद्ध देश से उत्पाद के पहुंच कीमत तथा व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूटों और करों का निवल की औसत विक्रय कीमत के बीच तुलना की है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित की गई थी। यह तुलना दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों के मूल की संबद्ध वस्तुएं उस कीमत पर भारतीय बाजार में आयातित की गई थी जो कि घरेलू उद्योग की विक्रय कीमतों से काफी कम थी। यह नोट किया गया है कि चूंकि घरेलू उद्योग में संपूर्ण पीओआई के दौरान उत्पाद का उत्पादन नहीं किया, इसलिए व्यावहारिक रूप से पीओआई के कुछ माह में घरेलू उद्योग में कोई बिक्री नहीं की। यह तालिका प्रत्येक संबद्ध देश से कीमत कटौती के स्तर को दर्शाती है:

कीमत कटौती	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा.	***	***	***	***
सूचकांक		100	103	106	117
ईयू					
उतराई कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
सूचकांक		100	104	101	110
कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	(0-10)%	(0-10)%	(0-10)%	(0-10)%
मलेशिया					
पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
सूचकांक		100	95	102	109
कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***

कीमत कटौती	% रेंज	(0-10)%	0-10%	(0-10)%	0-10%
दक्षिण अफ्रीका					
पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
सूचकांक		100	111	109	112
कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	(0-10)%	(5-15)%	(0-10)%	(0-10)%
यूएसए					
पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
सूचकांक		100	120	101	122
कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	0-10%	(5-15)%	0-10%	0-10%
सिंगापुर					
पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	आयात नहीं	***	***	***
सूचकांक		0	100	103	112
कीमत कटौती	रु./किग्रा.	-	***	***	***
कीमत कटौती	%	-	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	-	(0-10%)	(0-10)%	0-10%
संपूर्ण रूप में संबद्ध देश	रु./किग्रा.	-5 से 0	-10 से -5	-5 से 0	0 से 5

68. यह देखा गया है कि ई.यू. और दक्षिणी अफ्रीका से आयातों के मामले में कम दाम मांगना सीमान्त रूप से नकारात्मक होता है, जबकि अन्य देशों से सामान्यतः सकारात्मक होता है। पाटित आयातों से कम दाम मांगना कुल मिलाकर सकारात्मक, यद्यपि कम, होता है।
69. याचिकाकर्ता का यह दावा है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात चूंकि बाजार में एक बड़ा हिस्सा बनता है, इसलिए घरेलू उद्योग के पास आयात मूल्य को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। जबकि याचिकाकर्ता एक मात्र घरेलू आपूर्तिकर्ता है, बाजार में उत्पाद के उपभोक्ताओं की संख्या सीमित है और इसलिए उपभोक्ताओं को ऐसे मूल्यों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है जो विदेशी उत्पादकों के द्वारा दिए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में, घरेलू उद्योग आयातों के पहुंच मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि आयातकर्ता जब विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदते हैं, तो वे दो किस्म के क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं – (क) 90 दिनों के लिए ब्याज मुक्त क्रेडिट और (ख) 270 दिनों पर ब्याज लगाकर क्रेडिट और यह ब्याज लागत भारत में वित्त-पोषित लागत से काफी कम होती है। भारत में बैंकों के द्वारा दी गई ब्याज दर के लिहाज से आयातकर्ता काफी कम दर पर क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं। इस क्रेडिट की तुलना में बैंक 13 से 15 प्रतिशत की दर पर ऋण दे रहे हैं, इस तरह से घरेलू

उद्योगों की कीमतों की तुलना में आयात करना काफी सस्ता हो रहा है और आयातों को तरजीह देने का यह एक कारण है। याचिकाकर्ता ने इस वजह से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली और आयातों के पहुंच मूल्य में समायोजन करने का दावा किया है।

70. प्राधिकारी पहुंच मूल्य में निर्यातकों के द्वारा दिए गए क्रेडिट लागत लाभ के समायोजन के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट करते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्रेडिट लागत अलावा, माल – भाड़ा, अधिमान्य सीमा-शुल्क अथवा निर्यातकों के द्वारा एजेंटों को भुगतान किया गया कमीशन जैसे कारक भी हो सकते हैं, जिनके बारे में निर्यातकों और घरेलू उद्योग के व्यवसाय मॉडलों में अन्तर होने की स्थिति में ऐसे समायोजन के लिए तर्क के रूप में दिए जा सकते हैं। प्राधिकारी की समनुरूप प्रक्रिया के अनुसार पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए फैक्टरी से बाहर निर्यात मूल्य की गणना करते हुए अब तक उपर्युक्त समायोजनों को समुचित रूप से लेखे में लिया जाता है। इस संबंध में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कुछ इच्छुक पक्षकारों ने अलग-अलग देशों से आयातों पर अधिमान्य आधार पर सीमा शुल्क को क्षति विश्लेषण के लिए ध्यान में रखने के लिए तर्क दिया है क्योंकि घरेलू उद्योग पहुंच मूल्य को मिलाते हैं जो मूल्य को स्थिर करने से रोकता है। एक विशेष आयात स्रोत/स्रोतों पर आयातकर्ता देश के द्वारा दिए गए अधिमान्य सीमा-शुल्क का भी किसी पाटनरोधी जांच में पहुंच मूल्य को प्रभावित कर सकता है, जो पाटन के अलावा अन्य कारकों की जांच करते समय कारक जांच के एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किए जाने के लिए जरूरी होता है। इसलिए, पहुंच मूल्य को यदि क्रेडिट लागत के कारकों से बदला जाता है, तो इसके लिए संभवतः आयात स्रोत के एक अथवा कुछ स्रोतों पर अधिमान्य सीमा शुल्क की अपेक्षा एमएफएन पर बुनियादी सीमा-शुल्क में निहित कारकों की आवश्यकता होती है। अतः प्राधिकारी को इसके बारे में पहले की जांचों की भांति पहुंच मूल्य का मूल्यांकन करने की सुनिश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है।

कम कीमत पर बिक्री :

71. प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों से पारित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग द्वारा कम मूल्य पर बेचने के बारे में भी जांच की है। इस प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित एनआईपी की आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। कम दाम पर बेचने के बारे में निर्धारण करने हेतु कम दाम मांगने के लिए विचार किए आयातों का पहुंच मूल्य अपनाया गया है। आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य के साथ घरेलू उद्योग के भारित औसत एनआईपी की तुलना निम्नलिखित को दर्शाती है :-

यूरोपीयन संघ :-

- **पैट्रोकेम मिडिल ईस्ट, दुबई और आईसीसी केमिकल्स, यू.एस.ए के माध्यम से मै० ओक्सी जीएमबीएच :-** सीआईएफ के लिए 1 प्रतिशत पहुंच प्रभार और लागू सीमा शुल्क अर्थात् बुनियादी सीमा-शुल्क और उपकर को जोड़ करके मै० ओक्सी जीएमबीएच के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण किया गया है। इस तरह पहुंच मूल्य का *** \$/एमटी (-5 से 0 प्रतिशत) के रूप में क्षति मार्जिन के साथ *** \$/एमटी के रूप में मूल्यांकन किया जाता है।
- **असहयोगी उत्पादक/निर्यातक :-** ई.यू.से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पहुंच मूल्य की 1 प्रतिशत पहुंच प्रभार और लागू सीमा-शुल्क अर्थात् बुनियादी सीमा-शुल्क और उपकर सहित सबसे कम निर्यात मूल्य /सीआईएफ के आधार पर गणनी की गई है। अतः पहुंच मूल्य का *** \$/एमटी के रूप में उल्लेख किया जाता है। अतः क्षति मार्जिन का *** \$/एमटी (0 से 5 प्रतिशत) के रूप में उल्लेख किया जाता है।

क्षति संबंधी तालिका

उत्पादक	निर्यातक	पहुंच कीमत \$/एमटी	क्षतिरहित कीमत \$/एमटी	क्षति मार्जिन \$/एमटी	क्षति मार्जिन (%) रेंज
ऑक्सिया जीएमबीएच	पैट्रोकेम मिडल ईस्ट, दुबई	***	***	(नकारात्मक) ***	*** (-5 से 0)
ऑक्सिया जीएमबीएच	आईसीसी कैमिकल्स यूएसए	***	***	(नकारात्मक) ***	*** (-5 से 0)
असहयोगी उत्पादक/निर्यातक और उपरोक्त दोनों से भिन्न सम्मिश्रण		***	***	***	*** (0-5)

मलेशिया

- मै० पीसीएम के माध्यम से मै० पीसीडी : आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य का मै० पीसीडी के द्वारा निर्मित तथा भारत को मै० पीसीएम के द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के जांच किए गए भारित औसत सीआईएफ मूल्यों में 1 प्रतिशत पहुंच प्रभार और लागू सीमा शुल्क अर्थात् बुनियादी सीमा शुल्क और उपकर जोड़ कर निर्धारण किया जाता है। पहुंच मूल्य का इस प्रकार *** \$/एमटी के रूप में उल्लेख किया जाता है। मै० पीसीएम के माध्यम से मै० पीसीडी के लिए क्षति मार्जिन को इस प्रकार ***** \$/एमटी के रूप में उल्लेख किया जाता है।
- मै० बी ए एस एफ पेट्रोनास : मै. बी ए एस एफ पेट्रोनास के लिए पहुंच मूल्य का सीआईएफ के लिए 1 प्रतिशत मूल्य और लागू सीमा शुल्क को जोड़कर निर्धारण किया गया है। पहुंच मूल्य का इस प्रकार *** \$/एमटी के रूप में *** \$/एमटी (0 से 5 प्रतिशत) के रूप में क्षति मार्जिन के साथ उल्लेख किया जाता है।
- असहयोगी उत्पादक/निर्यातक : मलेशिया से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पहुंच मूल्य की 1 प्रतिशत प्रभार और लागू सीमा अर्थात् बुनियादी सीमा शुल्क और उपकर सहित सबसे कम निर्यात मूल्य/ सीआईएफ के आधार पर गणना की गई है। पहुंच मूल्य और क्षति मार्जिन का क्रमशः *** \$/एमटी और *** \$/एमटी (10 से 15 प्रतिशत) के रूप में निर्धारण किया जाता है।

क्षति संबंधी सारणी

उत्पादक	निर्यातक	पहुंच कीमत \$/एमटी	क्षतिरहित कीमत \$/एमटी	क्षति मार्जिन \$/एमटी	क्षति मार्जिन (%) रेंज
---------	----------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

पीसीडी	पीसीएम	***	***	***	*** (0 से 5)
बी ए एस एफ पेट्रोनास	बी ए एस एफ पेट्रोनास	***	***	***	*** (0 से 5)
असहयोगी उत्पादक/निर्यातक और उपरोक्त दोनों से भिन्न सम्मिश्रण		***	***	***	*** (10-15)

दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, सिंगापुर:-

- पीओआई में उपर्युक्त तीन सम्बद्ध देशों के उत्पादकों / निर्यातकों से संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य की सी.आई.एफ.पर 1 प्रतिशत प्रभार, उपकर सहित बुनियादी सीमा-शुल्क को जोड़ने के बाद सौदेवार डीजीसीआई एण्ड एस के आधार पर गणना की गई है। यूएसए, सिंगापुर और द. अफ्रीका से सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादकों / निर्यातकों के लिए क्रमशः *** \$/एमटी, *** \$/एमटी और *** \$/एमटी के रूप में विचार किया जाता है।

क्षति संबंधी तालिका

संबद्ध देश	उत्पादक	निर्यातक	पहुंच कीमत \$/एमटी	गैर क्षतिकारक कीमत \$/एमटी	क्षति मार्जिन \$/एमटी	क्षति मार्जिन (%) रेंज
दक्षिण अफ्रीका	कोई	कोई	***	***	***	*** (0-5)
यूएसए	कोई	कोई	***	***	***	*** (0-5)
सिंगापुर	कोई	कोई	***	***	***	*** (0-5)

72. यह देखा गया है कि यू.ई. को छोड़कर सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी से कम थे, इस प्रकार यह मूल्यों को रोकने का आभास देता है।

मूल्य प्रतिबंध / दबाव

73. क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा क्या ऐसे आयातों के दबावों से काफी हद तक कीमतें प्रतिबंधित हो रही हैं और कीमत में बढ़ोतरी को रोक रही है जो काफी सीमा तक हो गयीं होगी, इस बात का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने क्षति अवधि में लागतों और मूल्यों में परिवर्तन करने के बारे में विचार किया। स्थिति नीचे सारणी में दर्शायी है।

विवरण	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
बिक्री की लागत	रुपए / कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	107	122	144

बिक्री कीमत	रुपए / कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	103	107	117

74. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और विक्रय मूल्य दोनों में बढ़ोतरी हुई है, यद्यपि लागतों में काफी वृद्धि हुई है। पर घरेलू उद्योग उस सीमा तक अपने मूल्यों को बढ़ा नहीं सका है जिसके परिणामस्वरूप पीओआई में वित्तीय हानियां हुई हैं। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि अपने विक्रय मूल्य को लागत में बढ़ोतरी के अनुपात में अथवा लागत स्तर तक बढ़ोतरी करने में असमर्थ रहे हैं जिसकी वजह से बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति से हानि हो रही है। यह देखा गया है कि आयातों से घरेलू कीमतें प्रतिबन्धित हो रही हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि कच्चे माल की कमी और अलाभकारी कीमतों की वजह से घरेलू उद्योग पीओआई में सामान्य उत्पादन प्राप्त नहीं कर सका है। याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों से हुई हानि का मूल्यांकन करने के लिए निष्क्रिय समय की वजह से हुई लागत को कुल लागत से अलग कर दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग बेशक पीओआई में सामान्य उत्पादन प्राप्त करने में समर्थ रहा था परन्तु लागत विक्रय मूल्य की अपेक्षा काफी अधिक रही होगी।
75. क्षति की विभिन्न अवधि की घरेलू उद्योग की वार्षिक उद्योगों की जांच की गयी थी। यह देखा गया है कि कम्पनी ने अपने निष्पादन के बहुत से कारणों की पहचान की है, जिनमें ये शामिल हैं :- एचपीसीएल से प्रोपलीन की अनुपलब्धता, उत्पादों के विक्रय मूल्य में संगत वृद्धि न होने सहित कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, बढ़ती हुई विद्युत लागत, चीन में ओक्सो एल्कोहलों के लिए नयी क्षमताओं की शुरुआत करने के बाद उत्पादों और कच्चे माल की कीमतों के बीच अन्तर में कमी, रुपए का अवमूल्यन, सामान्य मुद्रा स्फीति और उत्पाद कीमतों में संगत वृद्धि न होना, प्रोपलीन की कीमतों में बढ़ोतरी और उत्पादों के बाजार विक्रय मूल्य कम होना, नयी क्षमताएं जिनकी शुरुआत हुई है और अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अतिरिक्त क्षमताओं की शुरुआत, कम उत्पाद मूल्य और परिणामस्वरूप काफी लम्बी अवधि से यूनिट की बन्दी तथा उत्पादों का पाटन। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है :- (क) निवेश कीमतों में बढ़ोतरी अथवा सामान्य मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि ; (ख) कम उत्पादन के कारण उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी (ऊपरी खर्च/ कम उत्पादन की वजह से हुए निश्चित खर्चों के कारण) ; (ग) रुपए का अवमूल्यन / वृद्धि ; (घ) उत्पाद की कीमतों का न बढ़ना ।
76. यद्यपि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही थी परन्तु इसके उत्पादों के विक्रय मूल्य में यथा अनुपात बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। इसके अतिरिक्त उत्पादन की लागत में ये बढ़ोतरियां कच्चा माल की कीमतों में बढ़ोतरी, विद्युत की दर में बढ़ोतरी अथवा सामान्य मुद्रास्फीति के कारण थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को सामान्य बाजार की स्थिति में उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी अथवा कमी के अनुरूप अपनी कीमतों को ऊपर अथवा नीचे करने की उम्मीद होती है। यदि घरेलू उद्योग को कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, विद्युत की दर में बढ़ोतरी अथवा सामान्य मुद्रा-स्फीति जैसे कारकों की वजह से उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी का सामना करना हो अथवा यदि घरेलू उद्योग इन बढ़ोतरियों के अनुपात में अपनी कीमतों को बढ़ाने में असमर्थ हो, तो ऐसा हो सकता है कि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करने से रोका गया हो। यद्यपि घरेलू उद्योग अपने विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी करने की अपनी असमर्थता के लिए उत्तरदायी अन्य कारकों की पहचान करता ही था, परन्तु प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये सभी कारक मूलतः आयातों से भी जुड़े होते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद की आयात प्रतिस्पर्धा के आधार पर मूल्य का निर्धारण करना होता है। चूंकि उपभोक्ता आयातित उत्पाद

मूल्य के तुलनीय मूल्य पर उत्पाद खरीदना चाहेंगे, और यदि घरेलू उद्योग ने उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी होने के बावजूद अपनी कीमतों में बढ़ोतरी न की हो, तो यह कम कीमत के आयातों की उपलब्धता की वजह से भी होता है। तथापि, यह माना जाता है कि कम उत्पादन होने की वजह से उत्पादन की लागत में हुई बढ़ोतरी उपभोक्ताओं पर नहीं जा सकती है तथा व्यवसाय उद्यमियों से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वे केवल इस वजह से अधिक कीमत लें कि वे अपने लाभ के स्तरों को बनाए रखना चाहते हैं और उत्पादन (और बाद) की बिक्री अन्य कारकों की वजह से कम थी

77. घरेलू उद्योग ने एक कारक के रूप में विनिमय दर में परिवर्तनों की पहचान की है। तथापि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के द्वारा विनिमय दर का यह उल्लेख विचाराधीन उत्पाद की कीमतों को बढ़ाने की उनकी सामर्थ्य के संदर्भ में है। यदि रुपए का अवमूल्यन होता है, तो आयातों की पहुंच मूल्य बढ़ जाता है तथा घरेलू उद्योग बेहतर कीमतें लेने की स्थिति में होता है। इसी प्रकार, यदि रुपए का मूल्य बढ़ता है तो आयातों के पहुंच मूल्य में गिरावट आती है तथा घरेलू उद्योग से अपनी कीमतें कम करने की उम्मीद की जाती है। अतः वार्षिक रिपोर्टों में विनिमय दर में घट-बढ़ संबंधी संदर्भ बाजार में अपनी कीमतों में बदलाव करने के लिए घरेलू उद्योग की समर्थता अथवा असमर्थता के बारे में होता है।
78. अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट क्षति के दो अलग-अलग कारकों को दर्शाती है – (क) घरेलू उद्योग को लागत में बढ़ोतरी होने के अनुपात में अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करने से रोका जा रहा है (जो पाटन के परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए) और (ख) कच्चे माल की अनुपलब्धता की वजह से घरेलू उद्योग की उत्पाद की उस सीमा तक उत्पादन करने में असमर्थता जितना यह कर सकता है। इसलिए प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि उत्पादन, बिक्री और बाजार शेयर में बदलाव का जहां तक संबंध है, इसमें हास भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण नहीं हो सकता लेकिन पाटित आयातों से कम कीमत मांगी जाती है और कीमत पर प्रतिबंध होता है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर :-

79. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षा है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। नियमावली में यह भी व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति के बारे में सभी प्रासंगिक आर्थिक कारक और सूचकों का एक वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए और ये शामिल होने चाहिए – बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार शेयर, उत्पादकता में वास्तविक और संभावित गिरावट, निवेश पर लाभ अथवा क्षमता का समुपयोजन ; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन में मार्जिन की मात्रा ; नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, सामान – सूचियां, रोजगार, मजदूरी, विकास तथा पूंजीगत निवेश जुटाने की सामर्थ्य। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरामीटरों के बारे में नीचे बताया गया है।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री :

80. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिए अनुसार है –

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई	पीओआई*
क्षमता	एमटी	20,625	22,500	22,500	28,125	22,500
उत्पादन	एमटी	19,407	22,184	14,409	6,735	5,388

क्षमता उपयोग	%	94.09%	98.60%	64.04%	23.95%	23.95%
घरेलू बिक्री	एमटी	19,321	21,612	14,472	7,651	6,121
मांग	एमटी	42,536	50,753	46,606	61,596	49,277

* पीओआई (आंकड़े वार्षिक हैं)

81. उपर्युक्त सारणी से यह देखा गया है कि :

- (क) देश में अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011-12 में घरेलू उद्योग ने क्षमताओं में अभिवृद्धि की।
- (ख) देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान काफी बढ़ोतरी हुई है।
- (ग) वर्ष 2011-12 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तथापि, उसके बाद वर्ष 2012-13 और पीओआई में भी उत्पादन में काफी गिरावट आयी। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन काफी कम था।
- (घ) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग के उसी रुझान को अपनाया है जैसा रुझान उत्पादन के बारे में था। घरेलू उद्योग वर्ष 2011-12 की अवधि में अच्छा क्षमता उपयोग प्राप्त कर सकता था, परन्तु उसके बाद 2011-12 और पीओआई के दौरान इसको काफी गिरावट हुई है। जबकि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में एक अवधि में 16 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई, परन्तु पीओआई के दौरान क्षमता उपयोग में केवल 24 प्रतिशत की गिरावट हुई। वर्ष 2010-11 में क्षमता उपयोग बढ़ा और उसके बाद वर्ष 2012-13 और पीओआई के दौरान इसमें काफी गिरावट आयी।
- (ङ.) वर्ष 2011-12 में घरेलू उद्योग की बिक्री बढ़ी और उसके बाद कमी हुई। वार्षिक आधार पर पीओआई में घरेलू बिक्री में आधार वर्ष 2010-11 की तुलना 68 प्रतिशत गिरावट हुई।

82. अतः निष्कर्ष यह है कि देश में उत्पाद की मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में काफी ह्रास हुआ है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष 2012-13 की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में काफी गिरावट आयी है। याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि जहां तक वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 के प्रारंभ में उत्पादन का संबंध है, कच्चे माल की अनुपलब्धता की वजह से घरेलू उद्योग को उत्पादन की हानि हुई है। घरेलू उद्योग को एचपीसीएल संयंत्र में आग लगने की वजह से (जो उन्हें कच्चे - माल की आपूर्ति करता है) फिर अगस्त 2013 से उत्पादन की हानि हुई। साथ ही, वार्षिक रिपोर्टों से यह भी स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने अपने उत्पादों के अलाभकारी मूल्य की वजह से उत्पादन को कम भी कर दिया था। यह नहीं है कि उत्पादन संबंधी संपूर्ण हानि कच्चे माल की अनुपलब्धता की वजह से हुई थी। विभिन्न पैरामीटरों (यथा उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, और बाजार शेयर) में हुए ह्रास को प्राधिकारी यह नहीं मानते हैं कि इस वजह से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

लाभ, लाभप्रदता, निवेश पर लाभ और नकद लाभ :-

83. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, विक्रय मूल्य, लाभ/ हानि, नकद लाभ, और निवेश पर लाभ के बारे में नीचे दिए अनुसार विश्लेषण किया गया है :-

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई*
बिक्री लागत	रु. / कि.ग्रा.	***	***	***	***
सूचक		100	107	122	144
विक्रय मूल्य	रु. / कि.ग्रा.	***	***	***	***
सूचक		100	103	107	117
लाभ/हानि	रु. / कि.ग्रा.	***	***	***	***

सूचक		100	68	-36	-125
लाभ/हानि	रु. लाख	***	***	***	***
सूचक		100	76	-27	-39
नकद लाभ	रु. / कि.ग्रा.	***	***	***	***
सूचक		100	72	-21	-100
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
सूचक		100	80	-15	-32
ब्याज से पहले लाभ	रु. / कि.ग्रा.	***	***	***	***
सूचक		100	63	-13	-64
ब्याज से पहले लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
सूचक		100	70	-19	-20
नियोजित पूंजी पर लाभ (रेंज)	%	15-20	10-15	0 to -5	-5 to -10

* पी.ओ.आई (आंकड़े वार्षिक हैं और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार हैं)

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :-

- क. क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत और विक्रय मूल्य दोनों में बढ़ोतरी हुई। तथापि, विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी लागत में हुई बढ़ोतरी से कम थी, अतः लाभप्रदता में गिरावट आयी।
- ख. आधार वर्ष 2010-11 में घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया था। तथापि, वर्ष 2011-12 में लाभप्रदता में ह्रास हुआ। इस वर्ष में उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद वर्ष 2011-12 में लाभप्रदता में गिरावट आयी। उसके बाद में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी ह्रास हुआ तथा वर्ष 2012-13 तथा पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की वित्तीय हानियां हुई।
- ग. क्षति अवधि के दौरान निवेश पर लाभ ने वही रुझान दर्शाया है जैसा लाभ का रुझान था। उसके बाद वर्ष 2012-13 और पीओआई में नकारात्मक स्थिति बनते हुए वर्ष 2011-12 में निवेश पर लाभ में गिरावट हुई।
- घ. उसके बाद वर्ष 2012-13 और पीओआई में नकारात्मक स्थिति बनते हुए वर्ष 2011-12 में ब्याज पूर्वलाभ और करों (पीबीआईटी) में गिरावट आयी।
- ड. नकद लाभ में भी वही रुझान दर्शाया है जैसा कि लाभों का था। उसके बाद 2012-13 तथा पीओआई में नकारात्मक स्थिति बनते हुए वर्ष 2011-12 में नकद लाभों में गिरावट आयी।

85. चूंकि घरेलू उद्योग ने पीओआई की कुछ अवधि में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया, इसलिए हितकर पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि लाभों में गिरावट की वजह घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादन का आस्थगित करना है। क्षति की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने उत्पादन की नियामक लागत को अपनाया है ताकि निष्क्रिय अवधि लागत को विश्लेषण में एनआईपी के निर्धारण हेतु शामिल न किया जा सके।

बाजार हिस्सा :-

86. घरेलू उद्योग के बाजार शेयर पर पाटित आयातों के प्रभावों की नीचे दिए अनुसार जांच की गई है :-

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	45%	43%	31%	12%
संबद्ध देश - आयात	%	45%	47%	69%	86%

अन्य देश - आयात	%	9%	10%	0%	2%
-----------------	---	----	-----	----	----

87. उपर्युक्त सारणी से यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है और संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में संचयी आधार पर समनुरूप बढ़ोतरी हुई है। आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार शेयर में 37 प्रतिशत की गिरावट हुई जबकि सम्बद्ध देशों के बाजार हिस्से में उसी अवधि में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तथापि, घरेलू उद्योग का उत्पादन, चूंकि, कच्चे माल की अनुपलब्धता और अलाभकारी उत्पाद कीमतों (अर्थात् पाटन) दोनों की वजह से प्रभावित हुआ, इसलिए प्राधिकारी ने देश में उत्पाद पाटन के प्रभाव को बाजार हिस्सा गिरावट के लिए एक सूचक के रूप में नहीं माना है।

रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

88. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति नीचे दिए अनुसार है :-

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई*
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
सूचक		100	83	67	66
वेतन और मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
सूचक		100	94	79	81
उत्पादन की प्रति इकाई के अनुसार मजदूरी	रु. / कि.ग्रा.	***	***	***	***
सूचक		100	83	107	294
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
सूचक		100	115	75	27

* पीओआई (आंकड़े वार्षिक हैं)

89. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास रोजगार में गिरावट आयी। वर्ष 2012 - 13 में भुगतान की गई मजदूरी में गिरावट आयी और फिर पीओआई के दौरान हल्की सी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2011 - 12 में उत्पादकता में वृद्धि हुई और बाद में उत्पादन में हुई गिरावट में अनुसार ही इसमें गिरावट आयी।
90. तथापि, चूंकि यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि कच्चे माल की अनुपलब्धता और अलाभकारी उत्पाद कीमतों (अर्थात्पाटन) दोनों की वजह से घरेलू उद्योग का उत्पादन प्रभावित हुआ, इसलिए प्राधिकारी ने इन पैरामीटरों को एक घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटन के प्रभाव के एक सूचक के रूप में नहीं माना है।

माल - सूचियां :-

91. संबद्ध वस्तुओं की माल - सूची से संबंधित आंकड़े नीचे सारणी में दर्शाए हैं :-

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
सूचक		100	179	239	122

92. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास माल – सूचियों में वर्ष 2012-13 तक बढ़ोतरी हुई और फिर जांच अवधि में इनमें गिरावट आयी।

तथापि, कच्चे माल की अनुपलब्धता और अलाभकारी उत्पाद कीमतों (अर्थात्पाटन) दोनों की वजह से घरेलू उद्योग का उत्पादन प्रभावित हुआ, इसलिए प्राधिकारी ने इन पैरामीटरों को एक घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटन के प्रभाव के एक सूचक के रूप में नहीं माना है।

वृद्धि

93. घरेलू उद्योग की वृद्धि से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दर्शाए हैं :-

वृद्धि	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
उत्पादन	हां/हां	-	14%	-35%	-63%
घरेलू बिक्री	हां/हां	-	12%	-33%	-58%
बिक्री लागत	हां/हां	-	7%	15%	25%
विक्रय मूल्य	हां/हां	-	3%	4%	10%
लाभ/(हानि)	हां/हां	-	-32%	-153%	-457%
आरओआई	हां/हां	-	-3%	-16%	-6%
बाजार शेयर	हां/हां	-	-3%	-12%	-19%

94. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वृद्धि पर मात्रा और मूल्य दोनों पैरामीटरों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जांच की अवधि के दौरान बिक्री, उत्पादन, बाजार शेयर, लाभों, निवेशों पर लाभ और नकद प्रवाह के संबंध में वृद्धि नकारात्मक थी।

95. अतः यह नोट किया जाता है कि कच्चे माल की अनुपलब्धता और अलाभकारी उत्पाद कीमतों (अर्थात् पाटन) दोनों की वजह से घरेलू उद्योग के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा और इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि मात्रा पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग की नकारात्मक वृद्धि को देश के उत्पाद पाटन के एक प्रभाव के रूप में निर्णायक नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, मूल्य संबंधी पैरामीटरों (जैसे लाभ, निवेश पर लाभ, और नकद प्रवाह) में वृद्धि का जहां तक संबंध है, प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि बन्दी की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए नियत व्यय की वजह से भी लाभों (परिणामतः नकद प्रवाह और निवेशों पर लाभ) में गिरावट हुई है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी के कॉस्ट ऑडीटर स्थिति के बारे में सतर्क रहे हैं और उन्होंने उत्पादन के आस्थगन की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए खर्चों को निकालकर विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता निर्धारित की है। यह नोट किया जाता है कि कॉस्ट आडीटरों के द्वारा निर्धारित लाभ की स्थिति भी मूल्य पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाती है। अतः यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग के लाभों पर उत्पादन आस्थगन के प्रभाव को हटा भी दिया जाए, तो भी घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक थी।

पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता

96. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को मानते हुए घरेलू उद्योग ने अपनी बढ़ती हुई क्षमता में निवेश किया है। तथापि, इन निवेशों के बावजूद घरेलू उद्योग का निष्पादन काफी खराब हो गया है।

पाटन स्तर और पाटन मार्जिन :-

97. यह नोट किया जाता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से पाटित मूल्यों पर देश में आयात हो रहा है तथा पाटन मार्जिन डी- मिनिमस सीमाओं से अधिक है

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक :-

98. संबद्ध देशों में आयात मूल्यों की जांच, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं, ये सब यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य और अहानिकर कीमतों से कम है और ये घरेलू उद्योग में कम दाम लेने अथवा कम दाम में बिक्री कर रहे हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्यतः विचाराधीन उत्पाद की कीमतें मुख्य कच्चे - माल की कीमतों के अनुसार आगे - पीछे रहनी चाहिए तथा घरेलू उद्योग इन निवेश कीमतों तथा आयातों की पहुंच कीमत को ध्यान में रखते हुए अपनी कीमतें निर्धारित कर रहा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वार्षिक रिपोर्टों में घरेलू उद्योग के विवरणों में घरेलू उद्योग के विवरण होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग कच्चे माल अथवा विद्युत की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद अपनी कीमतों को बढ़ा नहीं सका है। ये सार्वजनिक विवरण यह भी दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों का आयातों के साथ बेंचमार्क (निर्धारित) करता है। अतः संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू कीमतों के वस्तुतः कम करने का एक कारक है।
99. समिति का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तव में क्षति हुई है तथा उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, माल सूचियों जैसे मात्रा संबंधी पैरामीटरों में कमी की ओर ध्यान किये बिना ही कम मूल्य पर सस्ता बेचने से इसकी पुष्टि होती है।

आकस्मिक कारक

100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बहुत से हितकर पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि डी. आई. के लिए क्षति का कारण उनके “मूलभूत कारक” अर्थात् कच्चे माल की अधिक कीमत, प्रोफीलेन के एक स्रोत पर निर्भरता, आग दुर्घटना, अनुरक्षण की वजह से डी.आई और इसके आपूर्तिकर्ता अर्थात् एच पी सी एल दोनों के संयंत्र में बन्दी, 2 मुख्य उत्पादों अर्थात् एनबीए और 2 ईएचआई तथा आई बी ए आदि के मिश्रित उत्पादन को परस्पर बदलने की वजह से संभावित स्व-क्षति तथा अधिक मांग- आपूर्ति अन्तर की वजह से आयात करने की अनिवार्यता जैसे अन्य कारक, अन्तिम प्रयोक्ता के लिए विचाराधीन उत्पाद की बिना किसी रूकावट के निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जो ऊपर बताए अनुसार न्यायसंगत परिस्थितियों के परिणाम थे। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान ऐसे बहुत कारक हैं, जिनकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निस्संदेह, पाटन जैसे बाह्य कारकों के अलावा ये मूलभूत कारक भी होंगे।
101. प्राधिकारी ने अपनी विगत जांचों में ऐसे कारकों को उपयुक्त ढंग से समनुरूप पृथक किया है, जिससे पाटित आयातों की वजह से ही क्षति की मात्रा का मूल्यांकन किया जा सके। वर्तमान जांच में उत्पादन की मात्रा, बिक्री और क्षमता उपयोग पर मुख्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे 15 महीनों की पीओआई में 200 दिनों से अधिक समय संयंत्र में बंदी हुई। तथापि, पीओआई के पिछले कुछ महीनों में विशेषकर दिसम्बर, 2013 से जून, 2014 के दौरान संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्यों में गिरावट का रूझान दर्शाया है। पीओआई में संबद्ध देशों से आयात और महीनेवार उत्पादन उसी दिशा में रूझान को दर्शाता है जो कुछ हितकर पक्षकारों के इस दावे के विपरीत आंकड़ों को दर्शाते हैं कि आयात केवल तभी बढ़ते हैं जब डी. आई का उत्पादन कम हो जाता है। जब 2 ईएचआई और आईबीए के उत्पादन के आंकड़े सह संबंधित हो, तो पीओआई में एनबीए का महीनेवार उत्पादन 0.90 का सकारात्मक सहसंबंध भी दर्शाता है अर्थात् उसी दिशा में होता है जो डीआई द्वारा उत्पादित 3 उत्पादों में से मिश्रित उत्पादन के परस्पर बदलाव की वजह से स्वयं को हुई क्षति के दावे के विपरीत हो। घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी क्षति का सामना करना होगा जब इस पर पहुंच मूल्य (संभवतः कम पहुंच मूल्य) के समान रखने के लिए

दबाव में होता है। पीओआई में कम दाम लेने की महीने वार कीमत को नीचे दी गई सारणी में दर्शाए अलग – अलग महीनों में नकारात्मक और सकारात्मक हुआ नोट किया है। क्या पीओआई के दौरान कीमत का कम दाम मांगना एक निवल कीमत क्षति को दर्शाता है, अतः इस बात की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने पिछले कुछ महीनों की अपेक्षा सम्पूर्ण पीओआई की समग्र कीमत से कम दाम मांगने के बारे में मूल्यांकन किया है।

महीने वार कीमत कटौती

पीओआई	एनएसआर (रु./कि.ग्रा.)	पहुंच कीमत (रु./कि.ग्रा.)	कीमत का कम दाम मांगना (रु./कि.ग्रा.)
		औसत	औसत
अप्रैल- 13	***	***	-5 से 0
मई – 13	***	***	0 से 5
जून - 13	***	***	0 से 5
जुलाई - 13	***	***	-5 से 0
अगस्त- 13	***	***	-5 से 0
सितम्बर- 13	***	***	-5 से 0
अक्तूबर- 13	***	***	-5 से 0
नवंबर - 13	***	***	-5 से 0
दिसंबर -13	***	***	0 से 5
जनवरी - 14	***	***	15 से 20
फरवरी - 14	***	***	10 से 15
मार्च- 14	***	***	15 से 20
अप्रैल - 14	***	***	0 से 5
मई - 14	***	***	5 से 10
जून- 14	***	***	15 से 20
औसत			0 से 5

102. प्राधिकारी यह देखते हैं कि मूलभूत कारकों की वजह से भारी मात्रा में क्षति मुख्यतः होगी क्योंकि कच्चे माल की अधिक लागत, संयंत्र के ऊपरी खर्चों की वजह से कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा प्रक्रिया संबंधी अन्य कमियों को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार एनआईपी की गणना करते वक्त नियामक के रूप में माना जाता है। कीमत के प्रभाव को बाह्यकारकों अर्थात् पाटन से अधिक नियंत्रित कर लिया जाएगा जिसको सम्पूर्ण पीओआई के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन का मूल्यांकन करके नियंत्रित किया जा सकता है। मांग में बदलाव, उत्पाद की प्रतिस्थापनता/अप्रचलन आदि जैसे अन्य कारकों की प्राधिकारी के द्वारा यथा अपेक्षित जांच भी की जाती है। व्यापार की तुलनीय शर्तों पर कीमत प्रभाव को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए प्राधिकारी आयात कीमत के साथ बल्क प्रेषणों के लिए गणना किए एनआईपी से तुलना करता है, जो बल्क में होता भी है।

103. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अधीन सूचीबद्ध अन्य कारकों की नीचे जांच की है, जिनसे घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षति और पाटन के बीच कारक लिंक की जांच करने के लिए तथा घरेलू उद्योग को क्षति करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

तृतीय देशों से आयात :

104. प्राधिकारी ने सौदेवार आधार पर डीजीसीआई और एक से प्राप्त हुए संबद्ध वस्तुओं के आयात संबंधी आंकड़ों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि तीसरे देशों से आयात नगण्य हैं तथा घरेलू उद्योग के लिए दावा की गई क्षति का कारक नहीं हो सकते हैं।

मांग में कमी :-

105. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में पर्याप्त सुधार हुआ है। आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा पीओआई में इसमें बढ़ोतरी हुई है। मांग में संभव कमी से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों को व्यापार संबंधी प्रतिबंधित कार्य और उनके बीच में प्रतिस्पर्धा :-

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार संबंधी ऐसे कोई कार्य नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति कर सकते हैं।

प्रौद्योगिकी में विकास :-

107. घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया नाफ्था है, जिसके आधार पर वे भविष्य में प्राकृतिक गैस को बदलने की योजना बनाते हैं। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जहां तक अंतिम उत्पाद के उत्पादन का संबंध है, घरेलू उद्योग के द्वारा अपनायी गई मौजूदा प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया की विदेशी उत्पादकों की प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया से तुलना की जा सकती है।

खपत की पद्धति में बदलाव :-

108. घरेलू उद्योग के द्वारा ऐसी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है जिनका भारत में आयात किया गया है। खपत के पैटर्न में संभावित बदलाव ऐसे कारक नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने का दावा किया जा सकता है।

निर्यात संबंधी निष्पादन :-

109. याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति केवल घरेलू प्रचालनों की वजह से हुई है।

अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

110. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग के निष्पादन के प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन प्रभावित नहीं हुआ है। प्राधिकारी के द्वारा विचार की गयी सूचना केवल विधाराधीन उत्पाद के बारे में है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता के बारे में उत्पादन की तरह के रूझान का पालन किया गया है उत्पादकता में कमी की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

कारक लिंक सुनिश्चित करने के कारक

112. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में संबद्ध देशों से पाटित आयातों की वजह से कमी आयी है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारक लिंक निम्नलिखित आधारों पर सुनिश्चित किया जाता है :-

क. आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में काफी बढ़ोतरी हुई है। वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन और परिणामतया क्षमता उपयोग तथा बिक्री कच्चे माल की उपलब्धता एवं अलाभकारी कीमतों दोनों की वजह से प्रभावित हुई है। प्राधिकारी ने

घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी और तथा विचाराधीन उत्पाद के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री में कमी के बारे में विचार नहीं किया है।

- ख. घरेलू उद्योग विभिन्न संबद्ध देशों की आयात कीमत के आधार पर अपने विक्रय मूल्य निर्धारित कर रहा है। इसके अलावा जब कभी घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में कच्चे माल अथवा विद्युत अथवा सामान्य मुद्रास्फीति की वजह से बढ़ोतरी हो रही हो तो घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त करता है जब कभी घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें बढ़ानी चाही तो घरेलू उद्योग को उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी के अनुपात में अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोका गया है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के आयातों से कीमत पर दबाव पड़ा रहा है और यह कीमतों को बढ़ाने से घरेलू उद्योग को रोक रहे हैं। परिणामस्वरूप लाभों, नकद प्रवाह और आरओआई में कमी आयी है।
- घ. संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप बाजार में उत्पाद कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं।
- ड. घरेलू उद्योग का विकास आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित कीमत एवं मात्रा के आधार पर नकारात्मक हो गया है। यद्यपि मात्रा संबंधी पैरामीटरों में नकारात्मक वृद्धि उत्पादन संबंधी आस्थगन के कारण हो सकती है परन्तु कीमत संबंधी पैरामीटरों में नकारात्मक वृद्धि मुख्यतः देश में उत्पाद के पाटन की वजह से हुई है।
113. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए अहानिकारक कीमत निर्धारित की है। इसके लिए प्राधिकारी ने कच्चे माल और उपयोग के खपत संबंधी सर्वोत्तम मानदण्डों के बारे में विचार किया है। इसके अलावा, चूंकि घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान कुछ समय के लिए विचाराधीन उत्पाद का उत्पाद नहीं किया है, इसीलिए प्राधिकारी ने पिछले चार वर्षों के दौरान सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते *** एमटी की अधिकतम उत्पादन मात्रा के आधार पर निश्चित व्यय के बारे में विचार किया है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध- III के उपबंधों पर विचार करते हुए और विभिन्न पृथक खर्चों को हटा भी दिया है। घरेलू उद्योग के द्वारा नियोजित पूंजी की नियामवली के अनुबंध III के उपबंधों के आधार पर निर्धारण किया गया है तथा नियोजित पूंजी पर लाभ सांकेतिक उत्पादन के स्तर पर प्रदान किया गया है। घरेलू उद्योग की इस प्रकार निर्धारित क्षतिरहित कीमत की संबद्ध देशों के प्रत्येक निर्यातकों के संबद्ध आयातों की पहुंच मूल्य से तुलना की गयी है ताकि क्षति का मार्जिन निर्धारित किया जा सके।

भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

114. प्राधिकारी प्रयोक्ताओं के निवेदनों को नोट करते हैं तथा यह प्रस्ताव करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्यतः : पाटन के व्यापार संबंधी अनुचित कार्यों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है। जिससे भारतीय बाजार में खुली और स्पष्ट प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटन रोधी उपायों को लागू करना किसी भी तरीके से संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है और उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
115. प्राधिकारी यह भी प्रस्ताव करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क लगाने की स्थिति में भी भारत में उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है लेकिन ऐसे पाटन रोधी उपायों से भारत में स्पष्ट स्पर्धा में कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत पाटन रोधी उपायों से अनुचित प्राप्त हुए लाभों में कमी आ सकती है। जिससे घरेलू उद्योग की कमी प्रभावित होगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता रखने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता आपूर्ति के दो या दो से भी अधिक स्रोतों को रख सकेंगे।

प्रकटन पर टिप्पणियां

घरेलू उद्योग द्वारा टिप्पणियां

116. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:
- कीमत की कटौती का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने याचिका द्वारा उठाए गए ऋण की अवधि के मुद्दे को अस्वीकार कर दिया है।
 - प्राधिकारी कृपया शुल्क तालिका में यह विनिश्चित करें कि विचाराधीन उत्पाद पर इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि सीमा शुल्क के इस वर्गीकरण के अंतर्गत आयातकों द्वारा वस्तुओं को स्वीकृत किया जाता है, शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी कृपया शुल्क तालिका में यह विनिश्चित कर

सकते हैं कि सीमाशुल्क का वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है। यह निवेदन किया गया था कि केवल शुल्क तालिका की विषय सामग्री इस संबंध में प्रासंगिक है। “विचाराधीन उत्पाद” से संबंधित पैरा में सब कुछ उल्लेख किया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करते समय शुल्क तालिका की अनदेखी की जाएगी। पत्तन पर सीमाशुल्क के प्राधिकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर विचार कर सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं और अंतिम जांच परिणाम द्वारा जारी की गई अधिसूचना को ध्यान में नहीं रख सकते हैं।

- निर्धारित की गई क्षति कीमत अत्यधिक कम है और इससे बहुत कम अनुचित क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जाता है।
- वास्तविक उत्पादन की अनदेखी करना और क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए किसी अन्य उत्पादन आधार को अपनाना अनुपयुक्त है। प्राधिकारी को लागत, लेखा परीक्षा विवरण के अनुसार व्यय पर विचार करना चाहिए तथा इस तथ्य की अनदेखी करनी चाहिए कि याचिकादाता का संयंत्र बंद पड़ा हुआ था।
- प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भाड़े को शामिल करने के याचिकादाता के अनुरोध पर विचार करें।
- क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए ऋण की अवधि पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में हॉलडोर टोपोसो के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ऋण के प्रभाव को या तो “निर्यातक की लागत” अथवा “आयातक के लाभ के रूप में देखा जा सकता है”।

निर्यातक की लागत

क्रमांक	प्राचल		मामला- 1	मामला - 2	मामला - 3	मामला - 4
1	ब्याज मुक्त ऋण					
क	ऋण अवधि	दिवस	90	120	180	365
ख	निर्यातक की ब्याज लागत	%	6%	6%	6%	6%
ग	बिक्री कीमत (परिकल्पित)	अम.डॉ./ एम. टी.	1400	1400	1400	1400
घ	.ऋण लागत	अम.डॉ./ एम. टी	21	28	41	84
ड.	.ऋण लागत %	%	1.48%	1.97%	2.96%	6.00%
2	ऋण पर लगने वाला ब्याज					
क	ऋण अवधि	Days	90	120	180	365
ख	निर्यातक की ब्याज लागत	%	6%	6%	6%	6%
ग	निर्यातक द्वारा प्रभारित ब्याज लागत	%	4%	4%	4%	4%
घ	ब्याज लागत में अंतर	%	2%	2%	2%	2%
ड.	बिक्री कीमत (परिकल्पित)	अम.डॉ./ एम. टी	1400	1400	1400	1400
च	ऋण लागत	अम.डॉ./ एम. टी	7	9	14	28
छ	ऋण लागत %	%	0.49%	0.66%	0.99%	2.00%

आयातक को लाभ:

क्रमांक	प्राचल		मामला- 1	मामला - 2	मामला - 3	मामला - 4
1	ब्याज मुक्त ऋण					
क	ऋण अवधि	दिवस	90	120	180	365
ख	आयातक की ब्याज लागत	%	13%	13%	13%	13%
ग	हैजिंग लागत	%	6%	6%	6%	6%
घ	आयातक की निवल लागत	%	7%	7%	7%	7%
ड.	बिक्री कीमत (परिकल्पित)	अम.डॉ./ एम. टी	1400	1400	1400	1400
च	ऋण लागत	अम.डॉ./ एम. टी	24	32	48	98
छ	ऋण लागत %	%	1.73%	2.30%	3.45%	7.00%
2	ब्याज युक्त ऋण					
क	ऋण अवधि	दिवस	90	120	180	365
ख	आयातक की ब्याज लागत	%	13%	13%	13%	13%
ग	निर्यातक द्वारा प्रभारित ब्याज लागत	%	4%	4%	4%	4%
घ	हैजिंग लागत		6%	6%	6%	6%
ड.	ब्याज लागत में अंतर	%	3%	3%	3%	3%
च	बिक्री कीमत (परिकल्पित)	अम.डॉ./एम.टी	1400	1400	1400	1400
छ	ऋण लागत	अम.डॉ./एम.टी	10	14	21	42
ज	ऋण लागत %	%	0.74%	0.99%	1.48%	3.00%

- पाटन शुल्क, पाटन शुल्क (शुल्क के निर्धारित रूप में) की निर्धारित मात्रा के रूप में लगाया जा सकता है, जैसा कि उसे अम.डॉ./एम.टी के रूप में निर्धारित किया गया है। उक्त दावे के समर्थन में सीईएसटीएटी के मामलों को उल्लिखित किया जा सकता है।
- कोरिया एनबीआर के मामले में माननीय सीईएसटीएटी ने मै0 कुम्हो पैट्रो-कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड (2004(170) ई.ई.टी. 274), निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के आधार पर निर्धारित शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिवर्तनीय पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है।
- मैटकोक के मामले में सी ई एस टी ए टी ने अपने निर्णय 2000 (116) ई.एल.टी. द्वारा पाटनरोधी शुल्क को परिवर्तनीय शुल्क को संशोधित कर निर्धारित शुल्क कर दिया है।
- विट्रीफाइड टाइलों के मामले में सी ई एस टी टी ने निर्धारित मात्रा में शुल्क लगाए जाने के निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय की संपुष्टि की है।
- चीन से मैट कोक के मामले में सी ई एस टी ए टी का निर्णय।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियां

117. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :-

- डी जी सी आई एंड एस के अनुसार संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की गोपनीयता का दावा करने का कोई औचित्य नहीं है।
- घरेलू बाजार को यदि कोई क्षति हुई है, तो वह संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं बल्कि ऐसी क्षति स्वतः की गई है। प्रकटन विवरण में संयंत्र के बंद होने के कारण निष्क्रिय समय के कारण याचिकादाता के उत्पादन की लागत में समायोजन करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई क्रिया प्रणाली के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है।
- यदि कोई पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है तो उसकी सिफारिश केवल भारतीय रुपयों में ही की जानी चाहिए और न कि संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर में।
- मौजूदा मामले में यदि कोई शुल्क लगाया गया है तो उसमें ऐसे प्रयोक्ता की लागत को भी शामिल किया जाएगा जोकि अकेले घरेलू उत्पादक द्वारा संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति न किए जाने की समस्या का सामना कर रहे हैं।
- प्राधिकारी कृपया संपूर्ण प्रकटन विवरण में "पैट्रोनास" को बड़े अक्षरों में ही उल्लिखित करें।
- प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है और यह वृद्धि जांच अवधि में उत्पादन के प्रासंगिक है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सही नहीं है कि घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान 263 दिनों की अवधि के लिए बंद पड़ा हुआ था, जिसमें से 231 दिनों के लिए वह कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण बंद था और शेष दिनों के लिए वह अलाभप्रद कीमतों के कारण बंद था।
- प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयात का प्रत्येक तिमाही में विश्लेषण करना चाहिए। आयात की मात्राओं के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन का प्रत्येक महीने विश्लेषण करने से एक विकृत छवि प्रतिबिंबित होती है।
- यह समझ में नहीं आता कि किस आधार पर संबद्ध देशों से उत्पादन और आयातों के बीच सह-संबंध स्थापित किया गया है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा उत्पादन और आयात के वास्तविक आंकड़ों का खुलासा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त महीने बाद उत्पादन और आयात के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
- उचित विश्लेषण करने के लिए आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना केवल उस अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के साथ ही किया जाना चाहिए, जिसमें घरेलू उद्योग प्रचालन में था। ऐसे विश्लेषण से यह पता चलेगा कि इस मामले में कोई कीमत कटौती नहीं की जा रही है।
- कीमत में कटौती करने का प्राधिकारी का विश्लेषण सही नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन की बहुत अधिक लागत पर विचार किया है।

- यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर समग्र जांच अवधि के लिए भारित औसत आधार पर एन आई पी का निर्धारण किया गया है। प्राधिकारी ने जिन महीनेवार कच्चे माल की कीमतों पर विश्वास किया है, उसके बारे में सूचीबद्ध तरीके से खुलासा किया जाना चाहिए ताकि घरेलू उद्योग के उत्पादन और एनआईपी के संबंध में संदेह दूर हो सके।
- यह समझ में नहीं आता कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के प्रति यूनिट पर ऐसे वेतन का किस आधार पर दावा किया गया है और प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृत दी गई है।
- उस अवधि के लिए एनआईपी परिकलित किया जाना चाहिए जिस दौरान घरेलू उद्योग प्रचालन में था और पहुंच मूल्य की तुलना भी उसी अवधि के लिए की जानी चाहिए।
- यह कहना गलत है कि उत्पादन की कीमतें इसलिए नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि सभी संबद्ध देशों के लिए पहुंच मूल्य के विश्लेषण से ऐसा पता चलता है कि समग्र क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान पहुंच मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों ऐसा पता चलता है कि क्षति का एकमात्र कारण कच्चे माल की आपूर्ति न होना था जिसके फलस्वरूप संयंत्र बंद करना पड़ा।
- प्राधिकारी को क्षति विश्लेषण अवधि से घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों से सही उद्धरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे यह पता चले कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका गया है।
- घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र कारण संयंत्र के बंद होने के कारण उसके उत्पादन का कम होना है।
- प्राधिकारी का आर्थिक क्षति का निर्धारण करने के लिए मात्रा के प्राचलों पर विचार करने का निर्णय कानूनी रूप से असंगत है। घरेलू उद्योग को हुई आर्थिक क्षति का उचित मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग के सभी आर्थिक प्राचलों पर विचार किया जाना चाहिए।
- प्राधिकारी को कीमत प्रभाव पर अपने निर्णय में संशोधन करना चाहिए और यह निर्णय देना चाहिए कि जांच अवधि के दौरान पाटन के कारण कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- घरेलू उद्योग को कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है।
- प्राधिकारी द्वारा विचारित कच्चे माल की कीमतें बहुत अधिक हैं।
- प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान चुनिंदा महीनों (जबकि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुएं विनिर्मित की थीं) के लिए उत्पादन की लागत और कच्चे माल की कीमत के आंकड़ों के आधार पर एनआईपी निर्धारित की है लेकिन उन्होंने उसकी तुलना जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के औसत पहुंच मूल्य के साथ की है। इसलिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और एनआईपी का पुनर्निर्धारण करना चाहिए।
- घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार वेतनों में अत्यधिक वृद्धि के कारण उत्पादन की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- प्राधिकारी ने गलत तरीके से यह निर्णय लिया है कि रोजगार, उत्पादकता और मजदूरियां, आर्थिक क्षति का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। इसके साथ ही प्राधिकारी का यह प्रेक्षण भी सही नहीं है कि मालसूची क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ क्षति का एक संकेतक नहीं है।
- जारी किए जाने वाले संपूर्ण अंतिम जांच परिणाम में जहां कहीं भी प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मात्रा के प्राचलों की जांच की है, वहां यह दर्ज किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण मात्रा के प्राचलों को कोई क्षति नहीं हुई है।
- जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की संवृद्धि पर प्राधिकारी द्वारा गलत विश्लेषण किया गया है।
- यह नहीं समझा जाता कि प्राधिकारी ने किस आधार पर घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा की जांच की है।
- प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें और एनआईपी गलत ढंग से निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को जांच अवधि से पूर्व अवधि के लिए एनआईपी के सूचीबद्ध आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- प्राधिकारी यह गलत तरीके से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की कीमतें कच्चे माल की कीमतों के अनुरूप नहीं चलती हैं और घरेलू उद्योग अपनी कीमतें पहुंच कीमतों के आधार पर तय कर रहा है। प्राधिकारी ने

यह निर्णय भी गलत तरीके से दिया है कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें आयातों के अनुसार निर्धारित करता है।

- घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों पर उसी तरह से विचार किया जाना चाहिए जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के दावों का समर्थन करने के लिए पहले से स्थापित तथ्यों में और अधिक तथ्य नहीं जोड़ने चाहिए। इसके समर्थन में सी ई एस टी ए टी के आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि0 बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी {2006 (201) ई.एल.टी. 481 (ट्राई – डैले)} मामले का उल्लेख किया गया है।
- प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में वृद्धि को नोट करते समय प्रयोज्यताओं की लागत में होने वाली वृद्धि पर भी विचार करना चाहिए।
- मलेशिया से होने वाले आयात केवल भारत के घरेलू बाजार में मांग और पूर्ति में व्याप्त अंतर को दूर कर रहे हैं।
- जांच अवधि के दौरान क्षति विश्लेषण की अवधि में एन बी ए के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल प्रोपीलीन की अधिक कीमतों की जांच की जानी चाहिए।
- मौजूदा जांच में प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार मै0 पेट्रोनास कैमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएच बीएचडी और मै0 बीएस पेट्रोनास कैमिकल्स एसडीएन बीएचडी नामक संबंधित फार्मों के लिए पाटनरोधी शुल्क की समान दर की सिफारिश की जानी चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी जांच की जा रही है :

(क) चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, थाइलैंड और संयुक्त अरब अमीरात {अधिसूचना सं. 06/2013-सीमाशुल्क (ए डी डी) दिनांक 12 अप्रैल, 2013} के मूल की अथवा वहां से निर्यातित प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड।

(ख) चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताइपेई, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका {अधिसूचना सं. 27/2014-सीमाशुल्क (ए डी डी) दिनांक 13 जून, 2014} के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "विनाइल क्लोराइड की होमोपॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड)" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा।

- इस मामले में सीआईएफ के निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में पाटन मार्जिन का परिकलन किया जाना चाहिए और न कि कारखानागत निर्यात कीमत पर।
- परिचर्चा में अथवा रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि 212 दिनों के लिए घरेलू उद्योग को हुए उत्पादन में घाटे के कारण कैसे स्वतः क्षति नहीं हुई है, बल्कि यह क्षति आयातों से हुई है।
- यह देखा जाना बाकी है कि प्राधिकारी ने कैसे जांच अवधि को तुलना की अवधि के रूप में विचार किया है और कच्चे माल, प्रयोज्यताओं आदि जैसे विभिन्न प्राचलों के लिए "श्रेष्ठ उपयोग" अपनाने के लिए विगत तीन वर्षों पर विचार किया है।
- कारणात्मक संबंध स्पष्ट रूप से पाटनरोधी नियमावली के नियम 9 (2) और पाटनरोधी करार (एडीए) के अनुच्छेद 5.2 की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं।
- मौजूदा जांच में संबंधित देशों को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ गलत तरीके से संयोजित किया गया है। प्राधिकारी यूरोपीय यूनियन के आयातों को संचय नहीं करते हैं और उपायों को लागू किए बिना ही ऐसे आयातों के खिलाफ जांच को समाप्त कर देते हैं उक्त दावे के समर्थन में एडीए के अनुच्छेद 3.3, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के पैराग्राफ (3), यूरोपीय समितियों – ब्राजील से मेलेबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग्स {डब्ल्यू टी-डीएस 219/एबी/आर दिनांक 22 जुलाई, 2003}, चीन, क्रोशिया और थाइलैंड से आयरन अथवा स्टील की कुछ ट्यूब और पाइप फिटिंग्स {कमीशन विनियमन (ई सी) 16 अगस्त, 1995 की सं0 2022/95} के मामलों का उल्लेख किया गया है।

- यूरोपीय यूनियन से मांग और आयातों में वृद्धि होने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान इनमें गिरावट आई है।
- प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र बाजार का एक सूचक है। घरेलू बाजार में आयातों का अंतरप्रवाह पाटन को नहीं दर्शाता है, विशेषकर मौजूदा मामले में जहां घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान उत्पादन बंद कर दिया है।
- चूंकि प्राधिकारी द्वारा परिकलित किया गया क्षति का मार्जिन नकारात्मक (-5 से 0 प्रतिशत तक) है, इसलिए, यूरोपीय यूनियन से उत्पादक/निर्यातक के कारण कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है।
- प्राधिकारी का यह तर्क गलत है कि याचिकादाता को प्रोपलीन की 44 प्रतिशत कीमत वृद्धि (जब उसी अवधि के दौरान यूरोपीय यूनियन में प्रोपलीन की आयात कीमत की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि होती है) होने का लाभ अंतरित कर देना चाहिए था।
- कच्चे माल की अतिरिक्त लागत को अंतरित करने की याचिकादाता की असमर्थता के लिए आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- संबद्ध देशों से आयातों ने याचिकादाता की कीमतों में ह्रास/न्यूनीकरण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त एन-बुटानोल के यूरोपीय यूनियन के आयातों की कीमतों ने समग्र जांच अवधि के दौरान भारतीय कीमतों की कटौती नहीं है और यूरोपीय यूनियन की आयात की मात्रा में वर्ष 2011/12 से 47 प्रतिशत की कमी हुई है।
- प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष देते हुए मात्रा के प्राचलों में गिरावट आने पर विचार नहीं किया है कि क्या घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है। इसके साथ ही पूंजी निवेश को बढ़ाने में घरेलू उद्योग की अक्षमता और लाभ में गिरावट भी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन को बंद करने के कारण हुई है।
- प्राधिकारी ने बाजार के हिस्से, रोजगार, लाभप्रदता और वेतन में गिरावट आने पर विचार नहीं किया है और उन्होंने घरेलू उद्योग पर पाटन के आयात के एक संकेतक के रूप में मालसूची में परिवर्तनों पर विचार किया है।
- चूंकि यूरोपीय यूनियन से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे हैं अथवा कम कीमत पर बिक्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्षति का मूल्यांकन करने के लिए आरोपित पाटन अप्रासंगिक है।
- प्राधिकारी को पाटित आयातों से भिन्न अन्य कारकों की जांच करनी चाहिए जिनके कारण उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कारणात्मक संबंध और यूरोपीय यूनियन से आरोपित पाटित आयातों के बीच कोई संबंध नहीं है।
- पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना निचले स्तर के भारतीय उद्योगों के हित में नहीं है क्योंकि लोकल मांग घरेलू उत्पादन के दुगने से भी अधिक है।
- मौजूदा याचिका का एकमात्र उद्देश्य पाटनरोधी शुल्क लगाने के माध्यम से कृत्रिम आपूर्ति की कमी पैदा करना है जिससे याचिकादाता अपनी कीमतों को बढ़ा सकता है जोकि घरेलू प्रयोक्ताओं के लिए हानिकार होगी और यह पाटनरोधी तंत्र का गैर-कानूनी प्रयोग है।
- प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह याचिकादाता को ये आदेश दे कि वह अपनी उत्पादन क्षमताओं पर हुडहुड नामक चक्रवात के प्रभाव पर और ब्यौरे प्रस्तुत करे ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप आपूर्ति में कमी होगी जोकि भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए नुकसानदायक होगी।
- ऐसा माना गया है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की परिसंपत्तियों के बही मूल्य का उपयोग करके नियोजित पूंजी निर्धारित की है।
- प्राधिकारी को निचले स्तर तक की क्षतिरहित कीमत को समायोजित करना चाहिए ताकि वह (1) याचिकादाता की क्षति के भाग के रूप में यह स्वीकार करे कि यह आयातों के कारण नहीं हुई है और (2) आंशिक रूप से ऐसी क्षति स्थानीय आपूर्तिकर्ता से अत्यधिक कीमतों पर प्रोपलीन को खरीद कर स्वतः की गई है जबकि यह प्रत्यक्ष रूप से अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हो रही थी, को भी ध्यान में रखें।

- उपयुक्त औचित्य के बिना जांच अवधि निर्धारित की गई है।
- घरेलू उद्योग को यदि कोई क्षति हुई है तो वह आरोपित पाटित आयातों से भिन्न अन्य कारकों के कारण हुई है।
- यह निष्कर्ष देना गलत है कि भारतीय घरेलू उद्योग की कीमत का स्तर पाटित आयातों के कारण अलाभप्रद हो गया है। इसके विपरीत उत्पादन की लागत बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के असामान्य रूप से बढ़ गई है।
- कच्चे माल की अनुपलब्धता और उसके फलस्वरूप 212 दिन तक संयंत्र के बंद होने से कारणात्मक संबंध टूटता है।
- याचिकादाता ने अपरिहार्य रूप से घरेलू मांग में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण वर्ष 2010-11 से जांच अवधि तक आयातों के पक्ष में लाभ का बाजार का हिस्सा गंवा दिया।
- बिक्रियों की असामान्य रूप से अधिक लागत के आधार पर परिकलित की गई एनआईपी अनुचित रूप से अत्यधिक है।
- यूरोपीय यूनियन के निर्यातकों को ऐसी समस्त सूचना प्रदान नहीं की गई है कि पाटन, कीमत की कटौती और कम कीमत पर बिक्री होने तथा मार्जिन का निर्धारण किस आधार पर किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए इस आशय के निवेदनों को कि केवल उन महीनों के लिए तुलना की जानी चाहिए जिनके दौरान घरेलू उद्योग ने उत्पादन किया है, केवल अंतरभूत कारकों के कारण मात्रात्मक क्षति हुई है, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए विवरणों पर निष्कर्ष नहीं देने चाहिए, एन एस आर पहुंच मूल्य से अधिक है, इस जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए जैसा कि पहले के फोटोग्राफिक पेपर के मामले में घरेलू उद्योग रूग्ण था, मूल सीमाशुल्क के आधार पर विभिन्न दरों के कारण आयातों का संचयन संभव नहीं है, माननीय सीईएसटीएटी ने कारणात्मक संपर्क का मूल्यांकन नहीं किए जाने के कारण पहले इसी प्रकार के मामले के निर्णयों को रद्द कर दिया है, आयात के प्रमुख समय पर विचार नहीं किया गया है और इसलिए आयात और उत्पादन के सह-संबंध का गलत प्रतिपादन किया गया है, प्राधिकारी ने नोट कर लिया है। उनका यह निर्णय है कि जैसा कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहले अनुरोध किया गया है, जांच अवधि में माहवार विश्लेषण किया जाए तथा लिए गए मामले की प्रकृति पर विचार किया जाए। तथापि, कीमत की क्षति की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए कारणात्मक संबंधों के विश्लेषण करने के लिए माहवार प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है, जैसा कि सभी मामलों में किया गया है, इस निमित्त समग्र जांच अवधि पर विचार किया गया है। घरेलू उत्पादन के लिए प्रमुख समय को समान महत्ता दी जाती है और इसलिए समग्र मूल्यांकन करने के लिए समग्र जांच अवधि पर विचार किया जाता है ताकि प्रमुख समय के मुद्दों की औसत निकाली जा सके, जैसा कि पाटनरोधी जांच में सुसंगत रूप से किया जाता है।

119. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एममात्र घरेलू उत्पादक के रूप में मै0 एपीएल ने हालांकि घरेलू उत्पादकों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की है, फिर भी वह आयातों से विशेषकर संबद्ध देशों से पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा का सामना करता है। प्राधिकारी का यह भी निर्णय है कि संबद्ध देशों से आयातों द्वारा मांग और पूर्ति में व्याप्त अंतर को उचित कीमतों पर दूर करना आवश्यक है न कि अनुचित पाटित कीमतों पर, जिसका निदान इस निर्णय में किया जा रहा है।

120. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण कोई कीमत क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी का यह निर्णय है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, सत्यापित आंकड़ों को अपनाया गया है तथा पाटन की सीमा का मूल्यांकन का किसी भी सहयोगी अथवा असहयोगी निर्यातक द्वारा प्रतिवाद नहीं किया गया है। सहयोगी निर्यातकों के मामलों में एनआईपी और पहुंच मूल्य की तुलना, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यात कीमत के आंकड़ों के आधार पर की गई है जिसकी विधिवत जांच की गई थी और जिन्हें एक निर्यातक की सत्यापन रिपोर्ट और प्रकटन के माध्यम से निर्यातकों को प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, पहुंच मूल्य का आकलन ऐसे आंकड़ों पर किया गया है तथा क्षति के मार्जिन का मूल्यांकन समग्र जांच अवधि में एनआईपी के साथ उपयुक्त तुलना करने के बाद किया गया है। पाटित आयातों के पहुंच मूल्य तथा एनआईपी की कीमत कटौती द्वारा क्षति कीमत के प्रभाव को अपनाकर के क्षति मार्जिन का आकलन किया गया है।

121. हालांकि कीमत के प्रभाव से क्षति हुई है, जांच अवधि में इसकी मात्रा में विस्तार कम हुआ है क्योंकि अन्य अंतरभूत कारकों ने जांच अवधि में क्षति की मात्रा को आच्छादित कर दिया है। घरेलू उद्योग अभी भी उत्पादन कर रहा है और वह बंद नहीं है और उसने पाटन के कारण होने वाली क्षति को दूर करने का अनुरोध किया है।
122. प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों और अन्य निवेदनों का विश्लेषण किया है ताकि पाटन से भिन्न कारकों का निदान भी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए माननीय सी ई एस टी ए टी के पहले लिए गए निर्णयों के हवाले को ध्यान में रखकर किया जा सके।
123. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त डी जी सी आई एंड एस के कारोबार- वार आंकड़ों को सार्वजनिक फाइल में रखा गया है और उन्हें विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया है।
124. जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है, क्षति अवधि के दौरान उच्चतर क्षमता उपयोग, खपत के श्रेष्ठ प्राप्त मानदंडों आदि पर एनआईपी का निर्धारण करने के लिए सुसंगत क्रिया प्रणाली को अपनाकर समग्र जांच अवधि के लिए एन आई पी का निर्धारण किया गया है। निष्क्रिय समय के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के संबंध में प्राधिकारी का यह निर्णय है कि उन्होंने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार एनआईपी का मूल्यांकन करने के लिए सुसंगत पद्धति को अपनाया है।
125. एन आई पी में शामिल करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार भाड़े की लागत को उचित नहीं समझा गया है क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति अथवा तैयार माल के निकटस्थ यूनिट की अवस्थिति के संबंध में निर्णय, ग्राहकों से संबंधित प्रमुख निर्णय उनकी स्थापना के समय लिए जाते हैं तथा पाटनरोधी जांच में क्षति का मूल्यांकन करने के लिए एन आई पी के लिए वस्तुगत वस्तु की तुलना पहुंच मूल्य के साथ करना आवश्यक होता है और उन्हें एक यूनिट की अवस्थिति के इतिहास को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मामले के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जिसमें कच्चे माल के स्रोतों और ग्राहकों की अवस्थिति के साथ सत्व का दूसरे सत्व के साथ अंतर हो सकता है जोकि विविधीकृत हो सकते हैं और समय के साथ-साथ उनकी गतिशीलता में परिवर्तन हो सकता है।
126. ऋण की लागत के समायोजन के माध्यम से पहुंच मूल्य में परिवर्तन करने के बारे में प्राधिकारी का यह निर्णय है कि निर्णय की लागत का समायोजन पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, पहुंच मूल्य में ऋण लागत का समायोजन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है जैसाकि प्रकटन विवरण में बताया गया है तथा अन्य कारकों जैसे कि भाड़ा, प्राथमिक सीमाशुल्क अथवा निर्यातकों द्वारा एजेंटों को अदा किए गए कमीशन के लिए भी समायोजन करने आवश्यक होंगे जोकि व्यवसाय की पद्धतियों और देशों के बीच हुए द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर निर्भर होंगे।
127. ऐसे निवेदनों के संबंध में कि प्राधिकारी ने समग्र क्षति प्राचलों पर विचार नहीं किया है, प्राधिकारी का यह निर्णय है कि क्षति के अंतर्गत सभी संबद्ध क्षति प्राचलों का विश्लेषण किया गया है तथा कारणात्मक संबंधों की जांच की गई है ताकि जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, वहां पाटन के कारण पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव पर निर्णय लिया जा सके।
128. प्राधिकारी लक्ष्मी कुमारन और श्रीधरन एटॉर्नीज के ऐसे निवेदनों को नोट करते हैं कि मै0 पीसीडी और मै0 बीएसएसएफ पैट्रोनास दोनों के लिए समान दर पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाए। प्राधिकारी का यह निर्णय है कि मै0 पीसीडी और मै0 बीएसएसएफ पैट्रोनास द्वारा अपनाए गए निर्यात के माध्यम भिन्न हैं। चूंकि एक मूल्य श्रृंखला माध्यम के विशिष्ट यह मूल्यांकन किया गया है तथा संबंधित पक्षकारों के बीच कारोबार पर इसकी पुष्टि होने के बाद विचार किया गया है कि वे निकटस्थ स्थित हैं, मलेशिया से इन दोनों उत्पादकों/निर्यातकों को मिलाने की आवश्यकता उपयुक्त नहीं प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त, सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यात के संबंधित माध्यमों से भिन्न माध्यमों द्वारा किए गए ऐसे निर्यातों पर जिनकी जांच कर ली गई है और जिन्हें मौजूदा जांच में पृथक पाटन मार्जिन स्वीकृत करने और क्षति मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए विचारा किया गया है, पर बाकी/असहयोगी श्रेणी के अंतर्गत पाटन शुल्क लगेगा।
129. शुल्क के रूप और तरीके के संबंध में प्राधिकारी की यह अवधारणा है कि पाटनरोधी उपायों के क्रियान्वयन में प्रभावकारिता के अनुभव को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर में नियत शुल्क के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सुसंगत रूप से सिफारिश की जाती रही है। इसलिए प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि संयुक्त अमरीकी डॉलर के रूप में कमतर शुल्क नियम के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। शुल्क तालिका

को गहन बनाने के लिए घरेलू उद्योग के निवेदन को नोट करते हुए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए पाद टिप्पणी में यह उल्लेख किया है कि सीमाशुल्क शीर्ष निर्देशात्मक है।

सिफारिशें

130. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यात की गयी संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत कम होती है, इस प्रकार इसका पाटन होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबंध देशों से पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। इसीलिए प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नीचे दी गयी “शुल्क सारणी” में बताए गए रूप और तरीके से करने पर विचार करते हैं। तथापि जब भी कभी किसी उत्पादक/निर्यातक के लिए क्षति मार्जिन नकारात्मक हो तो इसको क्षति विश्लेषण संबंधी पहले पैराग्राफों में विश्लेषण में इस प्रकार दर्शाया गया है।

131. प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन के कम मार्जिन और क्षति के मार्जिन के बराबर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं जिससे पहले घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार नीचे दी गयी सारणी के कॉलम 8 में बतायी गयी राशि के बराबर संबद्ध देशों के मूल की अथवा निर्यात की गयी संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा पाटन रोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क सारणी

क्र.सं.	*उप शीर्षक / टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	ओक्सि या जीएम बीएच	पैट्रोकेम मिडिल ईस्ट एफजैडई, दुबई	शून्य	मी. ट.	अम. डॉ.
2)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	ओक्सि या जीएम बीएच	आईसीसी कैमिकल्स, यूएसए	शून्य	मी. ट.	अम. डॉ.
3)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	उपरोक्त 1) और 2) के अलावा कोई संयोजन		46.27	मी. ट.	अम. डॉ.
4)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	कोई	46.27	मी. ट.	अम. डॉ.

		अल्कोहल							
5)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	कोई	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	46.27	मी. ट.	अम. डॉ.
6)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	मलेशिया	मलेशिया	मै. पेट्रोनास कैमिक ल्स डेरिवेटी वस एसडीए न बीएचडी	मै. पेट्रोनास कैमिकल्स मार्केटिंग एसडीएन बीएचडी	51.42	मी. ट.	अम. डॉ.
7)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	मलेशिया	मलेशिया	बीएसए एफ पेट्रोनास	बीएसए फ पेट्रोनास	26.59	मी. ट.	अम. डॉ.
8)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	मलेशिया	मलेशिया	उपरोक्त 6) तथा 7) के अलावा कोई संयोजन		149.31	मी. ट.	अम. डॉ.
9)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	मलेशिया	कोई	कोई	कोई	149.31	मी. ट.	अम. डॉ.
10)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	कोई	मलेशिया	कोई	कोई	149.31	मी. ट.	अम. डॉ.
11)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	सिंगापुर	सिंगापुर	कोई	कोई	35.66	मी. ट.	अम. डॉ.

12)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	सिंगापुर	कोई	कोई	कोई	35.66	मी. ट.	अम. डॉ.
13)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	कोई	सिंगापुर	कोई	कोई	35.66	मी. ट.	अम. डॉ.
14)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	साउथ अफ्रीका	साउथ अफ्रीका	कोई	कोई	13.24	मी. ट.	अम. डॉ.
15)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	साउथ अफ्रीका	कोई	कोई	कोई	13.24	मी. ट.	अम. डॉ.
16)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	कोई	साउथ अफ्रीका	कोई	कोई	13.24	मी. ट.	अम. डॉ.
17)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	यूएसए	यूएसए	कोई	कोई	24.16	मी.ट .	अम. डॉ.
18)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	यूएसए	कोई	कोई	कोई	24.16	मी.ट .	अम. डॉ.
19)	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा “एन-बूटील अल्कोहल”	कोई	यूएसए	कोई	कोई	24.16	मी.ट .	अम. डॉ.

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और इसके कार्यक्षेत्र पर यह बाध्यकारी नहीं है।

132. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथानिर्धारित मूल्यांकन करने योग्य कीमत होगी तथा इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9 क के अधीन शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल होते हैं।

आगे की प्रक्रिया :

133. इस अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध एक अपील सीमा शुल्क टैरिफ नियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, तथा सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General Of Anti-Dumping And Allied Duties)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2016

FINAL FINDINGS

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol” originating in or exported from European Union (EU), Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America (USA).

F. No. 14/4/2013-DGAD.— Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules).

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed:

- a. The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), under the above Rules, received a written application from The Andhra Petrochemicals Ltd. (‘APL’) (hereinafter referred to as the “petitioner”) as domestic industry of the subject goods, alleging dumping of Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “NBA”) originating in or exported from European Union (EU), Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America (USA) (hereinafter referred to as the “subject countries”) and resultant injury to domestic industry and requesting recommendations for imposition of anti dumping duty on imports of the product under consideration from the subject countries.
- b. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petitioner filed an updated petition, which was considered by the Authority for initiation of investigations. The application was, therefore, considered as duly documented.
- c. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries.
- d. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.

- e. The Authority issued a public notice dated 20th November, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods from the subject countries.
- f. The Authority forwarded a copy of the public notice to all known exporters (whose details were made available by the Petitioner) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
- g. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.
- h. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- i. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Sasol Middle East FZCO 1 Sturdee Avenue Rosebank PO. Box : 5486 Johannesburg South Africa - 2000	Oxeno-Degussa Huls Group Degussa Huls Group Oxeno Olefinchemie GmbH D 45764 Mari Paul Baumann Strabe 1, Germany
Dow Europe GMBH The Dow Chemical Co. Texas City, Texas, USA	Oxea GmbH 1505, West LBJ Freeway Suite 400R Dallas Tx US 75234
EIF Atochem S.A 4, Cours Michelet 92091 Paris La Defence Cedex, France	Solvents Documentation Syntheses S.A B.P. 4, 13124 Peypin
ZAK Zaklely Azotowe Keozieryzn S.A Skr. Poizwota 163 47220 Kedzieegyn Kozle Poland	Eastman Chemical Texas City Operations PO Box 471 Texas City, TX 77592 USA
ICC Chemical Corporation 460, Park Avenue New York – 10022, USA	Perstorp Oxo AB Stenungsund Sanden 44495, Odsmal, Sweden
Eastman Chemical Asia Pacific Private Limited, Regional Office 9 North Buona Vista Drive # 05-01 The Metropolis Tower 1 Singapore 138588	Eastman Chemical Singapore Private Limited, Manufacturing Site 50 Sakra Avenue Jurong Island Singapore 627891
Arkema Headquarters 420 Rue Estienne D'Orves 92705 Colombes, Cedex, France	

- j. In response to the initiation notification, the following exporters/producers from the subject countries have responded:
- PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn Bhd, Malaysia or “PCD”
 - PETRONAS Chemicals Marketing Sdn Bhd, Malaysia or “PCM”
 - PCM Chemicals India Pvt. Ltd.
 - BASF PETRONAS Chemicals SDN Bhd, Malaysia OR “BASF”

- v. Oxea GmbH , EU
- vi. Petrochem Middle East FZE, Dubai
- vii. ICC Chemical Corporation, USA
- viii. Oxea Corporation, USA
- k. All the above producers/ exporters filed questionnaire response except M/s Oxea Corporation, USA whose submissions are mentioned later.
- l. Questionnaire was sent to the following known importers/users/associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6 (4) of the AD Rules:

K L J Group of Cos. H/O: KLJ House, 63, Rama Marg, Najafgarh Road New - Delhi- 110 015	PCL Group 703, 7th Floor, DLF Tower - B, District Centre Jasola, New Delhi - 110044
API Inds. Corporation NK Polymers & additives Mfg Co. 36/2 Ringanwada, Near Somnath Indl. Estate Daman - 396201 (UT)	Rachna Plasticizers Plot No: 116 & 117, Piparia Indl. Estate UT of D & NH, Silvassa, Vapi - Gujarat
Visen Industries Ltd. 102/A, Virwani Industrial Estate Goregaon (E) Mumbai- 4000 063	Micro Inks Ltd. Plot No: 2801/3A & 3, 2082/B, 2083/2, 2084 & 2085-25, Survey No: 285/1, GIDC 3rd Phase, Vapi, Valsad, Gujarat
Alkyl Amines Chemicals Ltd. Plot No. 67, MIDC Patal Ganga Indl. Area Village : Kaire, Tal : Khalapur Dist - Raigad	Lalitha Chem Inds. Pvt. Ltd. Unit No: 2, Plot No: 32B, Nanji Indl. Area, Survey No:200/1/2, Village : Kharadi, Pune
Deepak Nitrite Ltd. Enterprise Centre, 301, III Floor Besides Hotel Orchid, Vileparle (E) Mumbai- 4000099	Payal Polyplast Pvt. Ltd. E-24, Netaji Subhash Marg Darya Gunj New Delhi - 110002
Dorf Ketel Speciality Pvt. Ltd. Intec. Polymer - Division 1 Dorf Ketel Tower, D'Monte Lane, Orlm Malad (W), Mumbai- 400 064	Anushakti Chemical & Drugs Ltd. 71, Udyog Kshetra, 2nd Floor Mulund Goregaon Link Road, Mulund (W), Mumbai- 400080
C J Shah & Co. 105, Bajaj Bhavan, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai- 400021	Ramniklal S. Gosalia & Co. National House, 608, B.J. Marg, Jacob Circle, Mumbai- 400011
Haresh Petrochem Pvt. Ltd. 404/405, Acme Plaza, Andheri Kurla Road,	Hazel Mercantile Ltd. 3/10, Kapadia Chambers 599, J.S.S. Road,

Opp: Sangam Theatre, Andheri (E), Mumbai-400059	Marine Lines Mumbai- 4000 02
Kundan Rice Mills Ltd. D-16, City Chambers, Prashant Vihar, Delhi - 110085	Hazel Mercantile Ltd. 3/10, Kapadia Chambers 599, J.S.S. Road, Marine Lines Mumbai- 4000 02
Asian Solvochem Pvt. Ltd. Windsor, 2nd Floor, CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai- 400098	KLJ Resources Ltd. 76, Juhu Shopping Centre, 2nd Floor Gulmohar Cross, 9th Road, Juhu Scheme Mumbai- 400049
Petrochem Middle East (India) Pvt. Ltd. 201, Business Square, B-Wing, Andheri Kurla Road, Opp: Apple- Heritage, Andheri (E), Mumbai- 400093	Pon Pure Chem (P) Ltd. No: 32, H- Block, 15th Main Road, Anna Nagar, Chennai- 600 040
Yog International Pvt. Ltd. Khasra No. 36/8 Mundka Village Delhi- 110041	Daga Global Chemicals Ltd. 302, Sakar -III, Opp Old High Court Navrangapura, Ahmedabad- 380009
Apra Enterprises Plot No:176, 2nd Floor Dr. Keni House Sion (W), Mumbai- 400022	Overseas Polymer Pvt. Ltd. Vinmar House, A-41 MIDC Road No.2 Andheri (E), Mumbai- 400 093
Ketul Chem Pvt. Ltd. Western Edge-1, Kanakia Spaces, Unit No:403, Above Metro Shopping Mall, Borivali (E), Mumbai- 400 066	Balmukund Chemicals Pvt. Ltd. Plot No: 4765, GIDC Estate Nr. Ficom Char Rasta, Ankleshwar -393002
Paras Dyes & Chemicals B-82, Defence Colony, New Delhi-110024	Jagriti Plastics Ltd 107,M.G. House , Community Centre, Wazirpur Indl. Area, Delhi-110052
Surabhi Enterprises Pvt Ltd Head Office 4/1 Camac Street, Ground Floor, Kolkata - 700 016	Sanjay Chemicals (India) Pvt. Ltd. 5th Floor, Kanmoor House 281/287 Narshi Natha Street Masjid, Mumbai - 400 009 (Maharashtra)
Supreme India International C-11, Jeevan Jyot, 18/20, Cawasji Patel Street, Fort, Mumbai - 400 001	Buneesha Chem Pvt. Ltd. 203 / 204, Shiv Chambers, Plot No.21, A-Wing Sector - 11, Next to MTNL Bldg. CBD Belapur (E), Navi Mumbai
Ankita Chemical Corporation	Ketul Chem Pvt. Ltd.

No. 7, Sarwan Bhawan, Nai Gaum Cross Road, Dadar East Mumbai - 400 014	403, WESTERN EDGE, METRO STORE, BORIVALI (E), Mumbai – 400092
Nutan Chemicals J - 37, M. I. D. C., Bhosari, Pune - 411026, Maharashtra, India	Triveni Aromatics And Perfumery Private Limited 136, Pancharatna Char Rasta, G. I. D. C., Vapi - 386195, Gujarat
A.B. Enterprises 202, Shradanand Building 272/ 274, Samuel Street, Mumbai - 400 003	Plastichem Inds. Corporation A - 2001, Runwal Pride, 20th Floor, L. B. S. Road, Mulund West, Mumbai - 400 080
Tulsi Chemicals 3, Old No.2, Raja Annamalai Road 1st Floor, Puraswalkam Chennai - 600 084	Dev Chemicals 1-89, Adhyapak Nagar Nangloi Delhi - 110 041
Indian Plasticizers Manufacturers Association KLJ House, 63, Rama Marg, Nazafgarh Road, New Delhi 110015	

m. Following importers/consumers filed questionnaire responses.

- i. PCM Chemicals India Pvt. Ltd.,
- ii. Payal Petrochem Pvt. Ltd.,
- iii. Rachna Plasticizers,
- iv. KLJ Plasticizers Ltd.,
- v. KLJ Resources Ltd.,
- vi. Payal Polyplast Pvt. Ltd.

Further a number of other interested parties have offered comments and submission with regard to the present investigation, which have been appropriately taken into account. The said interested parties are as follows:

- i. Evonik Industries
- ii. Lubrizol India Pvt. Ltd.
- iii. Barkur Surfactants Pvt. Ltd., Mumbai
- iv. Unitop Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai
- v. Advanced Microdevices Pvt. Ltd.
- vi. Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd.

n. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by all interested parties. The public file was inspected by a number of interested parties a number of times. Interested parties, who requested inspection and copies of the documents from the public file, were provided with the same.

- o. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis, which was made available through public file.
- p. Further information was sought from the petitioner and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- q. On the request of the Authority, the Central Government extended the time for completion of the Investigation up to 19th February, 2016, in terms of Rule 17 of the AD Rules.
- r. A spot verification was also conducted at the premises of the following exporters:
- PETRONAS Chemicals Derivatives SdnBhd, Malaysia or PCD (on 8th December, 2015)
 - PETRONAS Chemicals Marketing SdnBhd, Malaysia or PCM (on 9th December, 2015)
 - BASF PETRONAS Chemicals SDN Bhd, Malaysia (on 7th December, 2015)
 - Oxea GmbH, EU (on 2nd- 3rd November, 2015)
- s. The above exporters were issued a report of the verification conducted. Comments offered by the exporters have further been taken into account in this Findings.
- t. The Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') considering the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- u. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2013 to 30th June 2014 (15 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI.
- v. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 6th November 2015. The parties, who presented their views in oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- w. Exchange rate for conversion of US\$ to Rs. is considered for the POI as Rs.60.77 as per customs data.
- x. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 8th February, 2016 to the known interested parties and comments received on the same, to the extent considered relevant by the Authority, has been considered in this final finding.
- y. In this Final Findings, "***" represents information furnished by the interested parties on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

2. The product under consideration in the present investigation is "Normal Butanol" or "N-Butyl Alcohol".

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

3. The Designated Authority should examine the petitioner's assertions that the goods produced by it and the product under consideration are like and technically and commercially substitutable.

Views of the Domestic Industry

4. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration: -

a) The product under consideration in the present petition is n-Butanol also known as n-butyl alcohol or normal butanol. Normal butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C_4H_9OH . It is a clear, mobile, neutral liquid with a characteristic odor. It is miscible with all common solvents but it is only sparingly soluble in water. NBA occurs naturally as a minor product of the fermentation of sugars and other carbohydrates, and is present in many foods and beverages.

b) Normal butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of N-Butanol is converted into derivatives for use as solvents in coating industries.

Examination by the Authority

5. The product under consideration in the present investigation is "Normal Butanol". Normal Butanol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. Normal Butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C_4H_9OH .

6. Normal Butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of Normal Butanol is converted into derivatives for use as solvent in coating industries and printing inks. Normal Butanol also finds application as extractant in production of drugs and natural substances, additive in polishes and cleaners, solubilizer in the textile industry, additive in deicing fluids, anti-icing additive in gasoline, humectant for cellulose nitrate, feedstock in the production of glycol ethers and flotation aids (Butyl Xanthate) and as starting material for the production of Butyl mono Carboxylates, Butyl Acetate, Butyl butyrate.

7. The product is classified under Customs Tariff heading No. 29051300. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

8. Rule 2(d) relating to the definition of "like article" specifies that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation, or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the article under investigation.

9. The petitioner has claimed that the subject goods, which are exported from subject countries into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Normal Butanol produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules. No specific instances of differences in technical characteristics which affect substitutability of domestic and imported subject goods have been substantiated which warrants a detailed examination. The issue of form of packaging has been dealt at appropriate places. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the petitioner in India are treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

10. The Authority notes that the Petitioner is producing NBA, EHA and IBA. EHA and NBA are produced in two different plants since 2011.

11. The Authority therefore holds that the product manufactured by the petitioner constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject countries.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

13. M/s PCD, PCM and PCM Chemicals India Pvt. Ltd. have contended that there are many other producers of like article namely, M/s Galaxy Chemicals, M/s Hemanshu Chemicals and Meru Chem Pvt. Ltd. The applicant has not mentioned the names of these producers at all.

14. The petitioner should not be considered as ‘domestic industry’ to impose anti dumping duties on PUC as the petitioner has never been a regular producer of subject goods.

Views of the Domestic Industry

15. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration: -

- a) The petition has been filed by M/s The Andhra Petrochemicals Limited as domestic industry.
- b) The Petitioner is the sole producer of the subject goods in India.
- c) As regards the contention of other parties, the petitioner has collected information and submitted the same to the Authority showing that these companies are not manufacturing product under consideration.
- d) Petitioner has neither imported the subject goods nor is related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration in the subject countries.
- e) The petitioner is eligible to constitute domestic industry as per Rule 2(b).

Examination by the Authority

16. The Authority notes that the application was filed by M/s The Andhra Petrochemicals Limited as domestic industry. The Petitioner is the sole producer of the subject goods in India. Petitioner has not imported the subject goods during the POI. Further, petitioner is not related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration in the subject countries.

17. As regards the contention that M/s Galaxy Chemicals, M/s Hemanshu Chemicals and Meru Chem Pvt. Ltd. are also producers of the product under consideration, the Authority notes that any evidence establishing that these parties are engaged in production of the product under consideration has not been provided. The clarificatory information provided by the Petitioner showed a written communication from these parties to the Petitioner stating therein as follows:

- i. Meru Chem Pvt. Ltd. stated that they are only trader and supplier of chemicals and solvent; they do not produce NBA or any other chemicals or solvent;
- ii. Hemanshu Chemicals stated that they are not producing the product, but are trading in the product;
- iii. Galaxy Chemicals stated they are not a user of the product and are trading in NBA and other solvent.

18. It is also noted that production of the product under consideration involves significant capital investment and therefore, the petitioner would certainly not have been aware of the existence of another producer in the Country. The communications from the parties clarifies that they are traders and not domestic producers of the product under consideration (PUC).

19. In view of the information on record, after due examination and considering the legal provisions, the Authority holds that the petitioner satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules, i.e. the requirement of standing under the Rules. The petitioner is therefore held to be constituting domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

D. DUMPING MARGIN

20. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under subsection (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Views of the Domestic Industry

21. The following are the submissions made by the petitioner in respect of normal value:

- (a) The following can form the basis for determination of normal value in the exporting countries:
 - (i) The price of the like article in the domestic market of the exporting country in the ordinary course of trade,
 - (ii) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country,
 - (iii) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits.
- (b) Efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of each of the subject countries. Efforts were also made to get price lists or quotations of producers of subject goods in the country. However, the petitioner has not been able to get any reliable information of prices prevailing in the domestic market of any of the subject countries.
- (c) The petitioner has claimed determination of normal value using constructed value approach. The petitioner has adopted power prices prevailing in the subject countries to construct the cost of intermediates – Syngas and Butraldehyde and the final product – Normal Butanol. The petitioner has claimed their consumption factors for raw material and utility to be adopted.

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

22. The exporters, importers, consumers and other interested parties made the following submissions:

- The petitioner's approach of constructing Normal Value is erroneous and based on doubtful resources and should therefore be rejected.

- The petitioner has calculated normal value on the basis of inflated cost and has wrongly claimed confidentiality over the constructed normal value. In this regard, *Birla Ericsson Opticals vs Designated Authority* 2004(167) E.L.T. 163 (Tri. - Del.) was cited.
- The Authority should disregard constructed normal value for Malaysia as determined by Petitioner and determine normal value based on Respondents- exporter's data.
- There is no dumping of the subject goods from Malaysia, as Respondents' prices are benchmarked based on ICIS prices. The import prices had in fact increased during the injury analysis period.

Examination by the Authority

23. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following parties have filed exporter questionnaire responses:

- PETRONAS Chemicals Derivatives SdnBhd, Malaysia or PCD
- PETRONAS Chemicals Marketing SdnBhd, Malaysia or PCM
- BASF PETRONAS Chemicals SDN Bhd, Malaysia or BASF
- Oxea GmbH , EU
- Petrochem Middle East FZE, Dubai
- ICC Chemical Corporation, USA
- Oxea Corporation, USA (made only submissions of no exports during POI).

I. MALAYSIA

a. Cooperative producers/ exporters

M/s PETRONAS Chemicals Derivatives SdnBhd, Malaysia or PCD

24. M/s PCD, the producer of the subject goods, has provided questionnaire response as a producer. Its related exporter i.e. M/s PCM and related importer i.e. M/s PCM Chemicals India Pvt. Ltd., have also filed questionnaire responses. The submissions are as under:

- PCD is a wholly-owned subsidiary of PETRONAS Chemicals Group Berhard (PCGB). PCGB is 64.4% owned by Petroliaam Nasional Berhard (PETRONAS) and 35.6% owned by public and other investors.
- The key raw materials for manufacturing the product are propylene and syngas/ oxogas.
- PCD procures both the raw materials from its related company at market price.
- By product generated during the process is Butanol off gas. The amount realized from the sales of Butanol off gas is taken as a credit while determining the production cost of the product concerned.
- Normal value is claimed based on sales in home market.

25. The Authority notes that the domestic sales of the subject goods in POI made by M/s PCD is ***MT. The Authority verified the questionnaire response filed by the producer and also its associated exporter, i.e. M/s PCM. The ordinary course of trade (80:20) test conducted on the domestic sales of M/s PCD indicates that **%, i.e. *** MT appropriately of the domestic sales are in the ordinary course of trade. The Normal Value of the subject goods in POI is therefore determined by referencing the transactions in the ordinary course of trade and allowing adjustments on pipeline charges (** \$/MT), inland transport (** \$/MT), credit cost (** \$/MT), packing (** \$/MT), with a total of ** \$/MT. The weighted average Normal Value is thus considered as ** \$/MT. The domestic sales of M/s PCD have been made through M/s PCM, a related entity of M/s PCD. The Authority further verified that M/s PCM has sold the

goods procured from M/s PCD to unrelated users in the domestic market with a further markup thus establishing an arm's length sales in ordinary course of trade.

M/s PETRONAS Chemicals Marketing SdnBhd, Malaysia or PCM

26. The exporter has submitted, inter-alia, as follows:

- a) PCM is a wholly-owned subsidiary of PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCGB).
- b) Sales to India are made from purchases made from PETRONAS Chemical Derivatives SdnBhd (wholly owned subsidiary of PCGB)
- c) In exceptional cases, sales to India were also from purchases made from BASF PETRONAS Chemicals SdnBhd (joint venture between BASF and PCGB)
- d) PCM Chemicals India Pvt. Ltd. is the related importer and trader in India.
- e) Sales to India are made to PCM Chemicals India and other unrelated customers.
- f) Normal value is claimed based on sales in home market.

27. The Authority notes that M/s PCM has sold the subject goods during POI to India with M/s PCM Chemicals India Pvt. Ltd. facilitating customer identification. The Authority has also correlated the export price of M/s PCM of goods produced by M/s PCD with the sales price of M/s PCD to M/s PCM. The weighted average CIF price is determined as *** \$/MT. The Authority allows adjustments on ocean freight, credit cost and handling to an extent of *** \$/MT, *** \$/MT and *** \$/MT respectively, coming to a total of *** \$/MT. The ex-factory export price is thus determined as *** \$/MT. The dumping margin is thus determined as *** \$/MT (10-15 %).

28. The weighted average landed value of imports has further been determined on the basis of the verified weighted average CIF prices of subject goods produced by M/s PCD and exported by M/s PCM to India by adding 1% landing charges and applicable customs duties i.e. basic custom duty and cess.

M/s PCM Chemicals India Pvt. Ltd.

29. The above related importer of the subject goods has filed questionnaire response completing the value chain and has submitted as under:

- a) PCM Chemicals India was acting as an importer and trader of the subject goods in the POI. However, PCM Chemicals India is an inactive company now.
- b) PCM Chemicals India was previously known as MITCO Labuan (India) Private Limited.
- c) MITCO Labuan Co. Ltd. and PETRONAS Chemicals Marketing Sdn Bhd. are the two shareholders of PCM Chemicals India. MITCO Labuan Co. Ltd. in turn is wholly owned by Petrolia Nasional Berhad ("PETRONAS").
- d) The Authority notes that the two transactions sold by M/s PCM to M/s PCM Chemicals India Pvt. Ltd. as high sea sales were further sold to end users with a mark up of *** %.

BASF PETRONAS

30. Normal Value: M/s BASF had made domestic sales to M/s PCM of *** MT at the rate of *** \$/MT. There are determined in the ordinary course of trade when compared with the weighted average ex-factory cost of production as verified on site. Adjustments on domestic sales are allowed on handling, others and credit cost to an extent of *** \$/MT, *** \$/MT and *** \$/MT, coming to a total of *** \$/MT. The weighted average **normal value** for M/s BASF is thus considered as *** \$/MT.

31. Export Price: M/s BASF exported a total of *** MT of the subject goods to India in POI directly at a weighted average CIF of *** \$/MT. Based on the on- site exporter verification, the Authority considers adjustments on

commissions (***/MT), handling (***/MT), overseas freight (***/MT), overseas insurance (***/MT), others (***/MT) and credit cost(***/MT), with a total of ***/MT. The ex- factory export price is thus considered as ***/MT. The dumping margin for M/s BASF is therefore determined to be as***/MT (0-5 %). The landed value has further been determined by adding 1% landing charges to CIF and applicable customs duties.

b. Non cooperative producers/ exporters:

32. For all the non- cooperating producers and exporters in Malaysia, the highest normal value of the cooperative exporters is considered as their Normal Value. For ex- factory export price, the lowest export price of cooperative exporters with adjustments as adopted in the case of cooperative exporters is taken into consideration. For the ex- factory export price thus, the CIF price of *** \$/MT with adjustments to an extent of ***/MT has been taken into consideration. Accordingly, the normal value and the ex- factory export price for non-cooperative producers/ exporters from Malaysia are evaluated as *** \$/MT and ***/MT respectively. The dumping margin is thus determined as *** \$/MT (15-20%).

33. The **landed value** for non- cooperative producers/ exporters from Malaysia has been adopted on the basis of the lowest export price (CIF), with 1% landing charges and applicable customs duty i.e. basic custom duty and cess.

DUMPING MARGIN

Sr. No.	Producer	Exporter	NV (USD/MT)	Ex-factory EP (USD/MT)	DM (USD/MT)	DM%	DM Range (%)
1)	PCD	PCM	***	***	***	***	10-15
2)	BASF PETRONAS	BASF PETRONAS	***	***	***	***	0-5
3)	Non cooperative producers/exporters and any combinations other than 1) and 2) above.		***	***	***	***	15-20

II. EUROPEAN UNION

a. Cooperative producers/ exporters

OXEA GmbH, Germany, EU

34. The above producer has submitted, inter-alia, as follows

- The raw materials used in manufacture of n-butanol are n-Butyraldehyde and hydrogen.
- The normal value has been claimed based on its sales in EU.
- The adjustments have been claimed on inland freight, inland insurance handling, credit and interest.
- The exports to India in POI have been made through M/s Petrochem Middle East, Dubai and M/s ICC Chemicals, USA.

35. The Authority notes that M/s Oxea GmbH, a producer of the subject goods in EU sold a total of ***MT of the subject goods in their domestic market. The ordinary course of trade (80:20) test on the domestic sales referencing the verified ex-factory cost of production in POI indicates that more than 99% of the domestic sales of M/s Oxea GmbH

were in the ordinary course of trade. Therefore the normal value of the producer is computed as per the weighted average domestic sales price with adjustments on inland freight (***/MT), inland insurance (***/MT), handling (***/MT), credit & interest (***/MT) [total of ***/MT]. The weighted average normal value is thus determined as ***/MT.

36. Further, the producer has exported a total of ***MT of the subject goods to India in POI through M/s Petrochem Middle East, Dubai (***MT) and M/s ICC Chemicals, USA (***MT). The weighted average export price (CIF) of the quantity exported to India is computed as ***/MT. The Authority on the above export price, has allowed adjustments on inland freight (***/MT), insurance (***/MT), handling (***/MT), overseas freight (***/MT), overseas insurance (***/MT), shipping charges (***/MT) and others (***/MT), coming to a total of ***/MT. The ex-factory export price for M/s Oxea GmbH, producer is thus held to be as ***/MT with the dumping margin determined as ***/MT (15-20 %).

37. **M/s Petrochem Middle East FZE, Dubai**, the exporter has submitted, that their company is only a trading company which, procures the subject goods from producers/ exporters based in EU and resells them to India.***MT of subject goods in POI has been exported by them to India. The weighted average CIF is determined as***\$/MT.

38. **ICC Chemical Corporation, USA**, the exporter has submitted, that their company is only an exporter of the subject goods ***MT of subject goods in POI has been exported by them to India, at a weighted average CIF of ***/MT.

39. Further, the landed value for M/s Oxea GmbH has been determined by adding 1% landing charges to CIF and applicable customs duties, i.e. basic custom duty and cess.

b. NON COOPERATIVE PRODUCERS/ EXPORTERS FROM EU

40. For all other non- cooperating producers and exporters from EU, the highest domestic selling price of cooperative exporters without any adjustment is taken into consideration for the computation of NV. For the determination of ex-factory export price, the lowest export price of cooperative exporters with adjustments as noted in case of cooperative exporters is taken into consideration. The CIF price for residual exporters/ producers from EU is determined as *** \$/MT. Accordingly, the NV and the ex- factory export price are determined as ***MT and ***/MT respectively. The dumping margin is thus considered as ***/MT (30-35 %).

41. The **landed value** for non cooperative producers/ exporters from EU has been computed on the basis of the lowest export price/ CIF, with 1% landing charges and applicable customs duty i.e. basic custom duty and cess.

DUMPING MARGIN

Sr. No.	Producer	Exporter	NV (USD/MT)	EP (USD/MT)	DM (USD/MT)	DM%	DM Range
1)	Oxea GmbH	Petrochem Middle East	***	***	***	***	15-20
2)	Oxea GmbH	ICC Chemicals, USA	***	***	***	***	15-20
3)	Non cooperative producers/exporters and any		***	***	***	***	30-35

	producer/exporter other than 1) & 2) above.					
--	--	--	--	--	--	--

III. PRODUCERS/ EXPORTERS FROM USA, SINGAPORE AND SOUTH AFRICA

Oxea Corporation, USA

42. The exporter has submitted, that their company did not export the subject goods to India in the POI and, therefore, does not have a basis to participate in the instant investigation or respond to the Exporter Questionnaire. Should the anti-dumping duty be imposed, the company reserves the right to apply for a New Shipper Review.

43. The Authority notes the submissions made by M/s Oxea Corporation, USA and holds that the new shipper review request would be dealt appropriately as per the relevant ADD Rules.

44. The Authority further notes that none of the producers/ exporters from USA, Singapore and South Africa have filed questionnaire response. Thus, in the absence of any response, the Authority has constructed normal value for all the producers/ exporters from these three countries on the basis of estimates of cost of production in accordance with Section 9A(1)c read with Rule 6(8) supra.

45. The normal value has been constructed by adopting consumption norms for major raw materials including Naphtha and their prices, prevailing power price and known estimates for conversion cost during the relevant period as per best available information. Selling, general & administrative costs and reasonable profit margin has been added to the cost of production so determined so as to arrive at a constructed normal value. A number of interested parties have contended that the cost of production of the domestic industry is significantly higher due to lower production in the present POI and higher price of raw material being paid by them. It is clarified that the Authority has adopted raw material and utility cost at best consumption norms, and conversion cost of POI has been normated at highest achieved capacity utilisation during injury period. The normal value for all non- cooperative producers/exporters in each of the abovementioned three subject countries, is considered as***\$/MT.

46. Further, the Authority as per its consistent practice, adopts the weighted average export price for all the producers/exporters of the above three countries based on transaction wise DGCI&S data for POI considering adjustments on a reasonable ocean freight as evidenced (*** US\$ for USA and *** US\$ for Singapore and South Africa each), marine insurance (***% of CIF), commission (***% of FOB), bank charges (***% of FOB), port expenses (***% of FOB) and handling (***% of FOB) for each of the three countries. The **ex- factory export prices for USA, Singapore and South Africa** are thus referenced as *** \$/MT, ***\$/MT and ***\$/MT respectively.

47. Further, the transaction wise DGCI&S data has been sorted on the product under consideration and non-product under consideration for all the injury period year including POI. The non PUC entries to an extent of about 6% in POI have been filtered for the purpose of evaluating the weighted average CIF for non-cooperating producers/ exporters from above mentioned three subject countries i.e. USA, Singapore and South Africa.

48. The **Landed Value** of the subject goods in POI has been determined on the basis of the transaction wise DGCI&S data after adding 1% landing charges on CIF, basic customs duty with cess.

DUMPING MARGIN

Country	Producer	Exporter	NV	EP	DM	DM%	DM
---------	----------	----------	----	----	----	-----	----

			(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)		Range
USA	Any	Any	***	***	***	***	20-25
Singapore	Any	Any	***	***	***	***	10-15
South Africa	Any	Any	***	***	***	***	10-15

E. INJURY

Submissions made by Domestic Industry

49. The domestic industry has submitted that:

- a. Demand for the product under consideration has remained positive throughout the injury period.
- b. Imports from the subject countries have shown significant increase over the period in absolute terms as well as in relation to consumption and production of the product under consideration in India. Further, imports from the subject countries constitute almost the entire volume of imports into India.
- c. Weighted average import prices (after including basic customs duties) have been significantly below the selling prices of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting.
- d. The injury margin is significant.
- e. The landed price of imports is significantly below the cost of production of the domestic industry throughout the injury period. Imports have had significant suppressing effect on the prices of the domestic industry in the market. Whereas the cost of sales increased significantly over the injury period, the selling price could not increase to such an extent due to presence of dumped imports, thereby suffering huge losses.
- f. The domestic industry enhanced capacities in the year 2011-12 in response to increase in demand. The production of the domestic industry improved in 2011-12 and then declined. The decline in production is significant in the POI when compared to the previous year.
- g. The domestic industry was able to achieve good capacity utilization in the period 2011-12, but the same has declined significantly thereafter in 2012-13 and the POI.
- h. Loss in production in the POI is due to other factors as well. The production in the POI declined to 5,388 MT on account of non-remunerative prices for some time and shortage in the supply of raw material. Considering that the loss of production in this period is due to other factors, the petitioner has reported its performance, as it would have been, had there been no loss of production due to shortage of raw materials. For this purpose, the petitioner has excluded the idle time cost from the total cost incurred for the production of product under consideration for the purpose of working out injury caused by dumped imports. It would be seen that even if the petitioner had achieved normal production in the POI, the selling price would still have been below cost of production. The petitioner has also claimed profitability after adjusting for idle time.
- i. Domestic sales have seen a similar trend. Whereas the demand for the product has increased by 18% between 2010-11 and the POI; the sales have declined by 68% and imports from the subject countries have increased by 125% in the same period. This clearly indicates that the imports have increasingly captured the market of the domestic industry.
- j. The profits of the domestic industry have declined throughout the injury period since 2010-11. The domestic industry has been suffering losses since 2012-13, which have intensified considerably in the POI. Profitability, cash profits, profit before interest and tax and return on investment have shown a similar trend.

- k. The petitioner has segregated cost incurred on account of idle time from the total cost to assess the injury caused by dumped imports. It would be seen that even if the petitioner had been able to achieve normal production in the POI, the profitability would have severely declined as a result of intense dumping from the subject countries.
- l. Market share of the domestic industry has declined throughout the injury period whereas the market share of the dumped imports has significantly increased throughout the injury period.
- m. Domestic industry has lost substantial orders during the injury period.
- n. The employment level increased in 2012-13 and declined thereafter. Wages paid have increased up to 2011-12 and then declined over the injury period.
- o. Productivity of the domestic industry has moved in the same direction as production.
- p. There is a threat of further material injury due to significant increase in volume of imports, significant price undercutting and price suppression, increasing inventories with the domestic industry and market share of dumped imports.

Submissions made by importers, exporters, users and user associations

50. The importers, exporters, users and user associations and other interested parties have submitted as follows:

- a. There is complete absence of causal link between the alleged injury to the domestic industry and the imports of subject goods from subject countries in the present case, as can be shown below:
 - Volume effect: Raw material shortage, fire accident, cyclone Hudhud → plant shutdown → reduced production → reduced sales → reduced market share
 - Price effect: Negative price undercutting → domestic industry did not adequately increase its price in response to the increasing cost even until the POI → decline in profitability factors due to plant shutdown
- b. Plant shutdown is an important factor in a causal link analysis. On this point, *Hematite Pig Iron* case [1990 O.J. (L135) 7] and *AGFA Gevaert AG vs. Designated Authority* were cited.
- c. Petitioner has attempted to lower the landed value by deducting notional credit cost for 90 days and inflate the non-injurious price by taking into account notional credit cost for 270 days.
- d. The sole reason of injury to Petitioner is suspension of production leading to plant closure for 212 days (almost 7 months) during the POI on account of non-availability of raw materials. Injury due to such factors cannot be attributed to imports. Petitioner's annual reports also stated this aspect. The Hon'ble CESTAT in the case of *Andhra Petrochemicals Ltd. v. Designated Authority*, 2006 (201) ELT 481 (Tri.-Del.) had also relied on the annual report of the domestic industry in that case to set aside the final findings by the Authority in that case.
- e. Petitioner has reported its performance as it would have been, had there been no loss of production. This is not permitted under law. The Authority may compare the level of imports during the period when Petitioner was operational and the level of imports when Petitioner was non-operational. Also, it is not clear what is raw material price considered for determining the performance. The domestic industry has to be taken "as is" to determine injury. On this point, the cases of *Caustic Soda originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and EU (excluding France) - Final Findings* dated October 1, 2003 and the Appellate Body Report of the *Thailand – H Beams* were cited.
- f. The petitioner has calculated normal value on the basis of inflated cost and has wrongly claimed confidentiality over the constructed normal value. In this regard, *Birla Ericsson Opticals vs Designated Authority* 2004(167) E.L.T. 163 (Tri. - Del.) was cited.
- g. Even during the period when the petitioner was producing, its production was not optimum. Therefore, imports during the POI were necessitated due to lack of production by the domestic industry.
- h. Price undercutting and price underselling are actually negative, which implies absence of causal link.

- i. Adjustments for credit cost and freight cost are not permissible under Indian law. Further, customs duty should be added to assessable value and not CIF price for calculating landed value.
- j. The reason for decline in Petitioner's profitability and increase in cost are intrinsic factors, such as non-availability of raw material to the petitioner.
- k. In light of the decline in inventories during the POI in comparison to 2011-12 and 2012-13, there is no injury to the domestic industry.
- l. The Government of Malaysia's submissions on non-injurious price and injury margin made during the public hearing should be considered. During a public hearing all interested parties including governments of concerned countries have a right to raise concerns about issues that arise in an AD investigation.
- m. The contention of the petitioner that excise duty and sales tax should be added to NIP for determination of injury margin, and that CVD should also be added to import price, should be rejected as per the Authority's consistent practice.
- n. Test of cumulative examination may not be even relevant in the present case as the present case warrants termination on grounds of causal link breach of a terminal magnitude.
- o. The lower volumes of petitioner are not on account of imports, but on account of idle time caused by short supply of raw material.
- p. If AD duty is levied based on its erratic and distraught performance on account of raw material supply issue, the position of user industry would become vulnerable and uncompetitive.
- q. The submission of the petitioner that there is no concept like NIP anywhere globally is incorrect.
- r. The Authority should reject various claims of the petitioner with regard to NIP such as inclusion of taxes etc and NIP should be determined as per Annexure III to the rules.
- s. The petitioner produces three products namely -EH, N-Butanol (n-BOL) and I-Butanol (i-BOL) in a single plant. Therefore, before any assessment of injury can be tied to imports it should be examined whether the petitioner harmed himself by reducing the output on n-BOL but increasing the output of 2-EH and i-BOL.
- t. The disruption in the Propylene supply in May-June 2013 by HPCL and a shutdown of the PRU unit necessary for the production of Propylene at HPCL in August 2013 should be evaluated. In this regard, the petitioner's 30th Annual Report 2013, Director report and the rating report should also be noted and assessed.
- u. All the numbers and trends showing the (lower) performance of the Petitioner like "production", "sales volume" etc. would have to be linked and adjusted to those numbers and trends related to the lack of raw material for production of the product concerned for 212 days of the financial year 2013-14.
- v. The material injury analysis is a prospective and not a retrospective analysis.
- w. Cumulating all subject countries in the present investigation would be inappropriate due to the conditions of competition between the subject countries *inter se*. In this regard, the following investigations of DGAD were cited:
 - * *Anti-dumping investigation concerning imports of Melamine originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan*, dated June 1, 2012;
 - * *Final Findings – Anti-dumping investigations involving imports of Acetone originating in or exported from European Union, Chinese Taipei, Singapore, South Africa & USA*, dated January 4, 2008
 - * *Final Findings – Anti-dumping investigation concerning import of Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000 to 4000 from China PR, Republic of Korea, Taiwan and Brazil*, dated November 11, 2004
 - * *Final Findings – Anti-dumping investigation concerning imports of Ball Bearings (up to 50 mm bore dia) from China PR, Poland, Russia and Romania* dated March 19, 2004.

- x. By virtue of AIFTA and the India-Malaysia CECA, the applicable basic customs duty for the same subject goods is different for imports from Malaysia and Singapore on the one hand and the other target countries (EU, US, and South Africa) on the other hand.
- y. The Authority should de-cumulate the EU imports and terminate the investigation against these imports. On this point, the EU cases of *Certain tube and pipe fittings, of iron or steel, from China, Croatia and Thailand* and *Ammonium nitrate from Russia*.
- z. The landed import price from subject countries increased over the injury period, which was more than the increase in price by the Petitioner over the injury period, which clearly indicates that the suppression was not caused by imports.
- za. Dumping must not be the sole but the substantial cause of injury. On this point, the Authority's *Final Findings – Anti-Dumping Investigations concerning imports of Cathode Ray Colour Television Picture Tubes originating in or exported from Malaysia, Thailand, China PR and Korea RP* dated February 17, 2009 and *Final Findings – Sunset review of Anti-Dumping Duty imposed in respect of imports of Acetone originating in or exported from European Union, South Africa, Singapore and USA* dated December 13, 2013, were cited.
- aa. The POI cannot be extended to 15 months at this stage of the investigation. The Authority's *Final Findings – Anti-dumping investigation concerning imports of Ball Bearings (up to 50 mm bore dia) from China PR, Poland, Russia and Romania* dated March 19, 2004 was cited.
- bb. The petitioner has failed to provide DGCI&S transaction-wise import data for the period April-June 2014 and has provided only summary of the said data. The accuracy of such summarised is doubted.
- cc. The Authority is requested to examine the reasons why imports from Malaysia have occurred during the injury analysis period in light of India-Malaysia CECA, Notification No. 56/2013 dated 31 December 2013.
- dd. The petitioner did not sell the subject goods during the entire POI. In light of this, the methodology adopted for comparison should be disclosed, and a public hearing should also be granted.
- ee. The Petitioner's profits decline when it is unable to procure raw material. Further, if Petitioner could have diversified its procurement of raw material, it could have easily avoided suspension of production during the POI.
- ff. The European Commission case referred by the petitioner deals only with the question of dumping margin and not injury margin. Further, the petitioner has not provided the name of the aforementioned case.
- gg. The domestic industry pays higher price for raw material because of shortage of raw material.
- hh. The petitioner's contention that it is producing the subject goods and EHA in different plants and production of one product is not dependent on another, should be rejected.
- ii. The petitioner's contention that it has invested in technology but still its performance deteriorated should be rejected.
- jj. Fire in HPCL plant is not force majeure, petitioner could source raw material from alternative sources and the petitioner should consider importing raw materials.
- kk. The petitioner's claim on non- remunerative prices on account of dumping is untenable and attempt to misuse the remedies available under the anti-dumping scheme.
- ll. Major refiners use propylene, which is the major raw material for NBA, captive to manufacture Poly Propylene. Thus, source of raw material for NBA in India will be unavailable or less available, making it essential to import the subject goods.
- mm. The Authority is requested to review and reject the Petitioner's claim regarding downward adjustment on account of freight costs to the landed price.

- nn.* The Authority must not adjust the landed price for differences in credit costs between exporting producers and its exporters and the domestic industry.
- oo.* The Petitioner increased capacities, production and sales significantly between 2010/11 and 2011/12, before the raw material shortages started.
- pp.* Capacity utilisation has been misleadingly understated by the petitioner because the capacity should be adjusted to reflect the fact that the plant was only running for 153 days or lesser, during the 12-month period.
- qq.* The Petitioner's claims that it made investments to optimise the production process and its performance deterioration is due to the competition from allegedly dumped imports, is wrong.
- rr.* M/s. Lubrizol has stated that the conditions of sale of the product by the petitioner evidently prove that the petitioner is operating under monopolistic condition and dictating the term of sale.
- ss.* The petitioner may not have interest in supplying blended product with said goods which may force the user to find alternate source of supply of high end blended products.
- tt.* The petitioner being the sole manufacturer of said product does not inspire any confidence in its valued customer. Non-availability of the product due to shut down of their plant either due to technical or financial reasons can put the domestic users to a greater hardship and would allow the trader to dictate the price of the product to their advantage. Such situation neither benefits the petitioner nor the end user.
- rr.* For security and continuous supply of product, no anti-dumping duty should be imposed, as this will penalize the user and also impact the potential export made by them.
- ss.* Levy of Anti-Dumping Duty on goods which are important to Industry is contradictory step of government against make in India policy.
- tt.* After June 2014, when M/s Andhra Petrochemicals stopped supplying, the party was forced to procure the material at more than 1.5 times the cost from a reseller.
- uu.* After including the duties and taxes, the cost of imported material becomes more than the cost of buying from Andhra Petrochemicals.
- vv.* M/s. Advanced Microdevices (Pvt.) Ltd. have stated that Anti-dumping duty should be applied to protect Indian Industry, however, the protection should not be such that the Indian Industry becomes lax and stops working on its efficiency and productivity and competitiveness.
- ww.* M/s. European Commission has stated that their Domestic industry increase production and sales by around 15%. Why profits declined in this favorable market situation when the capacity utilization also increased is questionable.
- xx.* Without the adjustment for interest rates for Indian bank loans, there would be no price undercutting.
- yy.* M/s. Barkur Surfactants Pvt. Ltd. and M/s. UNITOP chemicals Pvt. Ltd. have stated that they strongly protest for Anti-dumping duty on "Normal Butanol / N-Butyl Alcohol" till they have alternate manufacturer in India or are in a position to manufacture atleast 60000MT/ year, as the demand of NBA is growing because agro industry is growing in India. The Andhra Petrochemical Ltd. is a very small manufacturer compared to our growing demand.
- zz.* M/s. UNITOP chemicals Pvt. Ltd. has also stated that Andhra Petrochemicals Ltd. is the only manufacturer and their total production capacity is 30000 MT/ year, out of this Andhra Petrochemicals makes only 20000 MT to 22000MT/ year as its plant is very old, always under maintenance and shutdown so they never utilize fully and total requirement of this product in India is more than 70000MT/ year. So there is a gap of almost 50000MT/ year which is imported.

aaa. M/s. Sri Krishna Pharmaceuticals has stated that they imported the product Normal Butanol or N-Butyl Alcohol Originating in or exported from European Union (EU), Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America (USA) during the period April-2010 to March 2011, April-2011 to March 2012 & April-2012 to March 2013.

Cumulative Assessment

51. Annexure II (iii) of the Anti-Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -

- a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country/ territory is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and;
- b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

52. In the present case, the margin of dumping from each of the subject countries have been found to be more than the de minimis limit prescribed; the volume of dumped imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed; and the exports from the subject countries directly compete inter se and with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. Cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product. The therefore Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effect of dumped imports.

Examination by the Authority

53. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties.

54. The AD Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

55. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping Rules states as under:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

56. It is not necessary that all parameters of injury need to show deterioration. Some parameters may show deterioration; while some may show improvement. The Designated Authority considers all injury parameters and thereafter concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not ?

57. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments in the submissions.

Assessment of Demand

58. The demand of subject goods has been determined by summing the domestic sales of domestic like product with imports of subject goods from all countries. For the purpose of present injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI&S. The Authority notes that demand of subject goods increased significantly over the injury period as depicted in the table below.

Demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	POI*
Sales of Domestic Industry	MT	19,321	21,612	14,472	7,651	6,121
Subject Countries	MT	19,297	23,949	31,929	53,195	42,556
Other Countries	MT	3,918	5,192	205	750	600
Demand	MT	42,536	50,753	46,606	61,596	49,277
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>119</i>	<i>110</i>	<i>116</i>	<i>116</i>

**POI is annualized (April 2013 to June 2014)*

59. It is seen from the above table that the demand of the product in the country has increased in 2011-12, declined in 2012-13 and then increased again in the POI. However, the demand for the product has shown a significant increase in the POI as compared to base year.

Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

Import Volumes and Share of Subject Country

60. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries are as under:

Volume of Imports	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	POI*
EU	MT	3,546	8,758	6,738	7,021	5,617
Malaysia	MT	4,423	5,804	16,454	22,459	17,967
South Africa	MT	6,247	4,936	6,698	7,129	5,703
USA	MT	5,081	3,977	1,835	3,014	2,411
Singapore	MT	-	475	204	13,573	10,858
Subject Countries	MT	19,297	23,949	31,929	53,195	42,556
Other Countries	MT	3,918	5,192	205	750	600
Total Imports	MT	23,215	29,142	32,134	53,945	43,156
Subject imports in relation to Total Imports		83%	82%	99%	99%	99%
Indian Production	MT	19,407	22,184	14,409	6,735	5,388
Subject imports in relation to Indian Production	%	99%	108%	222%	790%	790%
Demand	MT	42,536	50,753	46,606	61,596	49,277

Subject imports in relation to Demand	%	45%	47%	69%	86%	86%
---------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

61. The analysis of the above indicates the following:

- Imports from the subject countries have increased significantly in absolute terms. The increase in imports during POI is quite significant.
- Imports from the subject countries cumulatively constitute 99% of total imports during POI.
- Whereas imports from subject countries increased, imports from third countries have been negligible. Imports thus increased in relation to total imports of the product in India.
- Imports from the subject countries in relation to production have increased from 99% during 2010-11 to 790% in the POI on cumulative basis.
- Imports from the subject countries in relation to total demand have increased from 45% in 2010-11 to 87% in the POI on cumulative basis.
- Imports from the subject countries have increased in relation to production & consumption in India consistently throughout the injury period.

It has been contended by the interested parties that the imports of the product under consideration have happened when the domestic industry has not produced the product. Table below shows a comparison of imports and production by the domestic industry in the 15 months of POI.

POI	Actual		Indexed	
	Production	Imports	Production	Imports
	MT	MT		
April, 2013	***	***	100	100
May, 2013	***	***	30	88
June, 2013	-	***	-	147
July, 2013	***	***	196	96
August, 2013	***	***	334	226
September, 2013	-	***	-	67
October, 2013	***	***	193	133
November, 2013	***	***	193	267
December, 2013	-	***	-	106
January, 2014	-	***	-	184
February, 2014	-	***	-	86
March, 2014	-	***	-	71
April, 2014	***	***	132	169
May, 2014	***	***	107	111
June, 2014	-	***	-	187

62. It is seen that imports declined in May, 2013 when production declined; imports increased in June, 2013 when production declined; imports declined in July, 2013 when production increased; imports increased significantly in Aug., 2013 (more than double of April, 2013) when production was significant (double of April 2013) in July and further increased in Aug. (more than three times of April, 2013). Similar situations were found thereafter in Oct. and

Nov., 2013. It is also found that despite no production by the domestic industry during Dec, 2013 and March, 2014, import volumes were not only low but declined.

63. The Authority has in view of fluctuating behaviour determined the statistical correlation coefficient between production and imports from subject countries, which comes to 0.5 which is a positive moderate coefficient indicating that both the parameters have more or less moved in the same direction, contrary to the claim of the interested parties that the imports and production have moved in opposite direction.

64. It is thus noted that imports from the subject countries have increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. It is also noted that even though the domestic industry had suspended production during the POI and while the imports might have been triggered for that reason, it is also a fact that the import volumes were higher when the domestic industry production was higher, thus showing that whenever the domestic industry was in a position to supply subject-goods, it faced competition with significant imports.

Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

65. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

“With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.”

66. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports of the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

Price Undercutting

67. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from each of the subject countries and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level. This comparison shows that during the period of investigation, the subject goods originating in the subject countries were imported into the Indian market at prices which were lower than the selling prices of the domestic industry. It is noted that since the domestic industry did not produce the product throughout the POI, the domestic industry practically had no sales few months of the POI. The table below shows the level of price undercutting from each of the subject countries:

Price Undercutting	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Net Sales Realization	Rs./Kg	***	***	***	***
Index		100	103	106	117
EU					
Landed Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Index		100	104	101	110

Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	(0-10)%	(0-10)%	(0-10)%	(0-10)%
Malaysia					
Landed Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Index		100	95	102	109
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	(0-10)%	0-10%	(0-10)%	0-10%
South Africa					
Landed Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Index		100	111	109	112
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	(0-10)%	(5-15)%	(0-10)%	(0-10)%
USA					
Landed Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Index		100	120	101	122
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	0-10%	(5-15)%	0-10%	0-10%
Singapore					
Landed Price	Rs./Kg	No imports	***	***	***
Index		0	100	103	112
Price Undercutting	Rs./Kg	-	***	***	***
Price Undercutting	%	-	***	***	***
Price Undercutting	% Range	-	(0-10%)	(0-10)%	0-10%
Subject Countries as a whole	Rs./Kg	-5 to 0	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5

68. It is seen that price undercutting in case of imports from EU and South Africa is marginally negative, whereas from other countries is marginally positive. Overall price undercutting from dumped imports is positive though low.

69. The petitioner has contended that since imports of the product under consideration constitutes majority share in the market, the domestic industry has no option but to follow the import price. While the petitioner is the sole domestic supplier, there are limited number of consumers of the product in the market and therefore the consumers are very well aware of the prices that are being offered by the foreign producers. Under these circumstances, the domestic industry cannot get a price higher than the landed price of imports. The petitioner has further contended that the importers are getting two kinds of credits when buying from foreign suppliers – (a) interest free credit for 90 days and (b) interest bearing credit for 270 days at interest cost substantially lower than the cost of funds in India. Considering the interest rate offered by the banks in India, importers are getting credit at a much lower rate. As against this credit, the banks are giving loans at a rate of 13-15%, thus making imports significantly cheaper as compared to domestic industry prices and is one of the reasons for preference of imports. The petitioner has claimed adjustment to the net sales realization of domestic industry and landed price of imports on this account.

70. The Authority notes the submissions of the domestic industry regarding adjustment of the credit cost benefit extended by the exporters in the landed value. The Authority in this regard also notes that besides the credit cost there could even be factors like freight, preferential custom duty or even commission paid to agents by exporters which could be argued for a similar adjustment in event of differences in the business models of the exporters and the domestic industry. So far the above adjustments are appropriately accounted for while calculating the Ex-factory export price for dumping margin determination as per Authority's consistent practice. The Authority in this regard further notes that certain interested parties have argued for differential basis custom duties on Imports from different countries to be taken into account for injury analysis since the domestic industry matches the landed value which triggers the price setting. The preferential custom duty extended by the importing country on a particular import source/sources may also impact the landed value in an AD investigation while examination of factors other than dumping needs to be carried out for an objective assessment of causal link. Therefore the landed value if altered by factoring credit cost may perhaps require factoring in of basic custom duty at a MFN rate rather than the preferential custom duties on one or a few import sources. The Authority therefore adheres to the consistent established practice of evaluating the landed value as done in its earlier investigations.

Price Underselling

71. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports. The landed price of imports considered for the purpose of price undercutting has also been adopted for the purpose of determining price underselling. Comparison of weighted average NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

European Union

- **M/s Oxea GmbH through Petrochem Middle East, Dubai and ICC Chemicals, USA:** The landed value for M/s Oxea GmbH has been determined by adding 1% landing charges to CIF and applicable customs duties, i.e. basic custom duty and cess. The landed value is thus evaluated as *** \$/MT with injury margin as ***\$/MT (-5 to 0 %).
- **Non cooperative producers/ exporters:** The landed value for non cooperative producers/ exporters from EU has been computed on the basis of the lowest export price/ CIF, with 1% landing charges and applicable customs duty i.e. basic custom duty and cess. The landed value is thus referenced as***\$/MT. The injury margin is thus referenced as ***\$/MT (0-5 %).

Injury Table

Producer	Exporter	Landed price \$/MT	Non injurious Price \$/MT	Injury Margin \$/MT	Injury Margin (%) Range
OxeaGmbh	Petrochem Middle East, Dubai	***	***	(Negative) ***	*** (-5 to 0)
OxeaGmbh	ICC Chemicals, USA	***	***	(Negative) ***	*** (-5 to 0)
Non cooperative producer/exporters and combinations other than above two rows		***	***	***	*** (0-5)

Malaysia

- **M/s PCD through M/s PCM:** The weighted average landed value of imports has been determined on the basis of the verified weighted average CIF prices of subject goods produced by M/s PCD and exported by M/s PCM to India by adding 1% landing charges and applicable customs duties i.e. basic custom duty and cess. The landed value is thus referenced as *** \$/MT. The injury margin for M/s PCD through M/s PCM is thus determined as *** \$/MT (0-5 %).
- **M/s BASF PETRONAS:** The landed value for M/s BASF PETRONAS has been determined by adding 1% landing charges to CIF and applicable customs duties. The landed value is thus evaluated as *** \$/MT with injury margin as ***\$/MT (0-5 %).
- **Non cooperative producers/ exporters:** The landed value for the non cooperative producers/ exporters from Malaysia has been computed on the basis of the lowest export price (CIF), with 1% landing charges and applicable customs duty i.e. basic custom duty and cess. The landed value and the injury margin are determined as ***\$/MT and ***\$/MT respectively (10-15%).

Injury Table

Producer	Exporter	Landed price \$/MT	Non injurious Price \$/MT	Injury Margin \$/MT	Injury Margin (%) Range
PCD	PCM	***	***	***	*** (0-5)
BASF PETRONAS	BASF PETRONAS	***	***	***	*** (0-5)
Non cooperative producer/exporters and combinations other than above two rows		***	***	***	*** (10-15)

South Africa, USA, Singapore

- The Landed Value of the subject goods from producers/ exporters from above mentioned three subject countries in POI has been computed on the basis of the transaction wise DGCI&S data after adding 1% landing charges on CIF, basic customs duty with cess. The landed values for producers/ exporters of the subject goods from USA, Singapore and South Africa is thus considered as ***\$/MT, ***\$/MT and *** \$/MT respectively.

Injury Table

Subject country	Producer	Exporter	Landed price \$/MT	Non injurious Price \$/MT	Injury Margin \$/MT	Injury Margin (%) Range
South Africa	Any	Any	***	***	***	*** (0-5)
USA	Any	Any	***	***	***	*** (0-5)
Singapore	Any	Any	***	***	***	*** (0-5)

72. It is seen that the landed prices of the subject goods from the subject countries except for EU were lower than the NIP determined for the domestic industry, thus indicating price suppression phenomena.

Price Suppression/Depression

73. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the Table below:

Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of sales	Rs./KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>107</i>	<i>122</i>	<i>144</i>
Selling Price	Rs./KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>103</i>	<i>107</i>	<i>117</i>

74. It is seen that both costs as well as selling price of the domestic industry increased over the injury period. Whereas the costs have increased significantly; the domestic industry has not been able to increase its prices to that extent, thus, leading to financial losses in the POI. The petitioner has claimed that they have been unable to increase its selling price in proportion to increase in cost or even at the level of cost thereby suffering losses due to presence of dumped imports in the market. It is seen that the imports are suppressing the domestic prices. The petitioner has further claimed that the domestic industry could not achieve normal production in the POI due to non-remunerative prices and shortage of raw material. The petitioner has segregated cost incurred on account of idle time from the total cost to assess the injury caused by dumped imports. It has been further claimed by the petitioner that even if the domestic industry had been able to achieve normal production in the POI, the cost would have been significantly higher than the selling price.

75. Annual reports of the domestic industry for various period of injury were examined. It is seen that the company has identified a number of reasons for its performance, which includes non-availability of propylene from HPCL, increase in the prices of raw materials with no corresponding increase in sale prices of products, increased power cost, decline in gap between the prices of products and raw-materials after commencement of new capacities for oxo alcohols in China, depreciation of rupee, general inflation, and no corresponding increase in product prices, increase in propylene prices and lower market selling prices for the products, new capacities that have come up and further capacities coming up in

the international scenario, poor product prices and consequently unit shut down for prolonged period and dumping of the product. The Authority notes in this regard that the factors affecting the domestic industry can be broadly divided into the following - (a) increase in cost of production due to increase in input prices or general inflation; (b) increase in cost of production due to lower production (because of increased incidence of overhead/fixed expenses getting loaded on lower production); (c) rupee depreciation/appreciation; (d) product prices not increasing.

76. While the cost of production of the domestic industry was increasing, its selling price of the products were not increasing proportionally. Further, these increases in the cost of production were on account of increase in raw material price increases, power rate increases or general inflation. The Authority notes that the domestic industry is expected to move its prices up or down in tandem with the increase or reduction in cost of production in a normal market situation. If the domestic industry has been faced with the increase in the cost of production on account of factors such as raw material price increases, power rate increases or general inflation, and if the domestic industry is unable to increase its prices in proportion to these increases, it could be that the domestic industry has been prevented from increasing its prices. While the domestic industry did identify other factors as also responsible for its inability to increase its selling price, the Authority notes that all these factors are intrinsically linked to imports also because the domestic industry has to price its product in competition to the imports. Since the consumers would want to buy the product at a price comparable to the imported product price, if the domestic industry has not increased its prices despite increase in cost of production, it is also due to availability of low priced imports. It is however appreciated that the increase in the cost of production due to lower production cannot be passed onto the consumers and business enterprises are not expected to charge higher prices merely because they want to maintain their profit levels and the production (and consequently) sales were lower due to other factors.

77. The domestic industry identified changes in exchange rate as one of the factors. The Authority however notes that this reference to exchange rate by the domestic industry is in the context of its ability to increase the prices of the product under consideration. If rupee depreciates, the landed price of imports increases and the domestic industry is in a position to charge better prices. Similarly, if rupee appreciates, the landed price of imports declines and the domestic industry is expected to reduce its prices. Thus, reference to exchange rate fluctuations in the annual reports refers to the ability or inability of the domestic industry to change its prices in the market.

78. The Authority thus notes that the annual report of the domestic industry does show two distinctly different factors of injury - (a) domestic industry being prevented from increasing its prices in proportion to the cost increases (which must clearly be seen a result of dumping) and (b) inability of the domestic industry to produce the product to the extent it could have due to non-availability of raw materials. The Authority therefore holds that as far as changes in production, sales and market share are concerned, and the deterioration in the same could not be attributed to dumping of the product under consideration in India, but the dumped imports have led to price undercutting and price suppression.

Economic parameters of the domestic industry

79. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. An

examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

80. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	POI*
Capacity	MT	20,625	22,500	22,500	28,125	22,500
Production	MT	19,407	22,184	14,409	6,735	5,388
Capacity Utilization	%	94.09%	98.60%	64.04%	23.95%	23.95%
Domestic Sales	MT	19,321	21,612	14,472	7,651	6,121
Demand	MT	42,536	50,753	46,606	61,596	49,277

**POI (figures are annualized)*

81. It is seen from the above table that:

- The domestic industry enhanced capacities in 2011-12 in view of higher demand in the Country.
- The demand for the product under consideration in the country has increased significantly over the injury period.
- Production of the domestic industry increased in 2011-12. However, the production declined significantly thereafter in 2012-13 and further in the POI. Production of the domestic industry in the POI was significantly low.
- Capacity utilization of the domestic industry has followed the same trend as that of production. The domestic industry was able to achieve good capacity utilization in the period 2011-12, but the same has declined significantly thereafter in 2012-13 and the POI. Whereas demand for the product under consideration increased by 16% over the period, capacity utilization declined to mere 24% in the POI. Capacity utilization increased in 2010-11 and thereafter declined significantly in 2012-13 and the POI.
- Sales of domestic industry increased in 2011-12 and declined thereafter. The domestic sales in POI on annualized basis, declined by 68% as compared to base year 2010-11.

82. It is thus concluded that production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry deteriorated significantly despite increase in demand for the product in the Country. The Authority notes that the production of the domestic industry has declined significantly in the period of investigation as compared to base year as well as previous year 2012-13. The petitioner has admitted that the domestic industry has suffered loss in production due to unavailability of raw materials as far as decline in production in 2012-13 and beginning of 2013-14 is concerned. The domestic industry suffered production loss from Aug., 2013 again due to fire in HPCL plant (who supplies them raw materials). At the same time, the annual reports also make it evident that the Petitioner had also curtailed production due to unremunerative price of its products. It is not a situation where entirety of the production loss was due to raw materials unavailability. In any case, the Authority does not consider deterioration in volume parameters (such as production, capacity utilization, sales volumes and market share) in concluding whether that the domestic industry has suffered material injury.

Profits, profitability, return on investment and cash profits

83. The cost of sales, selling price, profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analyzed as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
Cost of sales	Rs./KG	***	***	***	***
Index		100	107	122	144
Selling price	Rs./KG	***	***	***	***
Index		100	103	107	117
Profit/loss	Rs./KG	***	***	***	***
Index		100	68	-36	-125
Profit/loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Index		100	76	-27	-39
Cash Profit	Rs./KG	***	***	***	***
Index		100	72	-21	-100
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Index		100	80	-15	-32
Profit before Interest	Rs./KG	***	***	***	***
Index		100	63	-13	-64
Profit before Interest	Rs. Lacs	***	***	***	***
Index		100	70	-19	-20
Return on Capital Employed (Range)	%	15-20	10-15	0 to -5	-5 to -10

**POI (figures are annualized and in accordance with the cost audit report)*

84. The Authority notes that:

- Both, the cost of sales and the selling price, increased over the injury period. However, the increase in selling price was lower than the increase in cost, thus, leading to decline in profitability.
- The domestic industry had earned profit in the base year, 2010-11. The profitability however deteriorated in 2011-12. The decline in profitability in 2011-12 was despite increase in production in this year. The profitability of the domestic industry deteriorated significantly thereafter and the domestic industry suffered financial losses in 2012-13 and the POI.
- Return on investment over the injury period has shown the same trend as that of profits. Return on investment declined in 2011-12, becoming negative thereafter, in 2012-13 and the POI.
- Profit before interest and taxes (PBIT) declined in 2011-12, becoming negative thereafter, in 2012-13 and the POI.
- Cash profits have also shown the same trend as that of profits. Cash profits declined in 2011-12, becoming negative thereafter, in 2012-13 and the POI.

85. Since the domestic industry has not produced the product under consideration for some part of the POI, the interested parties have contended that the decline in profits is because of suspension of production by the domestic industry. The Authority has for the purpose of determining extent of injury has adopted a normated cost of production to determine NIP so that idle period cost is not included in the analysis.

Market Share

86. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Domestic Industry	%	45%	43%	31%	12%

Subject countries-Imports	%	45%	47%	69%	86%
Other Countries-Imports	%	9%	10%	0%	2%

87. It is seen from the above table that the market share of the domestic industry has declined throughout the injury period and that of the subject countries on cumulative basis has increased consistently. The market share of the domestic industry declined by 33% during POI as compared to the base year, whereas the market share of the subject countries increased by 41% in the same period. However, since the production of the domestic industry suffered both due to non-availability of raw material as well as unremunerative product prices (i.e., dumping), the Authority has not considered decline in market share as an indicator of impact of dumping of the product in the Country.

Employment, Productivity and Wages

88. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Index		100	83	67	66
Salaries & Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Index		100	94	79	81
Wages per Unit of Production	Rs./Kg	***	***	***	***
Index		100	83	107	294
Productivity per Day	MT	***	***	***	***
Index		100	115	75	27

*POI (figures are annualized)

89. It is noted that employment with the domestic industry declined over the injury period. Wages paid have declined up to 2012-13 and then increased slightly in the POI. Productivity increased in 2011-12 and declined thereafter, in line with the decline in production.

90. However, since it is an established fact that the production of the domestic industry suffered both due to non-availability of raw material as well as unremunerative product prices (i.e., dumping), the Authority has not considered these parameters as an indicator of impact of dumping of subject goods on one domestic industry.

Inventories

91. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Index		100	179	239	122

92. It is seen that inventories with the domestic industry increased up to 2012-13 and then declined in the period of investigation.

However, since the production of the domestic industry suffered both due to non-availability of raw material as well as unremunerative product prices (i.e., dumping), the Authority has not considered changes in inventory as an indicator of impact of dumping on the domestic industry.

Growth

93. The data relating to growth of the domestic industry is shown in the following table:

Growth	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
Production	Y/Y	-	14%	-35%	-63%
Domestic Sales	Y/Y	-	12%	-33%	-58%
Cost of sales	Y/Y	-	7%	15%	25%
Selling price	Y/Y	-	3%	4%	10%
Profit/(Loss)	Y/Y	-	-32%	-153%	-457%
ROI	Y/Y	-	-3%	-16%	-6%
Market Share	Y/Y	-	-3%	-12%	-19%

94. The Authority notes that growth of the domestic industry was adverse both in terms of volume and price parameters. Growth with regard to sales, production, market share, profits, return on investments and cash flow was negative during period of investigation.

95. It is therefore noted that the production of the domestic industry suffered both due to non-availability of raw material as well as unremunerative product prices (i.e., dumping) and therefore the Authority considers that the negative growth of the domestic industry in respect of volume parameters could not be conclusively considered as an impact of dumping of the product in the Country. Further, as regards growth in price parameters (such as profits, return on investment and cash flows), the Authority acknowledges that the fixed expenses incurred by the domestic industry during the shutdown period have also contributed to decline in profits (and consequently cash flow and return on investments). However, the Authority notes that the cost auditors of the company have been mindful of the situation and have determined profitability of the product under consideration after excluding the expenses incurred by the domestic industry during the period of production suspension. It is noted that the profits position determined by the cost auditors also shows negative growth of the domestic industry in respect of price parameters. Thus, it is concluded that even when the effect of production suspension on the domestic industry profits is excluded, the growth of the domestic industry was negative.

Ability to raise capital investments

96. The Authority notes that given rising demand of the product in the country, the domestic industry has made investments in its enhancing capacity. However, despite these investments, the performance of the domestic industry has deteriorated considerably.

Level of dumping & dumping margin

97. It is noted that imports from each of the subject countries are entering the country at dumped prices and that the margin of dumping are above de-minimus limits.

Factors Affecting Domestic Prices

98. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing price undercutting as well as price underselling in the Indian market. The Authority notes that the prices of the product under consideration in general should move in tandem with the prices of key raw materials and the domestic industry has been fixing its prices considering these input prices

and landed price of imports. The Authority further notes that the statements of the domestic industry in annual reports contain statements by the domestic industry which indicate that the domestic industry has not been able to increase its prices despite increase in raw materials or power prices. These public statements also show that the domestic industry benchmarks its prices with the imports. Thus, the landed value of subject goods from the subject countries is indeed a factor off cutting domestic prices.

99. The Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury and the same is established on price undercutting and underselling without considering decline in volume parameters such as production, sales, capacity utilization, inventories.

Causal Link

100. The Authority notes that many interested parties have argued that injury to DI is due to their 'intrinsic factors' i.e. high prices of raw materials, dependence on one source of propylene, plant shut down both of DI and its supplier i.e. HPCL due to fire accidents, maintenance, likely self-injury by DI due to inter se change of production mix amongst the 2 main products i.e. NBA and 2 EHI and IBA etc. and other factors like inevitability to import due to huge demand supply gap, ensuring uninterrupted continuous supply of Product Under Consideration to the end users which were consequences of the warranting circumstances as stated above. The Authority notes that during the POI there are multiple factors which could have led to injury to the domestic industry. No doubt these would also be intrinsic besides extrinsic factors like dumping.

101. The Authority has consistently in its past investigations undertaken appropriate segregation of such factors so as to evaluate the extent of injury only on account of dumped imports. In the instant investigation, the production volume, sales and capacity utilisation have been primarily adversely affected an account of plant shut down for more than 200 days in the 15 months POI. However in a last few months in the POI especially Dec. 2013 to June 2014, the landed values of imports from subject countries have shown a declining trend. The month wise production and imports from subject countries in POI depict trend in the same direction when statistically correlated contrary to the claim of certain interested parties that imports increase only use when production of DI drops. The month wise production of NBA in POI when statistically correlated with production of 2 EHI and IBA also show a positive correlation of 0.90 i.e movement in same direction contrary to the claim of injury being self-inflicted due to inter se change of production mix amongst the 3 products produced by DI. The domestic industry would face price injury when it is under pressure to match the landed value (most likely the least landed value). The month-wise price undercutting in POI is noted to be negative as well as positive in different months as shown in table below. The Authority has therefore evaluated an overall price undercutting for entire POI rather than the last few months to examine whether the overall price undercutting in the POI demonstrates a net price injury.

102.

Month wise price undercutting

POI	NSR (Rs/Kg)	Landed Price (Rs/Kg)	Price undercutting (Rs/Kg)
		Average	Average
Apr- 13	***	***	-5 to 0
May – 13	***	***	0 to 5
Jun- 13	***	***	0 to 5
Jul- 13	***	***	-5 to 0
Aug- 13	***	***	-5 to 0
Sep- 13	***	***	-5 to 0
Oct- 13	***	***	-5 to 0

Nov- 13	***	***	-5 to 0
Dec-13	***	***	0 to 5
Jan- 14	***	***	15 to 20
Feb- 14	***	***	10 to 15
Mar- 14	***	***	15 to 20
Apr- 14	***	***	0 to 5
May- 14	***	***	5 to 10
Jun- 14	***	***	15 to 20
Average			0 to 5

103. The Authority 'notices that intrinsic factors' would primarily leads to a volume injury as the adverse price effect due to high cost elements of raw material, plant overheads and other process efficiencies are normated while computing the NIP as per AD rules. The price effect would be triggered more by extrinsic factors i.e. dumping which can be captured by evaluation of weighted average injury margin for the entire POI. The other factors like changes in demand, product substitutability/obsolescence etc. as required is also examined by the Authority. The Authority in order to capture the price effect strictly on the comparable terms of trade compares the NIP computed for bulk consignments with the import price which also happens in bulk.

104. The Authority has below examined the other factors listed under the Antidumping Rules which could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

Imports from third countries

105. The Authority has examined import data of the subject goods obtained from DGCI&S on transaction-wise basis. It is noted that imports from third countries are negligible and could not have caused claimed injury to the domestic industry.

Contraction in demand

106. The Authority notes that the demand for the subject goods has shown significant improvement during the injury period. It has increased in the POI from the base year and the previous year. Possible contraction in demand could not have caused injury to the domestic industry.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

107. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

Developments in technology

108. The domestic industry's production process is Naphtha based on which they plan to shift to natural gas in future. However, the Authority notes that the existing technology and process adopted by the domestic industry is comparable with foreign producers as regards production of the final product.

Changes in pattern of consumption

109. The domestic industry is producing the subject goods that have been imported into India. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

Export performance

110. Petitioner has no exports of the product under consideration. Thus, the claimed injury to the domestic industry is on account of domestic operations only.

Performance of the domestic industry with respect to other products

111. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

Productivity of the domestic industry

112. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has followed the same trend as production. Deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry.

Factors establishing causal link

113. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has deteriorated due to dumped imports from subject countries. Causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- a) The volume of imports has increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The annual report shows that the production, and consequently capacity utilization and sales of the domestic industry suffered due to both - non availability of raw materials and unremunerative product prices, however the Authority has not considered the decline in market share of the domestic industry and decline in production, capacity utilization, sales of the domestic industry as a result of dumping of the product under consideration.
- b) The domestic industry is fixing its selling prices based on the import price from various subject countries. Further, whenever the cost of production of the domestic industry is increasing due to either raw materials, or power or general inflation, the domestic industry wishes to increase its prices. Even when the domestic industry increased its prices, the domestic industry has been prevented from raising its prices in proportion to the increase in the cost of production.
- c) The imports of the product under consideration are causing price suppression and are preventing the domestic industry from raising the prices. Consequently, profits, cash flow and ROI has declined.
- d) The subject imports are resulting in price underselling in the market.
- e) The growth of the domestic industry became negative in terms of a number of price and volume related economic parameters. While negative growth in volume parameters could be due production suspension, negative growth in the price parameters is primarily due to dumping of the product in the Country.

114. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry. For the purpose the Authority has considered best consumption norms of the raw materials & utilization. Further, since the domestic industry did not produce the product under consideration for some period during the POI, the Authority has considered fixed expenses by considering optimum production volume of *** MT considering best capacity utilisation during last 4 years. The Authority has also segregated and excluded various expenses considering the provisions of Annexure-III to the Rules. Capital employed of the domestic industry has been determined on the basis of provisions of Annexure III of the Rules and the return on capital employed has been granted at the level of notional production. The non-injurious price of the domestic industry so determined has been compared with the landed values of the subject imports from each of the responding exporters in the subject countries to determine injury margin.

Indian industry's interest & other issues

115. The Authority notes the submissions of users and holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of

antidumping measures is not to restrict imports from the subject countries in any way, and, to affect the availability of the products to the consumers.

116. The Authority also holds that though in event of imposition of anti-dumping duties the price level of product in India may be affected but fair competition in the Indian market will not be reduced by such anti-dumping measures. On the contrary, the anti-dumping measures may mitigate the unfair advantage gained by dumping practices, which would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or even more sources of supply.

Comments on Disclosure

Comments by Domestic Industry

117. The following comments have been made by the domestic industry:

- While determining price undercutting, the Authority has rejected the issue of credit period raised by the petitioner.
- The Authority may kindly specify in duty table that the PUC should attract duty regardless of the customs classifications under which goods are being cleared by the importers. Further, the authority may kindly specify in duty table that the customs classification is indicative only. It was submitted that only the duty table contents are relevant in this regard. Anything mentioned in the para relating to "product under consideration" but not stated in duty table is likely to get ignored while issuing notification by the Ministry of Finance. The Customs authorities at the port also consider and rely upon the notifications issued by the MOF and do not take cognizance of the notification issued by the final findings.
- The non injurious price determined is grossly low and is leading to unduly low injury margin.
- It is inappropriate to ignore actual production and adopt any other production basis for determination of non injurious price. The Authority should consider the expenses as per cost audit statement and ignore the fact that the petitioner plant was under shutdown.
- The Authority is requested to consider the request of the petitioner for inclusion of freight for determination of injury margin.
- Credit period should be considered for injury margin determination. In this regard, the Supreme Court case of in the matter of Haldor Topose was cited. The impact of credit can be seen either in terms of "cost to the exporter" or "benefit to the importer".

Cost to the exporter:

SN	Parameter		Case -1	Case -2	Case -3	Case -4
1	Interest free credit					
A	Credit period	Days	90	120	180	365
B	Interest cost of exporter	%	6%	6%	6%	6%
C	Selling price (assumed)	US\$/MT	1400	1400	1400	1400
D	Credit cost	US\$/MT	21	28	41	84
E	Credit cost %	%	1.48%	1.97%	2.96%	6.00%
2	Interest bearing credit					
A	Credit period	Days	90	120	180	365
B	Interest cost of exporter	%	6%	6%	6%	6%

C	Interest cost charged by exporter	%	4%	4%	4%	4%
D	Difference in interest cost	%	2%	2%	2%	2%
E	Selling price (assumed)	US\$/MT	1400	1400	1400	1400
F	Credit cost	US\$/MT	7	9	14	28
G	Credit cost %	%	0.49%	0.66%	0.99%	2.00%

Benefit to the importer:

SN	Parameter		Case -1	Case -2	Case -3	Case -4
1	Interest free credit					
A	Credit period	Days	90	120	180	365
B	Interest cost of importer	%	13%	13%	13%	13%
C	Hedging cost	%	6%	6%	6%	6%
D	Net cost to importer	%	7%	7%	7%	7%
E	Selling price (assumed)	US\$/MT	1400	1400	1400	1400
F	Credit cost	US\$/MT	24	32	48	98
G	Credit cost %	%	1.73%	2.30%	3.45%	7.00%
2	Interest bearing credit					
A	Credit period	Days	90	120	180	365
B	Interest cost of importer	%	13%	13%	13%	13%
C	Interest cost charged by exporter	%	4%	4%	4%	4%
D	Hedging cost		6%	6%	6%	6%
E	Difference in interest cost	%	3%	3%	3%	3%
F	Selling price (assumed)	US\$/MT	1400	1400	1400	1400
G	Credit cost	US\$/MT	10	14	21	42
H	Credit cost %	%	0.74%	0.99%	1.48%	3.00%

- Anti dumping duty may be imposed as fixed quantum of anti dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty in US\$/kg. To support the said claim, cases of CESTAT were cited:

- In the case of NBR from Korea, the Hon'ble CESTAT modified variable anti-dumping duty recommended by Designated Authority to fixed duty based on the appeal filed by an exporter, M/s. Kumho Petro-Chemicals Co. Ltd. (2004(170)E.L.T. 274)
- In the case of Metcoke, the CESTAT, vide their decision 2000(116) E.L.T. 67 modified the anti-dumping duty from variable to fixed.
- In the case of Vitriified files, the CESTAT upheld the decision of the Designated Authority to impose fixed quantum of duty.
- The decision of the CESTAT in the matter of Metcoke from China.

Comments by Interested Parties:

118. The following comments have been made by interested parties:

- There is no justification for claiming landed price from subject countries as per DGCI&S as confidential.
- Injury, if any, to the domestic market was not due to imports from subject countries but self inflicted.

- There is no disclosure about the methodology adopted by the Authority to make adjustments in the cost of production of petitioner to account for the idle time due to plant shut downs in the disclosure statement.
- AD duties, if any, should only be recommended in terms of Indian Rs and not USD;
- Imposition of any AD duty in the present case would add on the cost of the users who are facing non supply of subject goods by the single domestic producer.
- The Authority may kindly record the term “PETRONAS” in capital letters throughout the disclosure statement and the final findings.
- The Authority’s observation that imports of the subject goods have increased in absolute terms and in relation to production in the POI, is incorrect in view of the surrounding facts i.e. the domestic industry was shut for a period of 263 days during the POI – for 231 days due to non-availability of raw material and for remaining days due to unremunerative prices.
- The Authority should do a quarter-by-quarter analysis of imports vis-à-vis production of the domestic industry. The month-by-month analysis of production of the domestic industry with import volumes gives a skewed picture.
- It is not understood, on what basis the correlation coefficient *between production and imports from subject countries* has been calculated, as the actual figures of production and imports have not been disclosed by the Authority. Further, non-disclosure of production and import figures month-wise is a violation of the principles of natural justice.
- For a proper analysis, landed value of imports should be compared with net sales realization of the domestic industry only for those periods when the domestic industry was in operation. Such analysis would show that there is no price undercutting in this case.
- The Authority’s analysis on Price Underselling is incorrect as the Authority has considered very high cost of production for the domestic industry.
- It is not clear on what basis the NIP has been determined on weighted average basis for the entire POI. The month-wise raw material prices relied upon by the Authority should be disclosed in indexed form to clear the doubts regarding cost of production and NIP of the domestic industry.
- It is not understood on what basis such wages per unit of production have been claimed by the domestic industry and allowed by the Authority.
- NIP should be calculated for the period in which the domestic industry was in operation and landed value should be compared for the same period.
- It is incorrect to say that the product prices were not increasing, because an analysis of landed value for all subject countries shows that landed value consistently increased during the entire injury analysis period.
- It is apparent from the annual reports of the domestic industry that the sole reason of injury was non-supply of raw material leading to plant shutdown.
- The Authority ought to show the exact extract from the annual reports of the domestic industry from the injury analysis period wherein it is stated that the domestic industry has been prevented from increasing prices due to dumping.
- The only reason for injury to the domestic industry is loss of production due to plant shutdown.
- The Authority’s determination of not considering volume parameters for determination of material injury is legally incorrect. All economic parameters of the domestic industry ought to be considered for a proper appreciation of material injury to the domestic industry.

- The Authority should modify its conclusions on price effect and conclude that there is no price effect due to imports during the POI.
- There is no volume injury to the domestic industry.
- Prices of raw materials considered by the Authority are very high.
- The Authority has determined NIP based on cost of production data and raw material prices for selective months (when the domestic industry manufactured the subject goods) in the POI but has compared the same with average landed value of the subject goods during the POI. The Authority should therefore re-determine cost of production and NIP of the domestic industry.
- Extraordinary hike in wages as claimed by the domestic industry has inflated the cost of production.
- The Authority wrongly holds that employment, productivity and wages are not relevant factors for determining material injury. Also the observation of the Authority that inventory is not an indicator of injury for the purpose of injury analysis, is incorrect.
- Throughout the final findings that would be issued, wherever the Authority examines the volume parameters of the domestic industry it should be recorded that *there is no injury on volume parameters due to imports of the subject goods*.
- Incorrect analysis has been made by the Authority on the growth of the domestic industry during the POI.
- It is not understood on what basis competition in the domestic market has been examined by the Authority.
- The Authority has incorrectly determined selling prices and NIP of the domestic industry. Also, the Authority should also provide indexed figures of NIP for the periods prior to the POI.
- The Authority wrongly notes that prices of the domestic industry did not move in tandem with prices of the raw material and the domestic industry has been fixing its prices based on landed prices. The Authority also wrongly concludes that the annual reports of the domestic industry show that the domestic industry benchmarks its prices with imports.
- The Annual reports of the domestic industry should be considered as it is. The Authority should not add more facts to already established facts to support the domestic industry's claims. To support this, CESTAT's case of *Andhra Petrochemicals Ltd. v. Designated Authority* [2006 (201) E.L.T. 481 (Tri. - Del.)] was cited.
- Volume parameters cannot be ignored while analysing material injury.
- There is no causal link in the present case as there is no volume injury to the domestic industry and injury due to price effects have been wrongly determined by the Authority.
- The Authority has not explained how cost of production has been adjusted to take into account idle time when production was suspended by the domestic industry.
- In determining the non-injurious price for domestic industry, the statute provides for a reasonable rate of return to be included. Reliance in this regard was placed on CESTAT's case of *Indian Spinners Association v. Designated Authority* 2004 (170) E.L.T. 144 (Tri. - Del.)
- The Authority should take into consideration increase in cost of utilities while noting increase in cost of sales of the domestic industry.
- Imports from Malaysia were only bridging the demand-supply gap in the domestic market of India.
- High prices of propylene, the primary raw material for the production of NBA, during the POI should be examined in the causal link analysis. Also the domestic industry was able to sell its entire production in the injury analysis period.

- Same rate of anti-dumping duty for related entities, i.e. for M/s PETRONAS Chemicals Derivatives SDH BHD and M/s BASF PETRONAS Chemicals SDN BHD in the present investigation should be recommended as per the consistent practice of the Authority. In this regard, anti-dumping investigations on the imports of:
 - (a) Plain Gypsum Plaster Board originating in or exported from China PR, Indonesia, Thailand, and United Arab Emirates [Notification No. 06/2013-Customs (ADD) dated 12 April 2013];
 - (b) Sunset review concerning imports of 'Homopolymer of Vinyl Chloride (Suspension Grade)' originating in or exported from China PR, Chinese Taipei, Indonesia, Japan, Korea RP, Malaysia, Thailand and the United States of America [Notification No. 27/2014-Customs (ADD) dated 13 June 2014].
- Dumping margin should be calculated as a percentage of CIF export price and not ex-factory export price in this case.
- There is no discussion or evidence placed on record to show that how the production loss of the domestic industry of 212 days did not allegedly lead to self inflicted injury, but the imports did.
- It remains to be seen as to how did the Authority undertook to consider the period of investigation as a comparison period and the last three years for adopting the "best utilization" ratios for various parameters such as raw materials, utilities etc.
- Causal link clearly fails to meet the requirements of Rule 9(2) of the Anti-dumping Rules and Article 5.2 of the Anti Dumping Agreement (ADA).
- The subject countries in the present investigation have wrongly been cumulated for the purposes of analyzing the injury caused to the domestic industry. The Authority de-cumulate the EU imports and terminate the investigation against those imports without the imposition of measures. To support the said claim, Article 3.3 of the ADA, Paragraph (iii) of Annexure II to the Anti-Dumping Rules, *European Communities – Malleable Cast Iron Tube Or Pipe Fittings From Brazil* [WT/DS219/AB/R dated 22 July 2003], *Certain tube and pipe fittings, of iron or steel, from China, Croatia and Thailand* [Commission Regulation (EC) No 2318/95 of 27 September 1995] and *Ammonium nitrate from Russia* [Council Regulation (EC) No 2022/95 of 16 August 1995] were cited.
- Despite increase in demand the imports from EU have declined over the injury period.
- Competition is an indicator of a free market. Inflow of imports into the home market does not point towards dumping especially in the present case where the domestic industry has suspended production during the POI.
- There is no price underselling caused by the producer/ exporter from EU since the injury margin calculated by the Authority is negative (-5 to 0%).
- The Authority's argumentation that the Petitioner should have been able to pass on the 40% price increase of propylene (when by comparison import prices of propylene into the EU increased only by 8% during the same period) is wrong.
- Imports cannot be held responsible for the Petitioner's inability to pass on excess raw material costs.
- Imports from the subject countries did not suppress /depress the Petitioner's prices. Furthermore, prices of EU imports of n-butanol have not undercut Indian prices throughout the entire period investigated and EU import volumes have decreased by 47% since 2011/12.
- The Authority did not consider deterioration in volume parameters in concluding whether that the domestic industry has suffered material injury. Also, the decline in profits and inability of the domestic industry to raise Capital Investments is because of suspension of production by the domestic industry.

- The Authority has not considered decline in market share; Employment, Productivity & Wages; and considered changes in inventory as an indicator of impact of dumping on the domestic industry.
- Since the imports from EU are not undercutting or underselling the domestic industry's prices, the alleged dumping is irrelevant for the injury assessment.
- The Authority should also examine factors other than dumped imports which might be injuring the domestic industry at the same time.
- There is a breach in causal link between material injury caused to the domestic industry and the allegedly dumped imports from EU.
- The imposition of anti-dumping duties is not in the interest of the downstream Indian industry as the local demand is more than twice the domestic production.
- The sole purpose of the present Petition is to create an artificial supply shortage through the imposition of anti-dumping duties that would allow the Petitioner to increase prices to the detriment of the domestic users, which is not a legitimate use of the anti-dumping instrument.
- The Authority is requested to order the Petitioner to provide further details on the impact of the cyclone *Hudhud* on its production capabilities, so that it could be assessed whether imposition of anti-dumping duties would lead to a supply shortage to the detriment of Indian users.
- It is assumed that the Authority has determined the capital employed using book value of the domestic industry's assets.
- The Authority should adjust the non-injurious price downwards to take into account (i) the part of the Petitioner's injury that it admits is not attributable to imports, and (ii) the part of the injury that is self-inflicted by purchasing propylene at exaggerated prices from a local supplier when it was apparently available cheaper from other international sources.
- The POI has been set out without appropriate justification.
- Injury, if any, has been suffered by the domestic industry by factors other than imports alleged to be dumped.
- It is wrong to conclude that price level of the Indian domestic industry became unremunerative because of the dumped imports, but rather that the cost of production had abnormally increased without any apparent reason.
- Unavailability of raw material and the resulting plant shut down for 212 days breaks the causal link.
- The petitioner would inevitably have lost market share to the benefit of imports over the period 2010- 11 to the POI because of the significant increase in domestic demand.
- NIP calculated on the basis of an abnormally high cost of sales has been unduly inflated.
- Full set of information on the basis of which the dumping, undercutting and underselling margins had been calculated was not disclosed to the EU exporters.

Examination by Authority:

119. The Authority notes the submissions on injury and causal link made by various interested parties, regarding comparison to be made for the months only when production was made by the Domestic Industry, volume injury occurring only due to intrinsic factors, Authority not to attribute and assign conclusions on statements in the annual reports of the domestic industry, NSR being higher than landed value, terminate present investigation like in earlier photographic paper case where the domestic industry was sick, cumulation of imports not possible due to different rates of basic custom duty, Hon'ble CESTAT having quashed the findings of the same case earlier due to non-evaluation of causal link, lead time of imports not considered and hence erroneous interpretation of import and production correlation, erroneous interpretation of price injury and causal link. The Authority notes the above submissions and

holds that a month-wise analysis in POI as requested earlier by various interested parties and keeping the nature of the case was undertaken. However while month-wise trend analysis has been undertaken to analyse causality, for the assessment of quantum of price injury, the entire POI has been taken as done in all cases. The lead time is equally important for domestic production, and therefore for an overall assessment, the entire POI is considered so as to average out the lead time issues, as done consistently in anti-dumping investigations.

120. The Authority also notes that M/s APL being the sole domestic producer though has no competition from domestic producers, it faces competition from imports especially dumped imports from subject countries. The authority also holds that filling of demand supply gap by imports from subject countries needs to be at fair price and not at unfair dumped price which is being addressed in the finding.

121. As regards the argument on no price injury due to dumping to Domestic Industry made by various interested parties the Authority holds that the verified data in accordance with the Anti Dumping Rules has been adopted and the extent of dumping evaluated has not been contested by either cooperative or non-cooperative exporters. The comparison of NIP and Landed Value in case of cooperative exporters has been done on the basis of export price data submitted by exporters, duly verified and furnished to exporters through an exporter's verification report and disclosure. The Landed Value accordingly has been worked out on this data and injury margin evaluated after appropriate comparison with NIP over the entire POI. The injury margin has been worked out by adopting the landed value of dumped imports and injurious price effect impact it can have by undercutting the NIP.

122. The price effect though triggered the onset of the injury, its ramification as a volume effect in POI is at a low key as other intrinsic factors have over shadowed the volume injury in POI. The domestic industry is still in production and not closed and has requested for injury redressal due to dumping.

123. The Authority has analysed annual reports and other submissions of the Domestic Industry to evaluate causal link so that factors other than dumping are also addressed in view of the issues submitted by various interested parties citing the earlier Judgement of Hon'ble CESTAT.

124. Transaction wise data of DGCI&S provided by the domestic industry has been placed in public file and made available to various interested parties.

125. The NIP has been determined for the entire POI by adopting the consistent methodology of determining NIP on highest capacity utilisation, best achieved norms of consumption etc. over the injury period as stipulated in Annexure III to the AD rules. Domestic Industry's and other interested parties' contention regarding idle time, the Authority holds that it has adopted the consistent practice to evaluate NIP as per Annexure III to the AD rules.

126. The freight cost as requested by the domestic industry for factoring in the NIP has not been considered appropriate as decisions of locating a unit near to raw-material supply or finished goods consumers are strategic decisions taken at the time of inception and injury assessment in an AD investigation warrants apple to apple comparison of NIP with Landed Value, and cannot be altered on a case to case basis, keeping in view the history of locating a unit which may vary entity to entity with raw-material sources and consumers location also getting diversified and changing dynamically over time.

127. As regards altering the landed value through credit cost adjustment, the Authority holds that the adjustment of credit cost has been done for evaluation of dumping margin. Further, adjustment of credit cost in landed value does not seem appropriate as stated in the disclosure statement as well, as other factors like freight, preferential custom duty or even commission paid to agents by exporters may also warrant an adjustment depending on business practices and bilateral arrangements between countries.

128. As regards the submissions that Authority has not dealt all injury parameters, the Authority holds that all relevant injury parameters have been analysed under the injury and causal link examination with a finding on the possible negative impact due to dumping wherever relevant.

129. The Authority notes the submissions of Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys to recommend same rate of anti dumping duty for both M/s PCD and M/s BASF PETRONAS. The Authority holds that the channels of export adopted by M/s PCD and M/s BASF PETRONAS are different. As the evaluation has been undertaken specific to a value chain channel and the transaction between related parties have been considered after confirming that these are at arms length, the need to combine the two producers/ exporters from Malaysia does not seem appropriate. Further, exports by channels other than the related channels of export by cooperative producers/ exporters which have been verified and considered for according individual dumping margin and injury margin assessment in the present investigation, would attract anti dumping duty under the residual/ non- cooperative category.

130. As regards the form and manner of duty, the Authority holds that anti dumping duty has consistently been recommended in the form of fixed duty in US\$ keeping in view the experience of efficacy in the implementation of anti dumping measures. The Authority has therefore recommended anti dumping duty as per lesser duty rule in fixed form in US\$. The Authority noting the submission of the domestic industry to make the duty table comprehensive, has mentioned in the footnote to the domestic industry that customs head is indicative.

Recommendations

131. The Authority notes that the export price of the subject goods exported from the subject countries are below normal value, thus establishing dumping of the same. The Authority also notes that the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from the subject countries. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of antidumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described in the “Duty Table” below. However, wherever the injury margin is negative for any producer/ exporter, it has been so indicated in the analysis in the previous paragraphs on injury analysis.

132. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty equal to the amount mentioned in Col 8 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government, on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

DUTY TABLE

S.N.	*Subheadings/Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	29051300	Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol”	European Union	European Union	Oxea GmbH	Petrochem MiddleEast FZE, Dubai	Nil	MT	US\$

2)	29051300	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	European Union	European Union	Oxea GmbH	ICC Chemicals, USA	Nil	MT	US\$
3)	29051300	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	European Union	European Union	Any combination other than 1) and 2) above.		46.27	MT	US\$
4)	29051300	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	European Union	Any	Any	Any	46.27	MT	US\$
5)	29051300	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	Any	European Union	Any	Any	46.27	MT	US\$
6)	29051300	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	Malaysia	Malaysia	M/s PETRONAS Chemicals Derivatives SdnBhd	M/s PETRONAS Chemicals Marketing SdnBhd	51.42	MT	US\$
7)	29051300	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	Malaysia	Malaysia	BASF PETRONAS	BASF PETRONAS	26.59	MT	US\$
8)	29051300	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	Malaysia	Malaysia	Any combination other than 6) and 7) above.		149.31	MT	US\$
9)	29051300	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	Malaysia	Any	Any	Any	149.31	MT	US\$
10)	29051300	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	Any	Malaysia	Any	Any	149.31	MT	US\$
11)	29051300	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	Singapore	Singapore	Any	Any	35.66	MT	US\$

12)	29051300	Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol”	Singapore	Any	Any	Any	35.66	MT	US\$
13)	29051300	Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol”	Any	Singapore	Any	Any	35.66	MT	US\$
14)	29051300	Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol”	S. Africa	S. Africa	Any	Any	13.24	MT	US\$
15)	29051300	Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol”	S. Africa	Any	Any	Any	13.24	MT	US\$
16)	29051300	Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol”	Any	S. Africa	Any	Any	13.24	MT	US\$
17)	29051300	Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol”	USA	USA	Any	Any	24.16	MT	US\$
18)	29051300	Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol”	USA	Any	Any	Any	24.16	MT	US\$
19)	29051300	Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol”	Any	USA	Any	Any	24.16	MT	US\$

* The customs classification is indicative only and not binding on the scope of this investigation.

133. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

Further Procedure

133. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K. BHALLA, Designated Authority